भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii - xii
अध्याय - I		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1 - 1.3	1
लेखापरीक्षा अधिदेश	1.4 - 1.6	2
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.7 - 1.9	2-3
अंश पूंजी, अनुदान/सहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण से संबंधित बजटीय जावक	1.10 - 1.11	3-4
वित्त लेखों के साथ समाधान	1.12 - 1.13	4
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	1.14 - 1.17	5-6
लेखों के अंतिमीकरण में बकाया	1.18 - 1.22	6-7
लेखों पर टिप्पणियाँ	1.23 - 1.26	7-10
आंतरिक नियंत्रण पर टिप्पणियाँ	1.27	10
लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली	1.28	10-11
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के उपस्थापन की स्थिति	1.29	11
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार	1.30 - 1.31	11-12
अध्याय - II		
सरकारी कंपनी का निष्पादन लेखापरीक्षा		
झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (झा.रा.ख.वि.नि.) का कार्यचालन	2	13
कार्यकारी सारांश	-	13-15
प्रस्तावना	2.1	15-16
संगठानात्मक ढांचा	2.2	16
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	2.3	16-17
लेखापरीक्षा मानदंड	2.4	17
लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं पद्धति	2.5	17
वित्तीय स्थिति	2.6	17-18
तीन वर्षों से अधिक समय से देय राशि का वसूली न होना	2.7	18
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	-	18
कोयला खनन और व्यापारिक गतिविधियाँ	2.8	18-19
जगलदगा कोयला ब्लॉक में खनन प्रारंभ न होना	2.9	19-20
सरकारी कंपनी व्यवस्था के तहत आबंटित आठ कोयला ब्लॉक	2.10	20
आठ कोयला ब्लॉकों में खनन कार्य का प्रारम्भ न होना	2.11	20-21

खनन विनियमों के उल्लंघन के कारण कोयला खान का परिचालन बन्द होना	2.12	22
कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा कोयले का आबंटन न करना	2.13	22-23
खनिज खनन एवं अन्य गतिविधियाँ	2.14	23-25
खनन पट्टे का नवीकरण न होना	2.15	25
चूना पत्थर खान एवं ग्रांइडिंग फैक्टरी	-	25
वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में चूना पत्थर खान का परिचालन न होना	2.16	25-27
अपरिचालित ग्रांइडिंग फैक्टरी पर निष्क्रिय व्यय	2.17	28-29
चूना पत्थर खानों में खान विनियम का उल्लंघन	2.18	29
ग्रेफाइट खान	-	29
वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में ग्रेफाइट खानों का अपरिचालन	2.19	29-30
कायनाइट खान	-	30
वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में कायनाइट खान का अपरिचालन	2.20	30-32
निजी संवेदकों द्वारा चूना पत्थर, ग्रेफाइट एवं कायनाइट के उत्पादन में कमी	2.21	32-33
पत्थर खान	-	33
पत्थर खानों का अपरिचालन	2.22	33-34
ग्रेनाइट खान एवं ग्रेनाइट टाइल्स प्लांट	-	34
ग्रेनाइट खान का अल्प निष्पादन	2.23	34-35
ग्रेनाइट टाइल्स प्लांट का अल्प उपयोग	2.24	35-36
खनिजों के स्टॉक का अनिस्तारीकरण	2.25	36-37
वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करना और खनिजों में कमी	2.26	37-38
नियत लगान का परिहार्य भुगतान	2.27	38
आंतरिक नियत्रंण तंत्र में कमियाँ	2.28	38-39
अनुबद्धित संख्या में निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन नहीं होना	2.28.1	39
आंतरिक लेखापरीक्षा	2.28.2	39-40
निष्कर्ष	-	40
अध्याय - III		
लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन	3	41
सांविधिक निगम		41
झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड		
झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अल्पावधि ऊर्जा क्रय पर दीर्घ कंडिका	3.1	41

प्रस्तावना	3.1.1	41-42
लेखापरीक्षा का उद्देश्य, क्षेत्र एवं पद्धति	3.1.2	42
लेखापरीक्षा निष्कर्ष		42
राज्य में ऊर्जा क्रय की स्थिति	3.1.3	42-43
अल्पावधि के आधार पर ऊर्जा क्रय	-	43
कम दर पर उपलब्ध ऊर्जा की कम निकासी के कारण हानि	3.1.4	43-44
संचरण लाइन की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना व्यापार हेतु निजी ऊर्जा उत्पादक से ऊर्जा क्रय	3.1.5	44-46
पीटीसी से ऊर्जा क्रय के कारण परिहार्य व्यय	3.1.6	46
निष्कर्ष	-	47
पावर फैक्टर अधिभार की उगाही में देरी के कारण हानि	3.2	47-49
प्रत्याभूति राशि के गैर-वसूली के कारण हानि	3.3	49-50
सरकारी कंपनियां		
झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड		
आयकर पर ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.4	50-52
झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड		
सेवा कर का परिहार्य भुगतान	3.5	52-53
तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड		
लिफ्ट की गैर-स्थापना के कारण निष्फल व्यय	3.6	53-55
सामान्य		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही	3.7	55-57

परिशिष्ट

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम के संबंध में 31 मार्च 2014 को प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋण तथा मानवशक्ति को दर्शाती अद्यतन विवरणी	1.7	59-61
1.2	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य अंश पूँजी, ऋण, अनुदान तथा सहाय्य, प्राप्त प्रत्याभूति, बकायों की माफी, अपलिखित ऋण तथा अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण तथा मार्च 2014 की समाप्ति पर प्रत्याभूति प्रतिबद्धता, को दर्शाती विवरणी	1.10	62-63
1.3	अद्यतन वर्ष के लिए तैयार लेखे के अनुसार सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	1.14	64-66

1.4	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के वित्तीय परिणाम को दर्शाती विवरणी	1.14	67
1.5	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकारी परिणाम को दर्शाती विवरणी	1.14	68
1.6	राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया हैं, में किए गए निवेश को दर्शाती विवरणी	1.20	69
2.1	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का संगठनात्मक ढाँचा	2.2	70
2.2	वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान कंपनी के कार्यकारी परिणाम को दर्शाती विवरणी	2.6	71
2.3	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के माइलस्टोन के लक्ष्य के तुलना में उपलब्धि को दर्शाती विवरणी	2.11	72-73
2.4	खनिज खानों के वैधानिक अनापत्तियों की स्थिति को दर्शाती विवरणी	2.14	74
2.5	31 मार्च 2014 को खनिज खानों के संबंध में खनन पट्टे और उनके नवीकरण को दर्शाती विवरणी	2.15	75
3.1	कंडिकायें/निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसका उत्तर अप्राप्त थे, को दर्शाती विवरणी	3.7.1	76
3.2	विभागावार लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) की विवरणी	3.7.3	77
3.3	विभागावार प्रारूप कंडिकाओं की विवरणी जिसके उत्तर अप्राप्त थे	3.7.3	78

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन झारखण्ड के सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम की 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंध रखता है।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानी गयी सरकारी कम्पनियाँ भी सम्मिलित) के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक (चार्टर्ड एकाउंटेंट) द्वारा सत्यापित किये लेखे जो सीएजी के अधिकारियों द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन है और सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर सीएजी अपनी टिप्पणियाँ या पूरक टिप्पणी देते हैं। इसके अलवा, ये कम्पनियाँ सीएजी द्वारा नमुना लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

सरकारी कम्पनी या निगम के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अंतर्गत झारखण्ड के राज्य विधायिका के समक्ष उपस्थापित करने हेतु सीएजी द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2013-14 के दौरान लेखों की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आए, साथ-साथ वे जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए, किंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके; 2013-14 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहाँ आवश्यक समझे गए, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन जिसमें लेखों के साथ-साथ निष्पादन लेखापरीक्षा और लेन-देन लेखापरीक्षा के परिणाम से संबंधित सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन, एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, एक दीर्घ कंडिका एवं पाँच कंडिकाएँ सम्मिलित है।

1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित होती है। कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा सीएजी के द्वारा भी की जाती है। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी), एक सांविधिक निगम, की लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 से अधिशासित होती थी। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को एक होल्डिंग कम्पनी, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) और तीन सहायक कम्पनियों, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) और झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) में पुन: संगठित (जनवरी 2014) कर दिया गया है।

31 मार्च 2014 तक झारखण्ड राज्य के 17 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा.क्षे.उ.) थे। इनमें जनवरी 2014 को जेएसईबी के पुनर्संगठन से बनी चार ऊर्जा कम्पनियाँ सम्मिलित है। कार्यशील सा.क्षे.उ. ने 8,160 कर्मचारियों को नियोजित किया और इनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 3,065.85 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया।

(कंडिकाएं 1.2, 1.4, 1.5, और 1.6)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2014 को, 18 सा.क्षे.उ. (जेएसईबी सहित) में ₹ 6,740.02 करोड़ का निवेश था जो 2008-09 में ₹ 3910.70 करोड़ से 72.35 प्रतिशत बढ़ा था। कुल निवेश का 2.95 प्रतिशत पूंजी एवं 97.05 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण के रूप में था। 2013-14 में कुल निवेश का करीब 98.68 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र में था। 2013-14 में सरकार ने ₹ 1168.79 करोड़ अंशपूंजी, ऋण और अनुदान/सहाय्य के लिए दिये।

(कंडिकाएं 1.7, 1.8, 1.9, और 1.11)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार 18 सा.क्षे.उ. (जेएसईबी सहित) में से, आठ सा.क्षे.उ. ने ₹ 27.92 करोड़ का समेकित लाभ अर्जित किया तथा तीन सा.क्षे.उ. ने ₹ 2757.06 करोड़ की समेकित हानि वहन की। शेष सात सा.क्षे.उ. में से, तीन सा.क्षे.उ.

ने कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया और शेष चार सा.क्षे.उ. का सितम्बर 2014 तक पहला लेखा बकाया नहीं हुआ था। अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड ने वर्ष 2012-13 में तथा तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड ने वर्ष 2001-2002 में क्रमश: ₹ 2667.56 करोड़ एवं ₹ 88.17 करोड़ का भारी हानि वहन किया।

(कंडिका 1.15)

बकाया लेखे

सितम्बर 2014 तक 14 सा.क्षे.उ. के कुल 45 लेखे बकाया थे। बकाया लेखें की अवधि एक से नौ वर्षों के थे। सा.क्षे.उ. को लेखों की तैयारी से संबंधित कार्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के साथ-साथ बकाया लेखों के निष्पादन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(कंडिका 1.18)

लेखों की गुणवत्ता

अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 के दौरान अंतिमीकृत 14 लेखों में से बारह लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दोषपूर्ण प्रमाण पत्र दिए थे। सीएजी द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा यह दर्शाता है की लेखों के रखरखाव की गुणवत्ता में काफी सुधार की जरूरत है। सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन कम्पनियों के आंतरिक नियंत्रण में कुछ कमजोर क्षेत्रों की ओर संकेत करते है।

(कंडिकाएं 1.23 और 1.27)

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के उपस्थापन की स्थिति

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के वर्ष 2001-02 से 2012-13 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ.ले.प्र) अगस्त 2010 से अगस्त 2014 के दौरान झारखण्ड सरकार (झा.स.) को निर्गत किया गया था परन्तु कोई भी पृ.ले.प्र. दिसम्बर 2014 तक राज्य विधान मंडल में उपस्थापित नहीं हुए थे।

(कंडिका 1.29)

2. झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का कार्यचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

परिचय

झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) को बिहार राज्य के बंटवारे के उपरान्त मई 2002 में राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया। कंपनी के मुख्य उद्देश्य राज्य में खनन पट्टा प्राप्त करने के बाद खानों के अन्वेषण, पूर्वेक्षण, विकास, प्रशासन, प्रबन्धन एवं नियंत्रण और खनिजों के प्रसंस्करण या इसके बिना विक्रय है।

(कंडिका 2.1)

वित्तीय स्थिति

कंपनी ने दिसम्बर 2014 तक वर्ष 2009-10 से 2013-14 के वार्षिक लेखे को अंतिमीकृत नहीं की है। कार्यचालन परिणामों के अनुसार, कंपनी ने 2009-10 में ₹ 29.35 करोड़ का लाभ अर्जित की जिसमें 2010-11 से गिरावट हुई और यह सिकनी कोयला खान जोकि कंपनी का एक मात्र परिचालित कोयला खान था, में उत्पादन नहीं होने के कारण घटकर 2013-14 में ₹ 2.15 करोड़ हो गया।

(कंडिका 2.6)

कोयला खनन एवं व्यापारिक गतिविधियां

कोयला मंत्रालय (को.मं.), भारत सरकार (भा.स.) ने 1987 में सिकनी कोयला खान का आबंटन किया और जगलदगा कोयला खान कोल इडिया लिमिटेड से 1996 में हस्तांतरित किया गया था। कोयला मंत्रालय ने पुन: 2006-2008 के दौरान, कंपनी को आठ कोयला ब्लॉक सरकारी कंपनी व्यवस्था (डिस्पेंसेसन) के अंतर्गत आबंटित किया।

(कंडिका 2.8)

कोयला खानों का अपरिचालन

सिकनी कोयला खान अप्रैल 2009 से दिसम्बर 2011 की अवधि तक परिचालन में था तत्पश्चात खान सुरक्षा महानिदेशक (डीजीएमएस) के द्वारा कोयला खान विनियमों के उल्लंघन के कारण कोयला खनन को रोक दिया गया। जगलदगा कोयला खान में कोयले का खनन वन अनापत्ति के अभाव में प्रारंभ नहीं हो पाया।

(कंडिकाएं 2.9 एवं 2.12)

आठ कोयला ब्लॉकों में खनन कार्य प्रारंभ नहीं होना

कंपनी सरकारी कंपनी व्यवस्था के अंतर्गत आंबटित आठ कोयला ब्लॉकों के विकास एवं उत्खनन प्रारंभ करने में विफल रही। भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा 24 सितम्बर 2014 को इन कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द कर दिया गया और कंपनी द्वारा इन कोयला ब्लॉकों पर किये गये ₹ 18.31 करोड़ का सम्पूर्ण खर्च निरर्थक हो गया।

(कंडिका 2.11)

कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कोयले का आबंटन न करना

2009-10 से 2013-14 की अवधि में कोल इडिया लिमिटेड के द्वारा कंपनी को 279252 मेट्रिक टन (एमटी) कोयले का आबंटन संबंधित वर्षों में ईंधन आपूर्ति अनुबंध के संपादन में विलम्ब होने के कारण नहीं किया गया। परिणामस्वरुप, कंपनी उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण नहीं कर सकी इस कारण से ₹ 2.16 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई।

(कंडिका 2.13)

खनिज खनन एवं अन्य गतिविधियां

खानों का अपरिचालन

कंपनी के पास चुना पत्थर, ग्रेफाइट, कायनाइट, पत्थर तथा ग्रेनाइट के नौ पट्टाधारित खानें थे। इनमें से, पाँच खानों के खनन योजनाएँ अनुमोदित थी, वन अनापत्ति मात्र एक

खान के लिए का प्राप्त था और किसी भी खान के लिए पर्यावरण अनापत्ति एवं झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं था।

वैधानिक अनापत्तियाँ के अभाव में चार खानों में खनन परिचालन 2012-13 में बंद हो गयी । अन्य चार खानें 14 वर्षों से अधिक समय से अपरिचालित थी। चेलांगी ग्रेनाइट खान एक मात्र खनिज खान था जो दिसम्बर 2014 तक परिचालन में था।

(कंडिकाएं 2.14 ,2.16, 2.19, 2.20 एवं 2.22)

अपरिचालित ग्रांइडिंग फैक्टरी पर निष्क्रिय व्यय

कंपनी अपने ग्रांइडिंग फैक्टरी को चुना पत्थर चूर्ण के उत्पादन हेतु अपेक्षित मात्रा में चुना पत्थर टुकडों के आपूर्ति सुनिश्चित करने में असफल रही परिणामत: ₹ 40.04 लाख की हानि हुई। कंपनी राजस्व अर्जन हेतु आधारभूत संरचना के उपयोग में भी विफल रही तथा ₹ 87.80 लाख का निष्क्रिय व्यय किया ।

(कंडिका 2.17)

चुना पत्थर, ग्रेफाइट, कायनाइट और ग्रेनाइट के उत्पादन में कमी

2009-14 के दौरान खानों के परिचालन अवधि में विभिन्न खनिजों के उत्पादन में कमी उत्पादन लक्ष्य का 45.90 प्रतिशत से 95.72 प्रतिशत के मध्य रहा। चेलांगी खान से ग्रेनाइट ब्लॉकों के उत्पादन में कमी 95.72 प्रतिशत थी जो तुपुदाना ग्रेनाइट टाइल्स प्लांट के अल्प निष्पादन का कारण था।

(कंडिकाएं 2.21 एवं 2.23)

ग्रेनाइट टाइल्स प्लांट का अल्प उपयोग

प्लांट 2007-2010 के दौरान ग्रेनाइट ब्लॉकों की अनुपलब्धता के कारण अपरिचालित रही। 2011-12 से 2013-14 के वर्षों के दौरान ग्रेनाइट टाइल्स का वार्षिक उत्पादन, क्षमता का मात्र 7.97 प्रतिशत से 30.12 प्रतिशत तक था। इस प्रकार, प्लांट अल्प उपयोग में रही।

(कंडिका 2.24)

वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करना तथा खनिजों में कमी

कंपनी ने मई 2010 से खनिजों के स्टॉक का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया तथा पिछले भौतिक सत्यापन में पाई गई भारी कमी के लिए सुधारात्मक उपाय करने में विफल रही।

(कंडिका 2.26)

नियत लगान का परिहार्य भुगतान

खानों के परिचालन हेतु वैधानिक अनापत्तियों को प्राप्त करने में विफलता के कारण 2009-10 से 2013-14 के दौरान कंपनी द्वारा ₹ 99.83 लाख का परिहार्य नियत लगान भुगतान किया गया।

(कंडिका 2.27)

आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियाँ

कंपनी ने 2009-10 के बाद परियोजनावार लागत-पत्र नहीं बनायी तथा कोई व्यापक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) भी नहीं बनायी। कंपनी का खानों के निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने हेतु कोई सर्तकता तथा अनुश्रवण प्रणाली नहीं हैं। कंपनी का अपना आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था तथा आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल भी नहीं बनाया था।

(कंडिका 2.28)

3. लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन

प्रतिवेदन में शामिल किये गये लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबंधन की कमियाँ, जिनके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई, को मुख्य रूप से दर्शाती है। इसमें "झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अल्पावधि उर्जा पर क्रय" पर दीर्घ कंडिका शामिल है। इंगित की गई अनियमितताएँ मुख्यत: निम्न प्रकार की है:

नियमों, दिशा-निर्देशों, प्रक्रियाओं, संविदाओं के शर्त्तों एवं बंधंजों के अनुपालन न करने के कारण तीन मामलों में ₹ 0.95 करोड़ की हानि ।

(कंडिकाएं 3.3, 3.4 एवं 3.5)

त्रुटिपूर्ण/दोषपूर्ण योजना के कारण तीन मामले में ₹ 2.81 करोड़ का निष्फल व्यय।

(कंडिकाएं 3.1.5, 3.1.6 एवं 3.6)

अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण के कारण चार मामलों में ₹ 287.66 करोड़ की हानि।

(कंडिकाएं 3.1.4, 3.1.5 एवं 3.2)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों का सारांश निम्नप्रकार है:

जेएसईबी ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान दामोदर घाटी निगम से अल्पावधि आधार पर 3467.99 एमयू ऊर्जा क्रय किया और इसी अवधि में जेएसईबी ने 2174.40 एमयू ऊर्जा की कम निकासी की जिसपर निम्नतर दर वसूली गई जिसके फलस्वरुप ₹ 231.24 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.1.4)

जेएसईबी को व्यापार के लिए संचरण लाइन की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना 70.68 एमयू अल्पावधि ऊर्जा क्रय करने के फलस्वरुप ऊर्जा व्यापार पर संचरण प्रभार एवं व्यापार मार्जिन के रुप में ₹ 1.96 करोड़ का परिहार्य व्यय (43.08 एमयू के संचरण शुल्क के लिए लागत ₹ 1.15 करोड़ तथा व्यापारिक मार्जिन के लिए ₹ 0.18 करोड़) एवं तत्काल जरुरत के लिए (27.60 एमयू जिसका मुल्य ₹ 0.63 करोड़) करना पड़ा।

(कंडिकाएं 3.1.5 एवं 3.1.6)

जेएसईबी ने कम दर पर उपलब्ध ऊर्जा पर विचार किये बिना उच्च दर पर एक निजी ऊर्जा उत्पादक से 83.16 एमयू ऊर्जा क्रय किया जिसके फलस्वरुप ₹ 7.42 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.1.5)

अन्य लेन-देन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों का सारांश निम्न प्रकार है:

जेएसईबी द्वारा टैरिफ के अनुसार पावर फैक्टर अधिभार की उगाही में अत्याधिक देरी के कारण एक कैप्टिव पावर प्लांट उपभोक्ता से ₹ 47.16 करोड़ का राजस्व अवसूलनीय रहे।

(कंडिका 3.2)

जेएसईबी के प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहने के कारण उपभोक्ता से ₹ 66.95 लाख की प्रत्याभूति राशि और उस पर ₹ 50.13 लाख के क्षतिपूर्ति प्रभार अवसूलनीय रहे।

(कंडिका 3.3)

झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए अग्रिम आयकर का भुगतान न करने और आयकर विवरणी दायर करने में देरी के कारण आयकर पर ₹ 28.82 लाख ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.4)

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा केंदू पत्ती के विक्रेता से पर्यवेक्षण शुल्क और गोदाम किराया पर लगने वाले सेवा कर की वसूली में विफल रहा जिसके कारण ₹ 15.63 लाख की गैर-वसूली रही।

(कंडिका 3.5)

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा प्रारंभिक कार्य को पूरा करने और कार्य स्थलों को सौंपने में विफल रहने के कारण लिफ्ट की अधिष्ठापन न होने के परिणामस्वरूप ₹ 84.57 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.6)

अध्याय-I

अध्याय - I

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में राज्य की सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के सा.क्षे.उ. की स्थापना लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए की गई है।

1.2 झारखण्ड राज्य में, 31 मार्च 2014 को 17[1] सरकारी कम्पनियाँ कार्यरत थी। कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंजो में सूचीबद्ध नहीं थी। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी), सांविधिक निगम को वर्ष 2013-14 (जनवरी 2014) के दौरान चार कम्पनियों, नामत: होल्डिंग कम्पनी झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) और सहायक कम्पनियाँ झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) और झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) में पुन:संगठित कर दिया गया।

सितम्बर 2014 तक अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार राज्य के सा.क्षे.उ. ने ₹ 3065.85 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। राज्य के सा.क्षे.उ. ने उनके अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार कुल ₹ 2729.14 करोड़ का घाटा वहन किया। 31 मार्च 2014 को इन्होंने कुल 8160 कर्मचारियों को नियोजित किया था।

1.3 राज्य के सा.क्षे.उ. में नौ विभागीय उपक्रम (वि.उ.), जो वाणिज्यिक क्रियाकलापों को कार्यान्वित करते हैं किंतु वे सरकारी विभागों के अंग हैं, तथा एक स्वायत्त संस्थान, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी), जिसका एकमात्र लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक है, शामिल नहीं है।

---

[1] (i) झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जेएसएफडीसी) (ii) झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको) (iii) झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जिडको) (iv) झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जेपीएचसीएल) (v) ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (जीआरडीए) (vi) झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट) (vii) झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) (viii) तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल) (ix) कर्णपूरा ऊर्जा लिमिटेड (केईएल) (x) झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जेटीडीसी) (xi) झारखण्ड राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल) (xii) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (जेएसएफसीएससीएल) (xiii) झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमएफडीसी) (xiv) झारखण्ड उर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) (xv) झारखण्ड उर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल) (xvi) झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) और (xvii) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल)

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कम्पनियों का लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार अधिशासित होता है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसका प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों द्वारा धारित हो। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी सम्मिलित होती है।

1.5 राज्य के सरकारी कम्पनियों के लेखों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा की जाती है।

1.6 सांविधिक निगम (जेएसईबी) का, इसके चार ऊर्जा कम्पनियो में पुन: संगठन (जनवरी 2014) तक की अवधि का लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 के द्वारा अधिशासित होता था तथा सीएजी इसका एक मात्र लेखापरीक्षक था।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.7 31 मार्च 2014 को, 18 सा.क्षे.उ. (जेएसईबी सहित) में ₹ 6740.02 करोड़ का निवेश था जैसा कि **तालिका - 1.1** में वर्णित है।

तालिका - 1.1

(₹ करोड़ में)

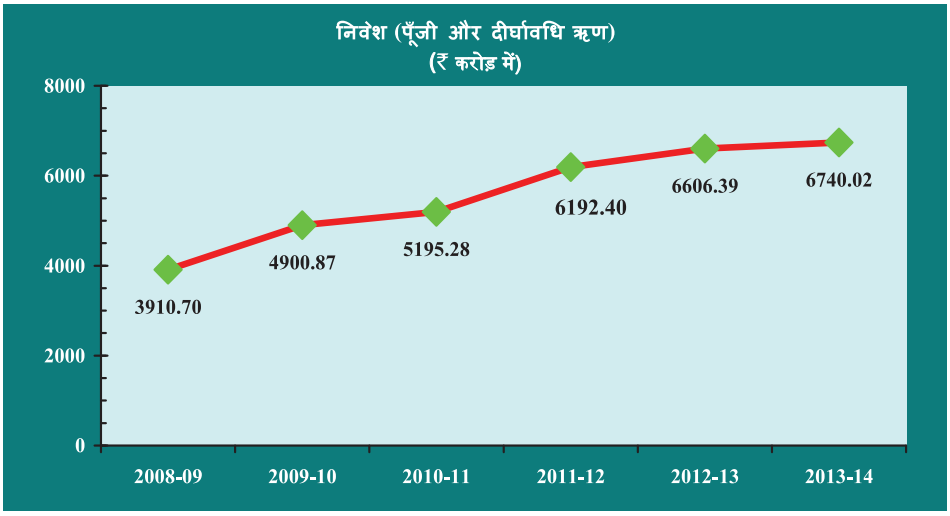
सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुल योग
पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	
199.05	687.60	886.65	-	5853.37	5853.37	6740.02

(स्रोत: सा.क्षे.उ. द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़ें)

राज्य के सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश के सारांशीकृत स्थिति का ब्यौरा ***परिशिष्ट-1.1*** में दिये गये हैं।

1.8 31 मार्च 2014, को सा.क्षे.उ. में कुल निवेश का 2.95 प्रतिशत पूँजी में और 97.05 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों में था। सा.क्षे.उ. में निवेश ₹ 3910.70 करोड़ वर्ष 2008-09 से 72.35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2013-14 में ₹ 6740.02 करोड़ हो गया, जैसा कि **रेखाचित्र - 1.1** में दिखाया गया है:

रेखाचित्र - 1.1



1.9 सा.क्षे.उ. में निवेश का जोर मुख्यतः विद्युत क्षेत्र में था। पिछले छः वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश बढ़ने की प्रवृति को दर्शाता है । यह वर्ष 2008-09 में ₹ 3874.65 करोड़ से 71.65 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 6650.97 करोड़ हो गया जो मुख्यतः सरकार एवं अन्य निकायों के द्वारा जीएसईबी और टीवीएनएल को दिये गये ऋण के कारण हुआ।

अंश पूंजी, अनुदान/सहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण से संबंधित बजटीय जावक

1.10 मार्च 2014 के अंत में राज्य के सा.क्षे.उ. के संबंध में अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का विस्तृत ब्यौरा ***परिशिष्ट-1.2*** में दिये गये हैं।

वर्ष 2013-14 को समाप्त हुये तीन वर्षों का अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का सारांशीकृत ब्यौरा **तालिका - 1.2** में दिया गया है:

तालिका - 1.2

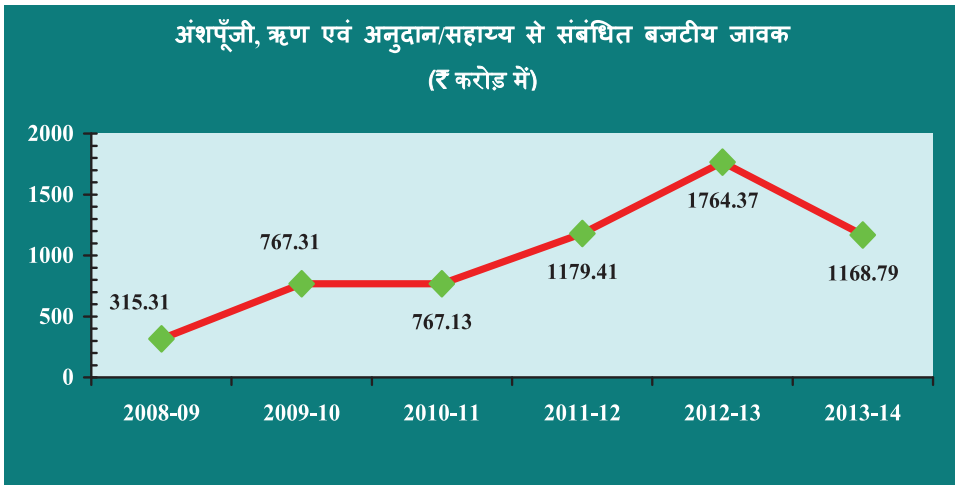
क्र. सं.	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		सा.क्षे.उ. की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सा.क्षे.उ. की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सा.क्षे.उ. की सं.[2]	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बजट से अंश पूँजी जावक	4	20.50	3	15.00	4	20.65
2.	बजट से दिये गये ऋण	2	408.91	2	561.70	1	175.34
3.	अनुदान/सहाय्य प्राप्ति	1	750.00	3	1187.67	2	972.80
4.	**कुल जावक**		**1179.41**		**1764.37**		**1168.79**

(स्रोत: सा.क्षे.उ. द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़े)

[2] छह: सा.क्षे.उ. (जीआरडीए, जिडको, जेटीडीसी, झालको, जेयूवीएनएल और जेएसईबी) का कुल जावक।

1.11 पिछले छः वर्षों में अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का विस्तृत ब्यौरा **रेखाचित्र - 1.2** में दर्शाये गये हैं:

रेखाचित्र - 1.2



बजटीय जावक, वर्ष 2012-13 में ₹ 1764.37 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 1168.79 करोड़ हो गया जो मुख्यत: जीएसईबी को दिये गये ऋण (₹ 175.34 करोड़) तथा अनुदान (₹ 967.09 करोड़) में जावक कमी के कारण था।

वित्त लेखों के साथ समाधान

1.12 राज्य के सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार बकाया अंशपूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति से संबंधित आँकड़े राज्य के वित्त लेखों में अंकित आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो संबंधित सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग द्वारा अंतर का समाधान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2014 तक की स्थिति **तालिका - 1.3** में दी गई है:

तालिका - 1.3

(₹ करोड़ में)

संबंधित बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
अंशपूँजी	56.05	192.70	136.65
ऋण	7296.75	6329.30	967.45

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़े)

1.13 हमने पाया कि नौ[3] सा.क्षे.उ. के आँकड़ों में अंतर था और इन अंतरों का समाधान 2001-02 से लम्बित था। यद्यपि वित्त लेखों में दर्ज और सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि के अंतर को पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था किंतु राज्य सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

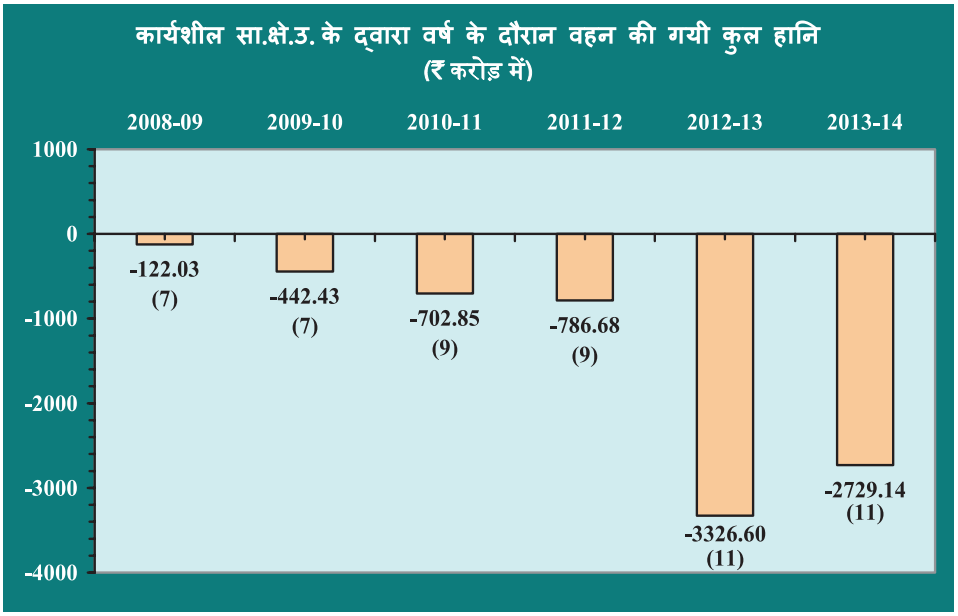
[3] जेएसएमएफडीसी, जेएसएफसीएससीएल, जेयूवीएनएल, टीवीएनएल, जिडको, झारक्राफ्ट, झालको, जीआरडीए और जेएसईबी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.14 सा.क्षे.उ. के वित्तीय परिणामों और सांविधिक निगम के वित्तीय स्थिति तथा कार्यपरिणामों का विस्तृत ब्यौरा क्रमशः ***परिशिष्ट-1.3, 1.4 एवं 1.5*** में दिये गये है।

1.15 2008-09 से 2013-14 के दौरान राज्य के सा.क्षे.उ. के द्वारा उनके अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार वहन किये गये कुल हानि (शुद्ध) ₹ 122.03 करोड़ से बढ़कर 2729.14 करोड़ हो गयी है जैसा की **रेखाचित्र - 1.3** में दिया गया है:

रेखाचित्र - 1.3



(कोष्ठक में आँकड़ें अद्यतन अंकेक्षित लेखों के आधार पर संबंधित वर्ष में कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या दर्शाते हैं)

अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार, 18 सा.क्षे.उ. (जेएसईबी सहित) में से, आठ[4] सा.क्षे.उ. ने ₹ 27.92 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जबकि तीन[5] सा.क्षे.उ. ने ₹ 2757.06 करोड़ की कुल हानि वहन की। बचे हुये सात सा.क्षे.उ. में से, तीन[6] सा.क्षे.उ. ने कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया और चार[7] सा.क्षे.उ. के प्रथम लेखा सितम्बर 2014 तक बकाया नहीं था। जीएसईबी के वर्ष 2012-13 एवं टीवीएनएल के वर्ष 2001-2002 के अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार क्रमशः ₹ 2667.56 करोड़ तथा ₹ 88.17 करोड़ की भारी हानि हुई।

1.16 सीएजी के तीन साल के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सा.क्षे.उ. ने ₹ 904.77 करोड़ की नियंत्रणीय हानियाँ वहन की एवं ₹ 40.80 करोड़ का निरर्थक निवेश किया जो अच्छे प्रबंधन के द्वारा नियंत्रणीय थी जैसा कि **तालिका - 1.4** में दिया गया है।

---

[4] जेएसएफडीसी, जेपीएचसीएल, झारक्राफ्ट, जेएसएमडीसी, जिडको, जीआरडीए, जेएसबीसीएल और जेटीडीसी।

[5] झालको, टीवीएनएल, और जेएसईबी।

[6] जेएसएमएफडीसी, केईएल और जेएसएफसीएससीएल।

[7] जेयूवीएनएल, जेयूयूएनएल, जेयूएसएनएल और जेबीवीएनएल।

तालिका - 1.4

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
शुद्ध हानि	786.68	3326.60	2729.14	6842.42
सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार नियंत्रणीय हानियाँ	487.27	119.19	298.31	904.77
निरर्थक निवेश	10.61	11.03	19.16	40.80

1.17 राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति प्रतिपादित नहीं किया था जिसके अंतर्गत सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रदत्त पूँजी पर न्यूनतम लाभ देने की आवश्यकता है। अपने अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार, आठ[8] सा.क्षे.उ. ने ₹ 27.92 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया लेकिन कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

1.18 लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 और 619-बी के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखाओं का समापन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः महीने के भीतर करना होता है। उसी तरह, सांविधिक निगम (जेएसईबी) के मामले में, लेखों का समापन, लेखापरीक्षा तथा विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार होता है। **तालिका - 1.5** में कार्यरत सा.क्षे.उ. के विवरण तथा उनके लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति (सितम्बर 2014) को दर्शाता है:

तालिका - 1.5

क्र.सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या	11	12	13	14	18[9]
2.	वर्ष के दौरान अंतिमीकृत लेखों की संख्या	14	12	8	20	14
3.	बकाया लेखों की संख्या	46	46	52	45	45[10]
4.	औसत बकाया प्रति सा.क्षे.उ.	4.18	3.83	4.00	3.21	2.50
5.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके लेखों का अंतिमीकरण होना बाकी था	11	12	13	14	14
6.	बकाये की अवधि (वर्ष)	1 to 16	1 to 17	1 to 16	1 to 13	1 to 9

1.19 2009-10 में ग्यारह सा.क्षे.उ. के संदर्भ में बकाये लेखों की संख्या वर्षों के दौरान 46 से घटकर 2013-14 में 14 सा.क्षे.उ. के संदर्भ में 45 हो गयी थी।

---

[8] जेएसएफडीसी, जेपीएचसीएल, झारक्राफ्ट, जेएसएमडीसी, जिडको, जीआरडीए, जेएसबीसीएल और जेटीडीसी।

[9] इसमें जेएसईबी और जनवरी 2014 में जेएसईबी के पुन: संगठन से गठित चार उर्जा कम्पनियाँ यथा जेयूवीएनएल, जेयूयूएनएल, जेयूएसएनएल एवं जेबीवीएनएल सम्मिलित हैं।

[10] जेएसईबी का एक लेखा (1 अप्रैल 2013 से 5 जनवरी 2014 तक की अवधि के लिये) सम्मलित है लेकिन जेयूवीएनएल, जेयूयूएनएल, जेयूएसएनएल एवं जेबीवीएनएल जिनका लेखापरीक्षा बकाया नहीं था, शामिल नहीं है।

1.20 राज्य सरकार ने एक सांविधिक निगम सहित सात सा.क्षे.उ. में, ₹ 1654.27 करोड़ (अंश पूँजी; ₹ 19.75 करोड़, ऋण; ₹ 183.34 करोड़, अनुदान; ₹ 1451.18 करोड़) का निवेश उन वर्षों में किया जिनमें लेखें अंतिमीकृत नहीं हुये हैं जिसका विवरण ***परिशिष्ट-1.6*** में दिया गया है। लेखों और उनके अनुवर्त्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गए निवेश और व्यय का लेखा जोखा उचित तरीके से किया गया था एवं जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था उसकी प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार, सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश, राज्य के विधायिका के संवीक्षा से वंचित रहा। इसके अतिरिक्त, लेखाओं के अंतिमीकरण में विलंब के परिणाम स्वरूप कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ धोखाघड़ी एवं सार्वजनिक कोष के बर्बादी की जोखिम भी हो सकती है।

1.21 प्रशासनिक विभागों को इन इकाईयों के क्रियाकलापों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है और यह सुनिश्चित करना है कि इन सा.क्षे.उ. ने अपने लेखों का अंतिमीकरण एवं उनका अंगीकरण नियत अवधि में कर लिया है। यद्यपि, सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं अधिकारियों का ध्यान लेखों के अंतिमीकरण में बकाया के तरफ आकृष्ट किया गया, पर कोई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप इन सा.क्षे.उ. के निवल परिसंपत्तियों का निर्धारण लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। प्रधान महालेखाकार (पीएजी) द्वारा मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग का ध्यान इन लेखों के अंतिमीकरण में बकाया के तरफ आकृष्ट किया गया था (अगस्त 2014) एवं बकाये लेखों को समयबद्ध तरीके से शीघ्र निष्पादन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था।

1.22 उपर्युक्त बकाये की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को इसका अनुश्रवण एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को पालन करते हुए लेखों का अंतिमीकरण समय पर सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखों पर टिप्पणियाँ

1.23 वर्ष 2013-14 के दौरान सात कंपनियों ने अपने तेरह लेखाओं (बकाये लेखों सहित) को प्रधान महालेखाकार को 30 सितम्बर 2014 तक अग्रसारित किया। इसमें से, तीन कंपनियों[11] के नौ लेखाओं का पूरक लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एक लेखा पर दोष-रहित प्रमाण पत्र एवं बारह लेखों पर दोषपूर्ण प्रमाण पत्र दिये। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और सीएजी के पुरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इगिंत करते है कि लेखाओं के रख रखाव की गुणवत्ता में वृहत रूप से सुधार की जरूरत है। सीएजी के टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विस्तृत विवरण **तालिका - 1.6** में दिये गये हैं।

[11] जेएसएफडीसी-1, जिडको-2, टीवीएनएल-6

तालिका - 1.6

क्र. सं.	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	लाभ में वृद्धि	1	0.23	1	0.01	-	-
2	लाभ में कमी	3	3.52	3	5.29	3	0.63
3	हानि में वृद्धि	-	-	1	0.08	2	33.72
4	हानि में कमी	-	-	1	0.36	-	-
5	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	-	-	3	-	-	-

1.24 कंपनियों के लेखों से संबंधित सीएजी की कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी है:

झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

वर्ष 2011-12 के लेखे

निम्न कारणों से वर्ष का लाभ ₹ 27.16 लाख अधिक आकलित किया गया:

- आयकर देयता में ₹ 4.40 लाख का कम प्रावधान एवं कम भूगतान की गई अग्रिम आयकर राशि पर देय ब्याज ₹ 15.85 लाख का प्रावधान न करना।
- परामर्शी शुल्क ₹ 6.91 लाख का लेखांकन जो वर्ष 2010-11 में ही प्राप्त हो गया था एवं लेखांकित भी किया जा चुका था।

वर्ष 2012-13 के लेखे

निम्न कारणों से वर्ष का लाभ ₹ 8.90 लाख अधिक आकलित किया गया:

- कम भुगतान की गई अग्रिम आयकर राशि पर देय ब्याज ₹ 8.90 लाख का प्रावधान न करना।

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड

वर्ष 2000-01 के लेखे

निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 11.61 करोड़ कम आकलित किया गया:

- राज्य सरकार के ऋण पर दंडात्मक ब्याज ₹ 10.38 करोड़ का प्रावधान न करना।
- कोयले की परिवहन पर अदत्त खर्च ₹ 1.23 करोड़ का प्रावधान न करना।

वर्ष 2001-02 के लेखे

निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 22.11 करोड़ कम आकलित किया गया:

- राज्य सरकार के ऋण पर दंडात्मक ब्याज ₹ 11.90 करोड़ का प्रावधान न करना।
- कोयले की परिवहन पर अदत्त खर्च ₹ 0.89 करोड़ का प्रावधान न करना।
- सीसीएल से संदिग्ध प्राप्य ₹ 7.63 करोड़ का प्रावधान न करना।

• पाँचवें वेतन आयोग द्वारा वेतन संशोधन के कारण बकाया ₹ 1.69 करोड़ का प्रावधान न करना।

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
वर्ष 2012-13 के लेखे

निम्न कारणों से वर्ष का लाभ ₹ 26.93 लाख अधिक आकलित किया गया:

• ₹ 0.95 लाख का मूल्य ह्रास में कम प्रावधान एवं स्थायी संपत्ति का अधिक आकलन।

• सेवाकर देय ₹ 19.76 लाख जो कंपनी द्वारा सेवा प्रदाता से एकत्र नहीं किया गया था, का प्रावधान न करना।

• अग्रिम आयकर के भुगतान में चुक के कारण देय ब्याज ₹ 6.22 लाख का प्रावधान न करना।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) के वार्षिक लेखे पर टिप्पणियों

1.25 जेएसईबी का वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखे, 2013-14 में प्राप्त हुआ जिसपर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत (अगस्त 2014) किया गया था। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन यह इंगित करता है कि खातों के रख रखाव की गुणवत्ता में वृहत सुधार की जरूरत है। जेएसईबी के अंतिम तीन वर्षों के लेखों पर सीएजी की टिप्पणियों का कुल मौद्रिक मूल्य का विस्तृत विवरण **तालिका -1.7** में दिए गये हैं।

तालिका - 1.7

क्र. सं.	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	हानि में कमी	3	56.98	1	5.58	1	1.02
2	हानि में वृद्धि	6	2140.29	1	31.80	1	572.68
	कुल	**6**		**1**		**1**	

1.26 जेएसईबी के लेखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे विवेचित हैं:

वर्ष 2012-13 के लेखे

निम्न कारणों से वर्ष के घाटा ₹ 572.68 कम आकलित किया गया:

• सरकारी उपभोक्ताओं (टीवीएनएल बाँध और खान क्षेत्र विकास प्राधिकरण) पर बकाया उर्जा बिल ₹ 494.82 करोड़ का प्रावधान न करना।

• सेंटल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल) द्वारा आपूर्ति किये गये कोयले की कमी के लिए ₹ 19 करोड़ का गैर-स्वीकार्य दावे का समावेश।

• सीआईएसएफ पर विविध व्यय के लिए दायित्व ₹ 91.71 लाख का प्रावधान न करना।

• सीसीएल एवं जेएसईबी के बीच 2011-12 तक कोयले की बिक्री खाते के संयुक्त सामंजस्य के अनुसार सीसीएल से कोयले की खरीद में देयता ₹ 5.66 करोड़ का कम प्रावधान।

- प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय ₹ 8.16 करोड़ का प्रावधान न करना।
- नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन से 2012-13 तक बिजली खरीद पर देयता ₹ 42.11 करोड़ का प्रावधान न करना।
- कार्यालय एवं आवासीय क्वार्टर में बिजली की खपत के लिए ₹ 36.74 लाख के विद्युत परिव्यय का लेखांकन न करना।
- कंप्यूटरीकृत विपत्त्रीकरण परिव्यय ₹ 1.65 करोड़ का प्रावधान न करना।

निम्न कारणों से वर्ष का घाटा ₹ 1.02 करोड़ अधिक आकलित किया गया:

- वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिये टैरिफ याचिका दाखिला शुल्क ₹ 40.80 लाख का लेखांकन।
- बैंक से ब्याज आय ₹ 60.22 लाख का मान्यता न देना ।

आंतरिक नियंत्रण पर टिप्पणियाँ

1.27 सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउंटेंट) को सीएजी के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ए) के अंतर्गत जारी किये गये दिशा निर्देशों के अंतर्गत उनके द्वारा लेखापरीक्षा की गई कम्पनियों के आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा उन क्षेत्रों की पहचान करना होता है जहाँ सुधार की आवश्यकता थी। वर्ष 2013-14 के दौरान सात[12] कम्पनियों के अंतिमीकृत लेखों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण में संभावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा किये गये मुख्य टिप्पणियों का सारांश सोदाहरण **तालिका - 1.8** में दिये गये है:

तालिका - 1.8

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जहाँ अनुशंसाये की गई थी	परिशिष्ट-1.3 के अनुसार कम्पनियों का क्रम संख्या का संदर्भ
1.	भंडार एवं पूर्जे की न्यूनतम/अधिकतम सीमा का तय न होना	2	क-06, क-08
2.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यापार के आकार के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का अभाव	3	क-03, क-05, क-15
3.	अचल परिसम्पत्तियों की पंजिका, जो पूर्ण विवरण जैसे मात्रात्मक विवरण तथा अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति दर्शाती हैं, का संधारण नहीं होना	4	क-01, क-04, क-05, क-08

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

1.28 2013-14 में लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 115.06 लाख की वसूली हेतु जीएसईबी प्रबंधन को इंगित किये गये थे जिनमें से ₹ 114.68 लाख के मामले जीएसईबी द्वारा

[12] जेएसएफडीसी, जिडको, जेपीएचसीएल, जीआरडीए, झारक्राफ्ट, टीवीएनएल और जेएसवीसीएल

स्वीकार किये गये। सितम्बर 2014 तक जीएसईबी द्वारा ₹ 54.15 लाख रुपये की वसूली की गयी थी।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के उपस्थापन की स्थिति

1.29 तालिका - 1.9 जीएसईबी के लेखों पर सीएजी द्वारा जारी किये गये पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प्र.) को सरकार द्वारा विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दिखलाती है।

तालिका - 1.9

क्र. सं.	सांविधिक निगम	वर्ष जहाँ तक पृ.ले.प्र. विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की गयी	वर्ष जहाँ तक पृ.ले.प्र. विधायिका के समक्ष उपस्थापित नहीं की गयी		
			पृ.ले.प्र. का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	विलम्ब का कारण
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	--	2001-02	20.08.2010	पृ.ले.प्र. को उपस्थापित नहीं करने का कारण सरकार ने नहीं बताया।
			2002-03	07.02.2011	
			2003-04	07.03.2011	
			2004-05	07.06.2011	
			2005-06	09.11.2011	
			2006-07	15.12.2011	
			2007-08	31.01.2012	
			2008-09	30.03.2012	
			2009-10	30.03.2012	
			2010-11	26.04.2012	
			2011-12	22.05.2013	
			2012-13	26.08.2014	

पृ.ले.प्र. को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर विधायिकी नियंत्रण कमजोर होता है एवं बाद में वित्तीय जवाबदेही कम पड़ जाती है। सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधान महालेखाकार द्वारा इस विषय को झारखंड सरकार के मुख्य सचिव तथा विद्युत एवं वित्त विभाग के सचिवों के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2014)। परंतु अभी तक उत्तर अप्राप्त है।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.30 झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के तहत अप्रैल 2003 में विद्युत टैरिफ का युक्तिसंगत बनाने, राज्य में विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण के संबंध में सुझाव देने और लाईसेंस निर्गत करने के उद्देश्य से किया गया है। 2013-14 के दौरान, जेएसईआरसी ने वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं पर एक भी आदेश जारी नहीं किया यद्यपि पाँच अन्य आदेश जारी किये गये। साथ ही, राज्य सरकार ने विदयुत अधिनियम, 2003 के धारा 131 और 133 के आलोक में झारखण्ड राज्य विद्युत सुधार स्थानांतरण योजना 2013 के तहत अधिसुचना संख्या 18 दिनाक 6 जनवरी

2014 के द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को चार नई कम्पनियों में विघटित किया।

1.31 चिन्हित लक्ष्यों के साथ विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम के कार्यांवयन के लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार के मध्य एक संयुक्त वचनबद्धता के रुप में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर अप्रैल 2001 को किया गया। महत्वपूर्ण लक्ष्यों के संबंध में अभी तक हुई उपलब्धि की प्रगति को **तालिका - 1.10** में बतलाया गया है।

तालिका - 1.10

क्र.सं.	लक्ष्य		उपलब्धि
1.	बिक्री हेतु उपलब्ध विद्युत में से तंत्र हानि को कम कर 18 प्रतिशत तक लाना		36.23 प्रतिशत
2.	सभी उपभोक्ताओं का100 प्रतिशत मीटरीकरण	एकल चरण (शहरी)	100.00 प्रतिशत
		एकल चरण (ग्रामीण)	79.02 प्रतिशत
		निम्न विभव (एलटी)	99.86 प्रतिशत
		उच्च विभव (एचटी)	100.00 प्रतिशत

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013-14 में जेएसईबी द्वारा उठायी गयी संचरण एवं वितरण हानि 36.23 प्रतिशत थी जो 18 प्रतिशत के लक्ष्य से बहुत अधिक था। आगे, एमओयू के अनुसार एकल चरण (ग्रामीण) के मामले में 100 प्रतिशत मीटरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था।

अध्याय-।।

अध्याय - II

2. सरकारी कंपनी का निष्पादन लेखापरीक्षा

झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (झा.रा.ख.वि.नि.) का कार्यचालन

कार्यकारी सारांश

परिचय

झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) को बिहार राज्य के बंटवारे के उपरान्त मई 2002 में राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया। कंपनी के मुख्य उद्देश्य राज्य में खनन पट्टा प्राप्त करने के बाद खानों के अन्वेषण, पूर्वेक्षण, विकास, प्रशासन, प्रबन्धन एवं नियंत्रण और खनिजों के प्रसंस्करण या इसके बिना विक्रय है।

(कंडिका 2.1)

वित्तीय स्थिति

कंपनी ने दिसम्बर 2014 तक वर्ष 2009-10 से 2013-14 के वार्षिक लेखे को अंतिमीकृत नहीं की है। कार्यचालन परिणामों के अनुसार, कंपनी 2009-10 में ₹ 29.35 करोड़ का लाभ अर्जित की जिसमें 2010-11 से गिरावट हुई और यह सिकनी कोयला खान जोकि कंपनी का एक मात्र परिचालित कोयला खान था, में उत्पादन नहीं होने के कारण घटकर 2013-14 में ₹ 2.15 करोड़ हो गया।

(कंडिका 2.6)

कोयला खनन एवं व्यापारिक गतिविधियां

कोयला मंत्रालय (को.मं.), भारत सरकार (भा.स.) ने 1987 में सिकनी कोयला खान का आबंटन किया और जगलदगा कोयला खान कोल इंडिया लिमिटेड से 1996 में हस्तांतरित किया गया था। कोयला मंत्रालय ने पुन: 2006-2008 के दौरान, कंपनी को आठ कोयला ब्लॉक सरकारी कंपनी व्यवस्था (डिस्पेंसेसन) के अंतर्गत आबंटित किया।

(कंडिका 2.8)

कोयला खानों का अपरिचालन

सिकनी कोयला खान अप्रैल 2009 से दिसम्बर 2011 की अवधि तक परिचालन में था तत्पश्चात खान सुरक्षा महानिदेशक (डीजीएमएस) के द्वारा कोयला खान विनियमों के उल्लंघन के कारण कोयला खनन को रोक दिया गया। जगलदगा कोयला खान में कोयले का खनन वन अनापत्ति के अभाव में प्रारंभ नहीं हो पाया।

(कंडिकाएं 2.9 एवं 2.12)

आठ कोयला ब्लॉकों में खनन कार्य प्रारंभ नहीं होना।

कंपनी सरकारी कंपनी व्यवस्था के अंतर्गत आंबटित आठ कोयला ब्लॉकों के विकास एवं उत्खनन प्रारंभ करने में विफल रही। भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा 24

सितम्बर 2014 को इन कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द कर दिया गया और कंपनी द्वारा इन कोयला ब्लॉकों पर किये गये ₹ 18.31 करोड़ का सम्पूर्ण खर्च निरर्थक हो गया।

(कंडिका 2.11)

कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कोयले का आबंटन न करना

2009-10 से 2013-14 की अवधि में कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कंपनी को 279252 मेट्रिक टन (एमटी) कोयले का आबंटन संबंधित वर्षों में ईंधन आपूर्ति अनुबंध के संपादन में विलम्ब होने के कारण नहीं किया गया। परिणामस्वरुप, कंपनी उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण नहीं कर सकी इस कारण से ₹ 2.16 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई।

(कंडिका 2.13)

खनिज खनन एवं अन्य गतिविधियां

खानों का अपरिचालन

कंपनी के पास चुना पत्थर, ग्रेफाइट, कायनाइट, पत्थर तथा ग्रेनाइट के नौ पट्टाधारित खानें थे। इनमें से, पाँच खानों के खनन योजनाएँ अनुमोदित थी, वन अनापत्ति मात्र एक खान के लिए का प्राप्त था और किसी भी खान के लिए पर्यावरण अनापत्ति एवं झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं था।

वैधानिक अनापत्तियाँ के अभाव में चार खानों में खनन परिचालन 2012-13 में बंद हो गयी। अन्य चार खानें 14 वर्षों से अधिक समय से अपरिचालित थी। चेलांगी ग्रेनाइट खान एक मात्र खनिज खान था जो दिसम्बर 2014 तक परिचालन में था।

(कंडिका 2.14 ,2.16, 2.19, 2.20 एवं 2.22)

अपरिचालित ग्रांइडिंग फैक्टरी पर निष्क्रिय व्यय

कंपनी अपने ग्रांइडिंग फैक्टरी को चुना पत्थर चूर्ण के उत्पादन हेतु अपेक्षित मात्रा में चुना पत्थर टुकडों के आपूर्ति सुनिश्चित करने में असफल रही परिणामत: ₹ 40.04 लाख की हानि हुई। कंपनी राजस्व अर्जन हेतु आधारभूत संरचना के उपयोग में भी विफल रही तथा ₹ 87.80 लाख का निष्क्रिय व्यय किया ।

(कंडिका 2.17)

चुना पत्थर, ग्रेफाइट, कायनाइट और ग्रेनाइट के उत्पादन में कमी

2009-14 के दौरान खानों के परिचालन अवधि में विभिन्न खनिजों के उत्पादन में कमी उत्पादन लक्ष्य का 45.90 प्रतिशत से 95.72 प्रतिशत के मध्य रहा। चेलांगी खान से ग्रेनाइट ब्लॉकों के उत्पादन में कमी 95.72 प्रतिशत थी जो तुपुदाना ग्रेनाइट टाइल्स प्लांट के अल्प निष्पादन का कारण बना।

(कंडिकाएं 2.21 एवं 2.23)

ग्रेनाइट टाइल्स प्लांट का अल्प उपयोग

प्लांट 2007-2010 के दौरान ग्रेनाइट ब्लॉकों की अनुपलब्धता के कारण अपरिचालित रही। 2011-12 से 2013-14 के वर्षों के दौरान ग्रेनाइट टाइल्स का वार्षिक उत्पादन, क्षमता का मात्र 7.97 प्रतिशत से 30.12 प्रतिशत तक था। इस प्रकार, प्लांट अल्प उपयोग में रही।

(कंडिका 2.24)

वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करना तथा खनिजों में कमी

कंपनी ने मई 2010 से खनिजों के स्टॉक का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया तथा पिछले भौतिक सत्यापन में पाई गई भारी कमी के लिए सुधारात्मक उपाय करने में विफल रही।

(कंडिका 2.26)

नियत लगान का परिहार्य भुगतान

खानों के परिचालन हेतु वैधानिक अनापत्तियों को प्राप्त करने में विफलता के कारण 2009-10 से 2013-14 के दौरान कंपनी द्वारा ₹ 99.83 लाख का परिहार्य नियत लगान भुगतान किया गया।

(कंडिका 2.27)

आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियाँ

कंपनी ने 2009-10 के बाद परियोजनावार लागत-पत्र नहीं बनायी तथा कोई व्यापक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस.) भी नहीं बनायी। कंपनी का खानों के निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने हेतु कोई सर्तकता तथा अनुश्रवण प्रणाली नहीं है। कंपनी का अपना आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था तथा आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल भी नहीं बनाया था ।

(कंडिका 2.28)

2.1 प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) को बिहार राज्य के बंटवारे के उपरान्त मई 2002 में राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया। कंपनी को झारखण्ड राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.ख.वि.नि.) के सभी सम्पत्तियों एवं दायित्वों को उसके निगमन की तिथि पर हस्तांतरित किया गया। कंपनी का मुख्य उद्देश्य राज्य के अन्दर खनन पट्टा प्राप्त करने के बाद खानों के अन्वेषण, पूर्वेक्षण, विकास, प्रशासन, प्रबंधन तथा नियंत्रण और प्रसंस्करण या इसके बिना विक्रय करना है।

बि.रा.ख.वि.नि. द्वारा दो कोयला खानें यथा सिकनी एवं जगलदगा मई 2002 में कंपनी के निगमन के समय हस्तांतरित किया गया था। सिकनी कोयला खान परिचालन में था। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय (को.मं.), भारत सरकार (भा.स.) ने

2006-08 के दौरान आठ[1] कोयला ब्लॉकों का आबंटन सरकारी वितरण मार्ग[2] के तहत किया। इन आठ कोयला ब्लॉकों का आबंटन उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया (सितम्बर 2014) जो कंडिका 2.11 में विवेचित है। कंपनी नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी), 2007 के तहत कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा आबंटित कोयले को राज्य के लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वितरण भी कर रही थी।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के चूना पत्थर, ग्रेफाइट, कायनाइट, पत्थर और ग्रेनाइट के नौ[3] पट्टाधारित खानें थे। इनमें से, चार[4] खानें 2012-13 तक विभिन्न अवधियों में संचालित थीं तथा केवल एक खान (चेलांगी ग्रेनाइट खान) दिसम्बर 2014 तक संचालन में थी। शेष चार[5] खानें 14 वर्षों से अधिक समय से परिचालन में नहीं थी। कंपनी प्लांट का भी परिचालन ग्रेनाइट टाइल्स (तुपुदाना ग्रेनाइट प्लांट) और चूना पत्थर चूर्ण (सुदना ग्रांइडिंग फैक्टरी) के उत्पादन के लिये कर रही थी।

2.2 संगठनात्मक ढाँचा

कंपनी खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार (झा.स.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। प्रबंध निदेशक ही एकमात्र पूर्णकालिक निदेशक और कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सहित सात निदेशक हैं। प्रबंध निदेशक को प्रतिदिन के कार्यों के लिये महाप्रबंधक (वित्त) और महाप्रबंधक (खान) द्वारा सहायता किया जाता है। कंपनी के एक पूर्णकालिक कंपनी सचिव भी है। कंपनी के संगठानात्मक ढाँचा ***परिशिष्ट-2.1*** में दिया गया है।

2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निर्धारित करने के थे कि:

- आबंटित कोयला ब्लॉकों एवं अन्य खनिज खानों के विकास मितव्ययी, कुशलतापूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से किया गया था और वैधानिक अनापत्तियाँ समय पर प्राप्त किये गये थे;
- खनिजों और खनिज उत्पादकों के उत्पादन एवं विक्रय मितव्ययी, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से किये गये थे; और

---

[1] (i) सुगिया, (ii) राउता, (iii) बुढ़ाखाप (iv) लातेहार, (v) पिन्डरा देवीपुर, (vi) पतरातू (vii) रबोध और (viii) जागेश्वर एवं खास जागेश्वर।

[2] सरकारी व्यवस्था मार्ग के अंतर्गत कोयला ब्लॉकों का आवंटन कोयला मंत्रालय द्वारा सिर्फ लोक क्षेत्र उधम को अपने कैप्टिव उपयोग या व्यापारिक खनन के लिए किया जाता है।

[3] (i) सेमरा सलातुआ (चूना पत्थर), (ii) बैंती-बागदा (चूना पत्थर), (iii) सलहन (चूना पत्थर), (iv) ज्योतिपहाड़ी (कायनाइट) (v) सिरबोई (कायनाइट), (vi) महुँगाई-तुलबुला (ग्रेफाइट), (vii) मानासोती (ग्रेफाइट), (viii) चेलांगी (ग्रेनाइट) एवं (ix) चन्दुला-सिमलगोड़ा (पत्थर)।

[4] (i) सेमरा सलातुआ (चूना पत्थर), (ii) बैंती-बागदा (चूना पत्थर), (iii) ज्योतिपहाड़ी (कायनाइट) एवं (iv) महुँगाई-तुलबुला (ग्रेफाइट)।

[5] (i) सलहन (चूना पत्थर), (ii) मानासोती (ग्रेफाइट), (iii) चन्दुला सिमलगोड़ा (पत्थर) एवं (iv) सिरबोई (कायनाइट)।

• कंपनी में प्रभावी और कुशल आंतरिक नियंत्रण तंत्र तथा अनुश्रवण प्रणाली प्रचलित थे।

2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्न स्रोतों से तैयार किया गया:

- परियोजनाओं के वार्षिक उत्पादन योजना और उत्पादन प्रतिवेदन;
- परियोजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन/औचित्य प्रतिवेदन/खनन योजना;
- निविदा दस्तावेजों के शर्तें एवं बंधेजों और संवेदकों के साथ अनुबंध;
- विनियम/भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपबंध/पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986/वन संरक्षण अधिनियम, 1980/खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एमसीडीआर), 1988/ खान और खनिज (नियमन एवं विकास) अधिनियम (एमएमडीआर) 1957, कोयला खान (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1973, कोयला खान विनिमय, 1957; और
- निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठकों के एजेंडा एवं कार्यवृत।

2.5 लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

कंपनी के खानों के विकास, उत्पादन गतिविधियों, खनिजों के विक्रय, खनिजों के लिये पट्टा का अधिग्रहण और वित्तीय निष्पादन के संबंध में 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि में सम्मिलित कंपनी के काम-काज का निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल से जून 2014 के दौरान किया गया। लेखापरीक्षा परीक्षण में कंपनी के निगमित कार्यालय एवं सभी पाँच परियोजना कार्यालयों[6] के दस्तावेजों के संवीक्षा शामिल था।

कंपनी के प्रबंधन के साथ एक प्रविष्टि सम्मेलन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और पद्धति पर चर्चा करने के लिये किया गया (मार्च 2014)। लेखापरीक्षा निष्कर्ष कंपनी एवं सरकार को जारी किये गये थे (अगस्त 2014)। सरकार और कंपनी के उत्तर प्राप्त हुआ है (दिसम्बर 2014)। समापन सम्मेलन का आयोजन (दिसम्बर 2014) सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार और कंपनी के प्रबंध निदेशक के साथ किया गया। सरकार के उत्तर और समापन सम्मेलन में सरकार तथा कंपनी द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को लेखापरीक्षा में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.6 वित्तीय स्थिति

कंपनी अपने दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों को स्वयं के आंतरिक संसाधनों जैसे खनिजों के विक्रय से आय एवं बैंकों में सावधि जमा पर अर्जित ब्याज से करती है। कंपनी दिसम्बर 2014 तक वर्ष 2009-10 से 2013-14 के वार्षिक लेखों को

[6] (i) परियोजना कार्यालय, डाल्टनगंज (नियंत्रक - सेमरा सलातुआ, महुँगाई-तुलबुला, मानासोती खानें एवं सुदना ग्रांइडिंग फैक्टरी) (ii) परियोजना कार्यालय, बैंती-बागदा (नियंत्रक - बैंती-बागदा एवं सलहन खान) (iii) परियोजना कार्यालय, तुपुदाना ग्रेनाइट प्लांट एवं चेलांगी खान (iv) परियोजना कार्यालय, बहरागोड़ा (ज्योतिपहाड़ी एवं सिरबोई खान) (v) परियोजना कार्यालय, चन्दुला सिमलगोड़ा (चन्दुला सिमलगोड़ा खान)।

अंतिमीकृत नहीं की है। 2013-14 को समाप्त पाँच वर्षों का कार्यचालन परिणाम ***परिशिष्ट-2.2*** में वर्णित है।

कंपनी ने 2009-10 में ₹ 29.35 करोड़ का लाभ अर्जित की जिसमें 2010-11 से गिरावट हुई और यह 2013-14 में सिकनी कोयला खान, जो कंपनी का एक मात्र परिचालित कोयला खान था, में कोयले के उत्पादन नहीं होने के कारण घटकर ₹ 2.15 करोड़ हो गया। कंपनी के राजस्व का मुख्य स्रोत कोयला खनन परिचालन, कोयला व्यापार और स्वयं के निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज थे। 2009-10 से 2013-14 के अवधि के दौरान खनिजों के विक्रय से प्राप्त कुल राजस्व ₹ 121.11 करोड़ में से, सिकनी कोयला खान से कोयले के विक्रय से प्राप्त राजस्व ₹ 114.84 करोड़ (94.82 प्रतिशत) था। हालांकि, 2012-13 और 2013-14 में अर्जित आय मुख्यत: कोयला व्यापार एवं स्वयं के निधि के निवेश पर ब्याज से थे ना कि खनन परियोजनाओं के परिचालन से थे।

2.7 तीन वर्षों से अधिक समय से देय राशि का वसूली न होना

31 मार्च 2010 तक विविध देनदारों से वसूली योग्य राशि ₹ 2.04 करोड़ था जिसमें से ₹ 1.75 करोड़ तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया था। वर्ष 2010-11 से 2013-14 के वर्षों के विविध देनदारों की स्थिति लेखों के अंतिमीकरण न होने के कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

लंबे समय से बकाये देनदारों का मुख्य कारण आवधिक अंतरालों में वसूली हेतु अनुश्रवण एवं उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिये कंपनी में एक प्रणाली का अभाव था। यह अकुशल ऋण प्रबंधन का सूचक है जिसका परिणाम लंबे समय से बकाया ऋण की वसूली न होना हो सकता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.8 कोयला खनन और व्यापारिक गतिविधियाँ

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने बि.रा.ख.वि.नि. को 1987 में सिकनी कोयला खान और 1996 में जगलदगा कोयला खान आबंटित किया था जो कंपनी को मई 2002 में इसके निगमन के बाद हस्तांतरित किये गये। कंपनी द्वारा किये गये आवेदन एवं झारखण्ड सरकार के सिफारिश के आधार पर, 2006-08 के दौरान कोयला खान (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1973 के धारा 3(3)(ए)(आइ) के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी को आठ कोयला ब्लॉक आबंटित किये गये। इन कोयला ब्लॉकों का विकास और कोयले का खनन कोयला मंत्रालय द्वारा निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार करना था। यद्यपि, उच्चतम न्यायलय द्वारा सरकारी कंपनी व्यवस्था के अंतर्गत आबंटित सभी ब्लॉकों को रद्द किया गया (सितंबर 2014) जो कंडिका 2.11 में विवेचित है।

कंपनी द्वारा परिचालित एक मात्र कोयला खान, सिकनी कोयला खान अप्रैल 2009 से दिसंबर 2011 की अवधि के दौरान परिचालन में था। खान में कोयला का उत्पादन 9.78 लाख मेट्रिक टन (एमटी) था और इस अवधि के दौरान कोयला की विक्रय द्वारा ₹ 114.84 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया। खान में खनन परिचालन के निलंबन के कारण जनवरी 2012 से अप्रैल 2014 तक कोयले का कोई उत्पादन एवं विक्रय नहीं हुआ था जैसा कि कंडिका 2.12 में विवेचित है। कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आबंटित कोयले को राज्य के लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वितरण भी कर रही थी और 2009-14 के दौरान 12.37 लाख एमटी कोयला वितरित की जिस पर ₹ 12.63 करोड़ का सेवा शुल्क अर्जित किया।

कोयला ब्लॉकों के विकास, कोयले के खनन एवं व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में लेखापरीक्षा में पाये गये कमियों को अगामी कंडिकाओं में विवेचित किये गये हैं।

2.9 जगलदगा कोयला ब्लॉक में खनन प्रारंभ न होना

जगलदगा कोयला खान में खनन वन अनापत्ति के अभाव में इसके आबंटन से 18 वर्षों के बीतने के बाद भी शुरु नहीं हो पाया था।

वर्ष 1996 में जगलदगा कोल ब्लॉक के आबंटन के बाद, बि.रा.ख.वि.नि. ने 94.41 एकड़ क्षेत्र में अन्वेषण का कार्य किया, जिसके लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने खनन योजना (एमपी) अनुमोदित किया (अक्टूबर 1997) और खनन पट्टा[7] प्रदान किया (फरवरी 1998)। कंपनी (झा.रा.ख.वि.नि.) ने वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार को कोयला ब्लॉक के 69.38 एकड़ वन भूमि में वन अनापत्ति[8] प्राप्त करने के लिए वन अपयोजन प्रस्ताव (एफडीपी) 45 माह के निर्धारित समय अवधि के विरूद्ध आबंटन तिथि से 10 वर्षो की अवधि के बाद जमा किया (मार्च 2006)। यद्यपि, वन एव पर्यावरण मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा दिसम्बर 2014 तक वन भूमि का अपयोजन क्षतिपूरक वनरोपन के अभाव एवं कंपनी द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के लिए डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) मानचित्र जमा करने में विफलता के कारण प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार, जगलदगा कोयला खान में खनन वन अनापत्ति के अभाव में कोयला ब्लॉक के आबंटन से 18 वर्षों के पश्चात भी प्रारंभ नहीं हुआ। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मई 2008 में कोयला खान क्षेत्र के लिए पर्यावरण अनापत्ति[9] की मंजूरी दी गयी थी।

---

[7] खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 9(1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में बिना अनुमोदित खनन योजना के खनन कार्य शुरु नहीं करेगा। खनन योजना खान के परिचालन अवधि में स्थल पर किये जाने वाले क्रियाविधियों का वर्णन करता है।

[8] वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के धारा 2 के अनुसार, किसी गैर वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि के अपयोजन के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है एवं क्षतिपूरक वनरोपन शुल्क देय होता है।

[9] पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अनुसार किसी भी नई परियोजना या किसी मौजूदा उधोग या परियोजना के विस्तार या आधुनिकीकरण का कार्य करने के लिए पर्यावरण अनापत्ति के आवेदन पर्यावरण प्रभाव आकलन एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को जमा करना होता है।

सरकार ने उत्तर दिया कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार खान के परिचालन हेतु संयुक्त उद्यम (स.उ.) साझेदार का चयन प्रारंभ किया गया था। हालांकि, प्रक्रियात्मक देरी के कारण संयुक्त उद्यम का गठन नहीं हो सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षतिपूरक वनरोपन भूमि एवं डीजीपीएस मात्रचित्र के अभाव में वन अनापत्ति प्राप्त करने में कंपनी की विफलता के कारण खनन प्रारंभ नही हो सका।

2.10 सरकारी कंपनी व्यवस्था के तहत आबंटित आठ कोयला ब्लॉक

2006 से 2008 के दौरान सरकारी कंपनी व्यवस्था के अंतर्गत आबंटित आठ कोयला ब्लॉकों के लिए, पूर्वेक्षण/विस्तृत अन्वेषण और खनन कंपनी या कोयला खनन करने के लिए उपयुक्त कंपनी के सहभागिता से एक अलग सरकारी कंपनी द्वारा किया जाना था।

आबंटन की शर्तो एवं बंधेजों के अनुसार अन्वेषित कोयला ब्लॉकों के लिए कंपनी को आबंटन के डेढ़ माह के अन्दर सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इन्सटीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआइएल) या जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया (जीएसआई) से जियोलाजिकल रिपोर्ट[10] (जीआर) क्रय करना था या अन्नवेषित ब्लॉकों के लिए जीआर, पूर्वेक्षण लाइसेंस मिलने की तिथि से दो वर्षों के अन्दर तैयार करना था।

कंपनी को जीआर की प्राप्ति के छ: महीनों के अन्दर खनन योजना (एमपी) जमा कर इसे कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदित कराना, जीआर के प्राप्ति की तिथि से 18 महीनों के अन्दर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से वन अनापत्ति एव पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करना था। कोयला ब्लॉकों से खनन कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार कोयला ब्लॉकों के जीआर की प्राप्ति की तिथि से 36 से 54 महीनों के अन्दर प्रारंभ करना था। माइलस्टोन की उपलब्धि न होने पर कोयला ब्लॉकों का आबंटन रदद् हो जाना दायी था।

2.11 आठ कोयला ब्लॉकों में खनन कार्य का प्रारंभ न होना

सरकारी कंपनी व्यवस्था के अंतर्गत आबंटित आठ कोयला ब्लॉकों के विकास में प्रगति माइलस्टोन के अनुरूप जीआर बनाने, खनन योजना को बनाने एवं अनुमोदन कराने तथा वन एवं पर्यावरण की अनापत्ति प्राप्ति के संबंध में संतोषप्रद नहीं था जैसा कि ***परिशिष्ट-2.3*** में विस्तृत है। कंपनी ने इन खानों का विकास संयुक्त उद्यम मार्ग द्वारा कराने का निर्णय लिया। यद्यपि, सितम्बर 2014 तक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने हेतु नियुक्त सलाहकार पर ₹ 40 लाख खर्च करने के बावजूद संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन नहीं हुआ था।

---

[10] जियोलोजिकल रिपोर्ट रिजर्व क्षेत्र का विस्तृत अन्वेषण करने के बाद बनाया गया संक्षिप्त, सूचक एवं अच्छी प्रलेखित रिपोर्ट है जो खनन प्रयोजन के लिए क्षेत्रिय आँकड़े की प्रस्तुति, विश्लेषण एवं संक्षेप करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

कंपनी के कोयला ब्लॉकों के विकास तथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों की प्राप्ति में विफलता के कारण कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने चार[11] कोयला ब्लॉकों का आबंटन, अन्तर मंत्रालय समुह[12] (आईएमजी) की अनुशंसा पर रदद् कर दिया (जनवरी 2013)। इसके साथ ही कोयला मंत्रालय ने दो रदद् कोयला ब्लॉकों के विरूद्ध जमा की गयी ₹ 18.82 करोड़[13] की बैंक गारंटी (बीजी) को निर्धारित माइलस्टोन को प्राप्त न करने के कारण जब्त करने का निर्णय लिया। यद्यपि, कंपनी ने इन कोयला ब्लॉकों की प्रत्यावर्तन हेतु उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में एक रिट याचिका दायर की (अप्रैल 2013), जो लंबित था (सितम्बर 2014)।

कम्पनी निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार आठ कोयला ब्लॉकों के विकास एवं खनन प्रारंभ करने में विफल रही। इन ब्लॉकों पर किया गया ₹ 18.31 करोड़ का खर्च उच्चतम न्यायालय द्वारा इनके आबंटन को रद्द करने पर निरर्थक हुआ।

इसी बीच, भारत के उच्चतम न्यायालय ने 24 सितम्बर 2014 के अपने एक फैसले में भारत सरकार के स्क्रीनिंग कमिटी के द्वारा एवं सरकारी कंपनी व्यवस्था मार्ग के तहत आबंटित किए गए कोयला ब्लॉकों को मनमाना एवं गैरकानूनी माना। अत: सरकारी कंपनी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी को आबंटित सभी आठ[14] कोयला ब्लॉकों को रदद् कर दिया। यद्यपि, कंपनी ने पहले ही इन कोयला ब्लॉकों के विकास एवं खनन हेतु सलाहकार सेवा (₹ 0.40 करोड़), विस्तृत जीआर (₹ 0.84 करोड़), जियोलोजिकल रिपोर्ट का क्रय (₹ 16.33 करोड़), बैंक गारण्टी कमीशन (₹ 0.74 करोड़) इत्यादि पर ₹ 18.31 करोड़ खर्च किया था।

इस प्रकार, कंपनी निर्धारित माइलस्टोन में नियत तिथि के पश्चात् छ: माह से 59 माह के बीत जाने के बावजूद कोयला ब्लॉकों के विकास एवं इन ब्लॉकों में खनन प्रारंभ करने में विफल रही। यदि निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार कोयला ब्लॉकों से उत्पादन प्रारंभ किया गया होता तो कोयला खानों के संचालन से अर्जित राजस्व द्वारा इन खानों में किये गए लागत की वसूली की जा सकती थी। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा इन कोयला ब्लॉकों को रद्द करने पर कंपनी द्वारा इन कोयला ब्लॉकों पर किये गए ₹ 18.31 करोड़ का सम्पूर्ण खर्च निरर्थक हो गया।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकार ने कहा कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार संयुक्त उद्यम साझेदार के चयन हेतु पहल की गई थी। हालांकि, प्रक्रियात्मक विलम्ब एव तत्पश्चात सीबीआई जाँच के कारण संयुक्त उद्यम का गठन नहीं हो पाया।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि कंपनी द्वारा खानों का विकास करने में अत्याधिक विलम्ब की गयी थी। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि प्रगति में कमी के कारण कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने चार कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द किया था।

---

[11] पिण्डरा देवीपुर, लातेहार, रबोध और पतरातू।

[12] उर्जा मंत्रालय, स्टील मंत्रालय, वाणिज्य एवं उधोग मंत्रालय, औधोगिक नियोजन एवं प्रवर्धन विभाग (आईपीपी), कानुन एवं न्याय मंत्रालय, कानूनी मामलों के विभाग एवं आर्थिक मामलों के विभाग के सदस्य शामिल हैं।

[13] बैंक गारन्टी की राशि का 50 प्रतिशत (₹ 31.00 करोड़ रबोध एवं ₹ 6.64 करोड़ पतरातू के लिए)।

[14] (i) सुगिया, (ii) राउता, (iii) बुढ़ाखाप, (iv) लातेहार, (v) पिन्डरा देवीपुर, (vi) पतरातू, (vii) रबोध और (viii) जागेश्वर एवं खास जागेश्वर।

2.12 खनन विनियमों के उल्लंघन के कारण कोयला खान का परिचालन बन्द होना

कोयला खान नियमावली, 1957 के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोयला खान के बेंचों की ढाल को 45 डिग्री से अधिक नहीं रखना था या किनारों को ऊँचाई के साथ बेन्च[15] करके रखना था जो तीन मीटर से अधिक न हो और चौड़ाई, ऊँचाई से कम न हो। संवेदकों के साथ सिकनी कोयला खान के लिए किए गए अनुबंध के शर्तो एवं बंधेजों में यह अनुबद्ध था कि एजेंसी को कोयला खान नियमावली, 1957 के अनुसार बेंचों को बनाये रखना होगा।

सिकनी खान में खनन गतिविधियाँ निर्धारित खनन मानदंडों के अनुपालन न होने के कारण 28 माह तक बन्द रहा।

यद्यपि, संवेदक उपयुक्त बेन्चिंग के बगैर ही खनन-कार्य कर रहा था, जैसे कि खदान बेंचों के दक्षिण-पश्चिम भाग की ऊँचाई स्वीकार्य सीमा के तीन मीटर के विरूद्ध 25 मीटर था और कोयला का उत्खनन दीवार के तल से किया जा रहा था। खनन विनियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण खान-सुरक्षा महानिदेशक (डीजीएमएस) ने खानों में व्यक्तियों की नियुक्ति को निषेध किया (अक्टूबर 2011) तथा कोयले का खनन बंद हो गया था (दिसम्बर 2011)। कंपनी के अनुरोध पर (मार्च 2014), मार्च 2014 में 10 मीटर उँचा बेंच बनाने और बेंच के किनारों को 70 डिग्री तक ढाल रखने की अनुमति प्रदान की गई और संवेदक द्वारा त्रुटियों को दूर करने के बाद खनन कार्य प्रारंभ किया गया (मई 2014)।

इस प्रकार, निर्धारित खनन मानदंडों का अनुपालन नहीं करने के कारण 28 महीनों तक खनन गतिविधियाँ निलंबित रही।

प्रबन्धन ने कहा कि वैधानिक/तकनीकी मानव शक्ति के कमी के कारण अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

तथ्य यथावत है कि विनियम के प्रावधानों के अनुपालन नहीं होने के कारण खनन परिचालन निलंबित था।

2.13 कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा कोयले का आबंटन न करना

कोयला मंत्रालय के नए कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी), 2007 के अनुसार राज्य सरकार को राज्य में वांछनीय उपभोक्ताओं[16] को कोयला वितरण करने हेतु राज्य के लिए एक नोडल एजेंसी नामित करना था। अधिसूचित एजेंसी को कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा मनोनीत कोयला कंपनी के साथ ईन्धन आपूर्ति अनुबन्ध (एफएसए) करना था। ईन्धन आपूर्ति अनुबन्ध राज्य सरकार द्वारा एजेन्सी की अधिसूचना रद्द करने या कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा यह दायित्व किसी अन्य कोयला कंपनी को देने तक प्रभावी होता। नोडल एजेंसी को कोल इण्डिया लिमिटेड के आधार मूल्य पर पाँच प्रतिशत सेवा-शुल्क वसूल करना था। तदनुसार, राज्य सरकार

[15] खनिज एवं ओभरवर्डन को क्रमिक परतों से निकाला जाता है, जिसमें से प्रत्येक एक बेंच होता है। जिसमें से कई एक ओपेंन पिट माईन या एक के अलग-अलग हिस्सों में और भिन्न उत्थानों पर साथ-साथ संचालन हो सकते हैं।

[16] लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ता जिनका वार्षिक आवश्यकता 4200 एमटी तक है एवं जिनका कोयला क्रय के लिये कोई पहुँच या कोल कम्पनियों के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबंध नहीं हैं।

ने झा.रा.ख.वि.नि को कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा आबंटित कोयले को झारखण्ड में उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु नोडल एजेंसी अधिसूचित किया।

वार्षिक ईंधन आपुर्ति अनुबंधों के हस्ताक्षर में विलम्ब के कारण लघु और मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बीच वितरण हेतु कोल एंडिया लिमिटेड द्वारा 279252 एमटी कोयला कम आबंटित किया गया।

हमने अवलोकित किया कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष नोडल एजेंसी का नामांकन कर रही थी जबकि नई कोयला वितरण नीति के तहत नामांकन प्रत्येक वर्ष करने की आवश्यकता नहीं थी। इससे प्रत्येक वर्ष ईन्धन आपूर्ति अनुबन्ध के निष्पादन में देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप कोयला आबंटन में एक से तीन महीने तक की देरी हुई। वैध ईन्धन आपूर्ति अनुबन्ध के अभाव में, कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा मासिक 37250 एमटी कोयला का आबंटन मई 2009, अप्रैल 2010 से जून 2010, अप्रैल 2011 एवं अप्रैल 2012 के माह में नहीं किया गया तथा कम मात्रा का आबंटन मई 2011 (32930 एमटी) एवं अप्रैल 2013 (22822 एमटी) में किया। परिणामत: कंपनी उपभोक्ताओं को 279252 एमटी कोयले का वितरण नहीं कर सकी तत्द्वारा ₹ 2.16 करोड़ के सेवा शुल्क से वंचित हुई।

सरकार ने कहा कि कोल इण्डिया लिमिटेड की नीति के अनुरूप वार्षिक आधार पर ईन्धन आपूर्ति अनुबन्ध किया जा रहा था। इसके अलावा, प्रबन्धन ने कहा कि किसी अन्य नोडल एजेंसी के नामांकन तक झा.रा.ख.वि.नि. को नोडल एजेंसी के रूप में जारी रखने की अनुमति के मामलों को कोल इण्डिया लिमिटेड एवं राज्य सरकार अधिकारियों के समक्ष रखा जा रहा है।

तथ्य यथावत है कि नई कोयला वितरण नीति के नियमों का अनुपालन नहीं होने के कारण तथा वैध ईन्धन आपूर्ति अनुबन्ध के अभाव में, कोल इण्डिया लिमिटेड ने कोयला आबंटित नहीं किया। परिणामत:, कंपनी उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण नहीं कर सकी और उसपर सेवा शुल्क पाने से वंचित रही।

2.14 खनिज खनन एवं अन्य गतिविधियाँ

कंपनी के पास चूना पत्थर, ग्रेफाइट, कायनाइट, पत्थर एवं ग्रेनाइट के नौ पट्टाधारित खानें थी। कंपनी निजी संवेदकों के द्वारा साथ ही विभागीय संचालन द्वारा चार[17] खानों में चूना पत्थर, कायनाइट और ग्रेफाइट का रेजिंग एवं विक्रय कर रही थी। 2012-13 के दौरान पर्यावरण अनापत्तियों के अभाव में इन खानों में खनन कार्य रोक दिया गया। कंपनी चेलांगी ग्रेनाइट खान से भी विभागीय स्तर पर ग्रेनाइट उत्खनन कर रही थी। शेष चार[18] खानें वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में परिचालन में नहीं थे। कंपनी के इन खानों के वैधानिक अनापत्तियों की स्थिति ***परिशिष्ट - 2.4*** में दिया गया है।

[17] (i) सेमरा सलातुआ (चूना पत्थर), (ii) बेंती-बागदा (चूना पत्थर), (iii) ज्योतिपहाड़ी (कायनाइट) एवं (iv) महुँगाई-तुलबुला (ग्रेफाइट)।

[18] (i) सलहन (चूना पत्थर), (ii) सिरबोई (कायनाइट), (iii) मानासोती (ग्रेफाइट) एवं (iv) चन्दुला सिमलगोडा (पत्थर)।

कंपनी अपने खानों से उत्पादित ग्रेनाइट ब्लॉक का उपयोग कर ग्रेनाइट टाइल्स को उत्पादन हेतु तुपुदाना ग्रेनाइट प्लान्ट एवं चूना पत्थर टुकड़े का उपयोग कर चूना पत्थर चूर्ण उत्पादन के लिए सुदना ग्रांइडिंग फैक्टरी का भी परिचालन कर रही थी।

2009-10 से 2013-14 के दौरान कंपनी का खान-वार उत्पादन एवं विक्रय निष्पादन **तालिका-2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1

खानों के नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	बिक्रीत एवं उत्पादित मात्रा (एमटी)	मूल्य (₹ लाख में)	बिक्रीत एवं उत्पादित मात्रा (एमटी)	मूल्य (₹ लाख में)	बिक्रीत एवं उत्पादित मात्रा (एमटी)	मूल्य (₹ लाख में)	बिक्रीत एवं उत्पादित मात्रा (एमटी)	मूल्य (₹ लाख में)	बिक्रीत एवं उत्पादित मात्रा (एमटी)	मूल्य (₹ लाख में)
सेमरा सलातुआ चूना पत्थर खान	37310	115.41	25174	79.30	10805	44.18	4048	16.82	-	-
बेंती-बागदा चूना पत्थर खान	-	-	2818	9.51	39883	135.09	8378	28.41	-	-
महुँगाई-तुलबुला ग्रेफाइट खान	-	-	-	-	-	-	1518	9.81	-	-
ज्योतिपहाड़ी कायनाइट खान	4420	55.55	3547	47.50	4012	54.77	1015	13.90	-	-
चेलांगी ग्रेनाइट खान (उत्पादन ब्लॉकों की संख्या में)	-	-	-	-	133*	-	203*	-	359*	-

(स्रोत - कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़ें)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि इस अवधि में 128416 एमटी चूना पत्थर, 12994[19] एमटी कायनाइट, 1518 एमटी ग्रेफाइट एवं 695 ग्रेनाइट ब्लॉकों का उत्पादन हुआ। कंपनी ने इन खनिजों की बिक्री से ₹ 6.10 करोड़ की उगाही की। इसके अलावा, वर्ष 2013-14 में चेलांगी ग्रेनाइट खान में उत्पादित 359 ग्रेनाइट ब्लॉकों के अतिरिक्त खनिजों का कोई उत्पादन एवं विक्रय नहीं था।

* चेलांगी ग्रेनाइट खान से उत्खनित ग्रेनाइट ब्लॉक ग्रेनाइट टाइल्स के उत्पादन के लिए तुपुदाना ग्रेनाइट प्लांट को स्थानांतरित किया गया था।

[19] अप्रैल 2009 से अप्रैल 2010 के दौरान ज्योतिपहाड़ी खान से विभागीय उत्खनित 4833 एमटी कायनाइट शामिल है।

कंपनी के खनिज खानों एवं प्लांट के संचालन में पाये गये कमियों की चर्चा आगामी कंडिकाओं में किये गये हैं।

2.15 खनन पट्टे का नवीकरण न होना

खनिज समुदान नियमावली (एमसीआर), 1960 के नियम 24ए के अनुसार विद्यमान पट्टे की समाप्ति के कम से कम बारह माह पूर्व ही राज्य सरकार को खनन पट्टा के नवीकरण के लिए आवेदन करना था। वर्ष 2004 तक आठ[20] खानों का पट्टा अवधि कालतिरोहित हुई। पट्टों के नवीकरण एवं खानों के परिचालन हेतु भारत सरकार से इनके खनन योजना वन एवं पर्यावरण अनापत्ति का अनुमोदन तथा संचालन हेतु झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड (जीएसपीसीबी) की सहमति प्राप्त करने थे। विभिन्न खानों के पट्टे की स्थिति ***परिशिष्ट - 2.5*** में उद्धरित है।

हमने पाया कि कंपनी ने 1995 से 2003 के दौरान सक्षम पदाधिकारी को आठ[21] पट्टों के नवीकरण हेतु आवेदन की। यद्यपि, एकमात्र चन्दुला-सिमलगोड़ा खान के लिए नवीकरण प्रदान किया गया है।

सरकार ने उत्तर दिया कि प्रारंभ में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दवारा पर्यावरण अनापत्ति पर जोर नहीं दिया जाता था। तदोपरांत, पर्यावरण अनापत्ति को खनन पट्टे के नवीकरण/अनुमोदन के लिए पूर्वापेक्षित कर दिया गया। कंपनी ने सभी पट्टों के नवीकरण के लिए आवेदन समय पर की थी।

तथापि, तथ्य यथावत है कि कंपनी वैधानिक अनापत्तियों की प्राप्ति में विफल रही। फलस्वरूप पट्टों का नवीकरण नहीं किया जा सका और आवेदन के 11 से 19 वर्षों के बीत जाने के बाद भी खानें अपरिचालित थीं।

चूना पत्थर खान एवं ग्रांइडिंग फैक्टरी

2.16 वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में चूना पत्थर खान का परिचालन न होना

चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुर मात्रा वाला तलछटी चट्टान होता है जिसका उपयोग टुकड़ों के रुप में स्टील प्लांट में होता है एवं चूर्ण का उपयोग सीमेंट उत्पादन में होता है। कंपनी के चूना पत्थर के तीन पट्टे सेमरा सलातुआ, बेंती-बागदा एवं सलहन में हैं। लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

• सेमरा-सलातुआ खान के 2578.28 एकड़ क्षेत्र के पट्टे का नवीकरण हेतु आवेदन बि.रा.ख.वि.नि. द्वारा प्रस्तुत किया गया (अप्रैल 1995) और वन अपयोजन प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित था (जून 1998)। कंपनी

---

[20] (i) सेमरा सलातुआ (चूना पत्थर), (ii) बेंती-बागदा (चूना पत्थर), (iii) सलहन (चूना पत्थर), (iv) ज्योतिपहाड़ी (कायनाइट), (v) सिरबोई (कायनाइट), (vi) महुँगाई-तुलबुला (ग्रेफाइट) एवं (vii) मानासोती (ग्रेफाइट) के सम्बन्ध में 20 वर्षों के लिए पट्टे एवं (viii) चन्दुला सिमलगोड़ा पत्थर खान के संबंध में 10 वर्षों के लिये।

[21] जनवरी 2011 में चेलांगी ग्रेनाइट खान को प्रदत्त नये पट्टे को छोड़कर।

(झा.रा.ख.वि.नि.) ने खनन योजना पट्टा नवीकरण के आवेदन से 19 वर्षों के व्यापक अवधि के बीत जाने के बाद भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) को प्रस्तुत किया (जून 2014) चूंकि यह अपने निरूत्साह प्रवृति के कारण खनन योजना तैयार करने में असफल रही। जिसका अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण के अध्ययन हेतु तीन वर्षों के लिए टर्म्स ऑफ रिफरेन्स[22] (टीओआर) जारी किया (फरवरी 2009) जो खनन स्कीम[23] को प्रस्तुत नहीं करने के कारण समाप्त हो गया था (फरवरी 2012)।

सेमरा सलातुआ खान जून 2012 से पर्यावरण अनापत्ति के अभाव में अपरिचालित रहा।।

कंपनी ने आधारभूत आँकड़ा को बनाने और पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) तथा पर्यावरण प्रबंधंन योजना (ईएमपी) को तैयार करने हेतु सलाहकार नियुक्त की (जनवरी 2013), यधपि, पर्यावरणीय अध्ययन हेतु टीओआर के लिए नया आवेदन प्रस्तुत नहीं किया (दिसम्बर 2014) और पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त नहीं किया जा सका। कंपनी ने झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से खनन संचालन हेतु सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन भी नहीं की है।

हमने पाया कि कंपनी अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनापत्ति के बिना ही खनन कार्य कर रही थी। परिणामत: जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा पर्यावरण अनापत्ति के अनुपलब्धता के कारण उत्पादन को निलंबित किया गया (जून 2012)।

- बेंती-बागदा खान के 334.87 एकड़ क्षेत्र पट्टा के नवीकरण का आवेदन बि.रा.ख.वि.नि. द्वारा प्रस्तुत किया गया (मई 1995)। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा अगस्त 2002 में बेंती-बागदा खान का खनन योजना अनुमोदित किया गया था। वनभूमि के कुल 69.87 एकड़ में से, 22.41 एकड़ क्षेत्र का वन अपयोजन प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जुलाई 2005 में अनुमोदित किया गया था। तदोपरांत, कंपनी ने वन भूमि के शेष 47.46 एकड़ के लिए वन अपयोजन प्रस्ताव जमा किया (जुलाई 2013)। तथापि, हमने अवलोकित किया कि कंपनी को संभावित खनिजयुक्त क्षेत्र का सीमांकन कर वन अपयोजन प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत और अनुपयोगी भूमि को प्रत्यार्पित करना था और जो अब तक किया जाना है (दिसम्बर 2014)।

बेंती बागदा खान जुलाई 2012 से पर्यावरण अनापत्ति के अभाव में जिला खनन अधिकारियों द्वारा खान के निलंबन के कारण परिचालन में नहीं रहा।

पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने हेतु एक सलाहकार को नियुक्त किया गया था (जनवरी 2007) जिसने पर्यावरण प्रभाव आकलन एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना को तैयार किया तथा पर्यावरण अनापत्ति के लिए आवेदन जुलाई 2007 में पट्टा नवीकरण के आवेदन के पश्चात् 12 वर्ष बीतने के बाद प्रस्तुत किया गया था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन के अध्ययन हेतु टीओआर जारी

[22] टीओआर पर्यावरण प्रभाव आकलन का प्रतिवेदन और पर्यावरण प्रबन्ध योजना बनाने के लिए सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय मामलों को संबोधित करने के लिए निर्धारित किया जाता है।

[23] खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के तहत, पट्टेदार को खनन योजना की समीक्षा करनी होती है और खनन योजना प्रस्तुत करने के हर पांच वर्षों के लिए खनन स्कीम (एमएस) के साथ एक प्रगामी खान समापन योजना (पीएमसीपी) प्रस्तुत करना होता है। इसमें अगले पाँच वर्षों में स्थलों पर की जानें वाली गतिविधियाँ शामिल होती है।

किया (मई 2008)। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा माँगें जाने पर, कंपनी ने खनन स्कीम सह प्रगामी खान समापन योजना (पीएमसीपी)[24] मार्च 2013 में प्रस्तुत की। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने टीओआर की वैधता समाप्त हो जाने (मई 2012) के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया (जुन 2013)। कंपनी ने पुन: टीओआर के लिए आवेदन की (जुलाई 2013) जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण अध्ययन हेतु जारी किया गया (दिसम्बर 2013), यद्यपि, कंपनी द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन/प्रर्यावरण प्रबंधन योजना अभी तक तैयार किया जाना था।

परिणामत:, खानों का उत्पादन निलंबित किया गया (जुलाई 2012) चूँकि जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा पर्यावरण अनापत्ति के अभाव के कारण खनन चालान जारी नहीं किया गया। इसके अलावा, कंपनी ने झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से परिचालन हेतु सहमति के लिए आवेदन किया था (मई 2014) और वह लंबित था (दिसम्बर 2014)।

सलहन खान वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में 1997 से अपरिचालित रहा।

- सलहन खान के 257.03 एकड़ क्षेत्र के पट्टा के नवीकरण का आवेदन बि.रा.ख.वि.नि. द्वारा प्रस्तुत किया गया था (मई 1995)। हमने देखा कि कंपनी के निरूत्साह प्रवृति के कारण नवीकरण के आवेदन के 19 वर्षो के बाद में कंपनी ने आईबीएम को खनन योजना प्रस्तुत किया (मई 2014) और इसका अनुमोदन लंबित था (दिसम्बर 2014)। कंपनी ने राज्य वन विभाग को वन अपयोजन प्रस्ताव जमा किया था (जून 2013) जो कि वन विभाग द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को अनुमोदन के लिये अभी तक अग्रेषित किया जाना था। कंपनी ने अभी तक पर्यावरण अनापत्ति के लिये कार्यवाही प्रारंभ नहीं की थी तथा झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से खान के संचालन के लिये सहमति प्राप्ति हेतु आवेदन नहीं किया था (दिसम्बर 2014) जिसके परिणामस्वरूप, 1997 से खान अपरिचालित रही।

इस प्रकार, दिसम्बर 2014 तक वैधानिक अनापत्तियॉ प्राप्ति करने में कंपनी के असफलता के कारण उपरोक्त सभी चूना पत्थर खानें अपरिचालित रही।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि आईबीएम ने सेमरा सलातुआ और सलहन के खनन योजना के अनुमोदन हेतु निरीक्षण किया है। बेंती-बागदा और सलहन खानों के लिए वन अनापत्ति का प्रस्ताव वन विभाग के पास लंबित है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से बेंती-बागदा खान के लिये टीओआर प्राप्त किया जा चुका है तथा पर्यावरण प्रभाव आंकलन/पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी प्रक्रियाधीन है।

तथ्य यथावत है कि वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में खानें अपरिचालित रहे।

[24] इसमें खान के परिचालन अवधि के पहले, अवधि के दौरान एवं बाद के सभी आवश्यक गतिविधियों के लिए एक प्रभावी योजना शामिल है, जो मितव्ययी रूप से एक स्वीकार्य भूसतह के निर्माण एवं भूमि के पुर्नस्थापन के निर्माण के लिए आवश्यक है।

2.17 अपरिचालित ग्रांइडिंग फैक्टरी पर निष्क्रिय व्यय

कंपनी ने एक संवेदक[25] को सेमरा सलातुआ से चूना पत्थर टुकड़ों के रेजिंग और अपने सुदना ग्रांइन्डिग फैक्टरी (फैक्टरी) में पीस कर चूना पत्थर चूर्ण के उत्पादन और उत्पादों के क्रय के लिए तीन वर्षों के लिए नियुक्त की (अगस्त 2007)। अनुबंध के शर्तो के अनुसार, संवेदक को प्रति वर्ष कम से कम 36,000 एमटी चूना पत्थर टुकडों का उत्पादन और क्रय करना था। इसके अतिरिक्त, संवेदक को प्रति वर्ष अनुमोदित दर पर 3600 एमटी चूना पत्थर टुकड़े की आपूर्ति करना और पीसना आवश्यक था और ऐसे उत्पादित चूना पत्थर चूर्ण को विक्रय मूल्य तथा रेजिंग, ग्रांइडिंग, परिवहन व्यय सहित के अन्तर राशि का भुगतान कर क्रय करना था।

कम्पनी चूर्ण उत्पादन के लिए चूना पत्थर टुकडों की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही और ₹ 40.04 लाख का हानि वहन किया।

हमने देखा कि संवेदक ने सितम्बर 2007 से अगस्त 2010 के दौरान 46296 एमटी चूना पत्थर टुकड़ों का उत्खनन किया यधपि 10500 एमटी चूना पत्थर चूर्ण के उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 1853 एमटी चूना पत्थर टुकडों (8647 एमटी की कमी) का ही आपूर्ति किया। इस प्रकार, कंपनी संवेदक द्वारा चूना पत्थर चूर्ण उत्पादन के लिए अपेक्षित चूना पत्थर टुकड़ों के आपूर्ति सुनिश्चित करने में असफल रही जिसके फलस्वरूप ₹ 40.04 लाख[26] की हानि हुई।

उपर्युक्त करार के समाप्ति पर (सितम्बर 2010) कंपनी ने यह कार्य एक दूसरे[27] संवेदक को प्रदान किया (मई 2011)। हालांकि, संवेदक को संविदा के शर्तो के अनुसार 4800 एमटी चूना पत्थर टुकडों को फैक्टरी में पीसने के लिए आपूर्ति करना था परन्तु उसने कोई चुना पत्थर टुकड़ा फैक्टरी को आपूर्ति नहीं किया, चूँकि इसे विभागीय या बाहरी एजेंसी की नियुक्ति द्वारा संचालन करने में कंपनी की असफलता के कारण फैक्टरी सितम्बर 2010 से बन्द रहा। इसके अलावा, सेमरा सलातुआ चूना पत्थर खान में चूना पत्थर टुकड़े का उत्पादन, जो फैक्टरी को कच्चा माल आपूर्ति कर रहा था, भी पर्यावरण अनापत्ति उपलब्ध नहीं रहने के कारण जून 2012 से बन्द हो गया।

इस प्रकार, कंपनी ग्रांइडिंग फैक्टरी को सितम्बर 2010 से संचालित करने में असफल रही, फलस्वरूप मार्च 2014 तक ₹ 87.80 लाख का वेतन एवं मजदूरी (₹ 83.43 लाख) एवं बिजली व्यय (₹ 4.37 लाख) पर, निष्क्रिय व्यय करना पड़ा।

सरकार ने उत्तर दिया कि प्रथम संवेदक अनुबंध के शर्तो एवं बंधेजों के अनुपालन में असफल रहा था। नोटिस निर्गत किये गये थे तथा एजेंसी को भुगतेय राशि को अर्थ दंड की वसूली हेतु रोका गया है। संवेदक की नियुक्ति नहीं किया जा सका चूंकि

---

[25] एमएलसी लिमिटेड।

[26] विक्रय मुल्य ₹ 750 - (रेजिंग लागत ₹110 + परिवहन लागत ₹ 75 + ग्राइंडिंग लागत ₹ 82 + अर्थदण्ड ₹ 20) यानी ₹ 463 प्रति एमटी x 8647 एमटी = ₹ 40.04 लाख।

[27] भवानी इंडस्ट्रीज।

निविदा के विरूद्ध कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुआ था। साथ ही, फैक्टरी को विभागीय स्तर से संचालित भी नहीं किया जा सका।

तथ्य यथावत है कि कंपनी संवेदक द्वारा चूना पत्थर टुकड़ों की अनुबंधित मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं फैक्टरी को संचालित करने में असफल रही जिसके परिणामस्वरुप राजस्व अर्जन हेतु आधारभूत संरचना अनुपयोगी रहा।

कंपनी को अवरोधों को दूर कर फैक्टरी के संचालन हेतु कदम उठाने एवं इसको लाभकारी तरीके से चलाने की जरूरत है।

2.18 चूना पत्थर खानों में खान विनियम का उल्लंघन

धातु खान विनियम, 1961 के नियम 106 के अनुसार (कोयला एवं तेल के अलावा अन्य सभी खानों में लागू) खान के किनारों को बेंच करके रखना था और किसी भी बेंच की ऊँचाई 1.5 मीटर से अधिक और चौड़ाई, ऊँचाई से कम नहीं होनी थी।

खान सुरक्षा महानिदेशक ने विनियमों के अनुपालन नहीं करने के कारण सेमरा-सलातुआ खान में व्यक्तियों के नियुक्ति को निषेध किया।

अभिलेखों के संवीक्षा से हमने अवलोकित किया कि सेमरा-सलातुआ चूना पत्थर खान में उत्खनन 1.5 मीटर की स्वीकार्य बेंच ऊँचाई के विरूद्ध लगभग 40 मीटर ऊँचाई पर अपर्याप्त बेंच की चौड़ाई बनाकर किया गया था। खान सुरक्षा महानिदेशक ने कंपनी को 60 दिनों के अंदर त्रुटियों को सुधारने का निर्देश दिया (सितम्बर 2010)। चूंकि कंपनी अनुपालन में विफल रही, खान सुरक्षा महानिदेशक ने खानों में व्यक्तियों की नियुक्ति को निषेध कर दिया (नवम्बर 2011)। तथापि, हमने देखा कि खान में उत्पादन मई 2012 तक जारी रहा। उसके बाद, पर्यावरण अनापत्ति के अभाव में खान अभी तक असंचालित रहा (दिसम्बर 2014)।

सरकार ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा कि वैधानिक अनापत्तियों को प्राप्त करने के बाद, कंपनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

तथ्य यथावत है कि खनन संचालन विनियम के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के कारण निलंबित रहा।

ग्रेफाइट खान

2.19 वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में ग्रेफाइट खानों का अपरिचालन

ग्रेफाइट कार्बन का एक रवा क्रिस्टलीय रूपान्तरण है, जिसका उपयोग सूखे बैटरी, रिफ्रैक्सनरीज, पेन्सिल, इलेक्ट्रोड, लूबरीकेन्ट, विस्फोटक तथा पेन्ट इत्यादि के निर्माण में उपयोग होता है। बि.रा.ख.वि.नि. के पास 1285.18 एकड़ में आच्छादित दो ग्रेफाइट खान पट्टे महुँगाई-तुलबुला और मानासोती में थी। इन खानों के पट्टा अवधि के समापन के बाद (महुँगाई-तुलबुला - अक्टूबर 1996 एवं मानासोती - सितम्बर 1999) पट्टों का नवीकरण पूर्वापेक्षित शर्तों को पूरा न करने के कारण प्रदान नहीं किया गया जैसा कि नीचे वर्णित है:

• महुँगाई-तुलबुला के 552.15 एकड़ क्षेत्र के पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन बि.रा.ख.वि.नि. द्वारा जमा किया गया था (अक्टुबर 1995) तथा खनन योजना

अनुमोदित था (अगस्त 1999)। कंपनी ने वन भूमि के 48.98 एकड़ का अपयोजन के लिए प्रस्ताव जमा की (अप्रैल 2008) जिसे राज्य वन विभाग द्वारा विमुक्त नहीं किया गया चूंकि यह अपूर्ण था तथा इसमें अनेक त्रुटियाँ थी। इसके अलावा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को पर्यावरण अनापत्ति के लिए आवेदन जुलाई 2013 को किया गया जिसका अनुमोदन प्रतिक्षित था (दिसम्बर 2014)।

महुँगाई-तुलबुला खान में वन पर्यावरण अनापत्ति एवं अनुमोदित खनन स्कीम के बिना खनन परिचालन को जिला खनन अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया।

कंपनी पर्यावरण अनापत्ति एवं अनुमोदित खनन स्कीम के बिना ही खनन परिचालन कर रही थी। जिसके कारण, खनन का परिचालन जिला खनन अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया था (जनवरी 2013) एवं आईबीएम ने भी अनुमोदित खनन स्कीम के बिना खनन कार्य को निषेध कर दिया (फरवरी 2014)। इसके अलावा, कंपनी ने झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति हेतु आवेदन की थी (जुलाई 2012)। यधपि, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने खनन पट्टे के अवधि की समाप्ति के बाद, पर्यावरण मंजूरी, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं परिचालन हेतु सहमति के बिना खान के परिचालन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया (दिसम्बर 2012)। खान परिचालन की सहमति अब-तक प्रदान नहीं की गयी है (दिसम्बर 2014)।

मानासोती ग्रेफाइट खान 1985 से वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में अपरिचालित रहा।

- मानासोती ग्रेफाईट खान के 733.03 एकड़ क्षेत्र में पट्टे के नवीकरण का आवेदन बि.रा.ख.वि.नि. द्वारा जमा किया गया था (अगस्त 1998)। कंपनी (झा.रा.ख.वि.नि.) ने संबंधित दस्तावेजों के अनुपलब्धता के कारण खनन योजना नहीं बनायी। कंपनी ने वन अपयोजन प्रस्ताव एवं पर्यावरण अनापत्ति के अनुमोदन साथ ही साथ झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति हेतु अभी तक कोई कारवाई शुरु नहीं किया (दिसम्बर 2014)। परिणामत: खान 1985 से असंचालित रही।

सरकार ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा कि महुँगाई-तुलबुला का खनन योजना एवं प्रगामी खान समापन योजना तैयार किया गया है और आईबीएम को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। वन विभाग को प्रस्तुत वन अपयोजन प्रस्ताव को संबंधित खनिजीकृत क्षेत्र जोन के संशोधन हेतु वापस किया गया था। मानासोती के पट्टे का प्रर्त्यापण विचारधीन है।

तथ्य यथावत है कि वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने में असफल रहने के कारण महुँगाई-तुलबुला खान अपरिचालित रहा। इसके अलावा, मानासोती खान के प्रत्यार्पण का प्रस्ताव अभी तक प्रस्तुत किया जाना था।

कायनाइट खान

2.20 वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में कायनाइट खान का अपरिचालन

कायनाइट रासायनिक दृष्टिकोण से उच्च एल्यूमिना सिलिकेट खनिज है, जिसका उपयोग मुख्यत: रिफ्रेक्ट्री उत्पादन में होता है। कंपनी ने कायनाइट के दो पट्टे पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के ज्योतिपहाड़ी एवं सिरबोई में प्राप्त की थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुए:

• कंपनी ने ज्योतिपहाड़ी खान के 50.25 एकड़ क्षेत्र के पट्टे के नवीकरण हेतु आवेदन की (अगस्त 2003)। खान का खनन योजना मार्च 2007 में अनुमोदित हो चुका था, तथापि कंपनी द्वारा प्रस्तुत खनन स्कीम (एमएस) एवं प्रगामी खान समापन योजना (पीएमसीपी) त्रुटियों के वजह से अनुमोदित नहीं हुआ था। कंपनी ने संशोधित खनन स्कीम जमा किया (जनवरी 2014) जिसका भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निरीक्षण किया गया था (मार्च 2014), तथापि अब तक इसे अनुमोदित नहीं किया गया है (दिसम्बर 2014)।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरणीय अध्ययन के लिए टीओआर जारी किया (फरवरी 2009) जो खनन स्कीम के जमा नहीं किये जाने के कारण कालतिरोहित हो गया (फरवरी 2012) और नया टीओआर अबतक प्राप्त किया जाना था। पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार नहीं किया जा सका था और पर्यावरण अनापत्ति भी प्राप्त नहीं किया जा सका। कंपनी ने खान के परिचालन हेतु झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के सहमति के लिए आवेदन नहीं किया (दिसम्बर 2014)।

ज्योतिपहाड़ी में खनन परिचालन अगस्त 2012 से अनुमोदित खनन स्कीम और पर्यावरण अनापत्ति के अभाव में बन्द रहा।

हमने पाया कि कंपनी अनुमोदित खनन स्कीम एवं प्रगामी खान समापन योजना और पर्यावरण अनापत्ति के बिना ही खनन कार्य कर रही थी। परिणामस्वरूप, आईबीएम ने खनन परिचालन निलंबित कर दिया (जून 2012) और जिला खनन अधिकारियों ने भी पर्यावरण अनापत्ति के अभाव में, खनन क्षेत्र में वाहनों के परिवहन के लिए परिवहन चालान निर्गत करने से इनकार कर दिया (अगस्त 2012)। इस प्रकार, अनुमोदित खनन स्कीम एवं प्रगामी खान समापन योजना और पर्यावरण अनापत्ति के अभाव में खनन कार्य अपरिचालित रही।

• कंपनी ने सिरबोई खान के 168.40 एकड़ क्षेत्र पर खनन पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत की (अगस्त 2003)। सिरबोई का खनन योजना जूलाई 2000 में अनुमोदित हो चुका था। वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने पर (फरवरी 2008), वन विभाग ने झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं प्रस्ताव में निहित त्रुटियों को भी सुधारने का निर्देश दिया (मई 2008)। कंपनी ने इसके अनुपालन में पाँच साल से भी अधिक अनावश्यक लंबी अवधि लिया और संशोधित वन अपयोजन प्रस्ताव प्रस्तुत की (जनवरी 2014) जिसे वन विभाग द्वारा अबतक विमुक्त नहीं किया गया है (दिसम्बर 2014)। इस प्रकार, प्रस्ताव को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अनुमोदनार्थ अभी भी अग्रेषित किया जाना है।

कम्पनी सिरबोई खान के लिए वन और पर्यावरण अनापत्तियों को प्राप्त करने में विफल रही और झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति प्राप्त नहीं की जिसके कारण खान 1992 से अपरिचालित रही।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण अध्ययन हेतु टीओआर जारी किया (फरवरी 2010) तथापि, कंपनी टीओआर के वैधता अवधि (फरवरी 2013) में पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने मे असफल रही। तत्पश्चात, कंपनी ने पर्यावरण अनापत्ति हेतु टीओआर के निर्धारण के लिए आवेदन नहीं किया था। साथ ही, खान के प्रचालन हेतु

झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड का सहमति भी अब तक प्राप्त नहीं किया गया था (दिसम्बर 2014)। परिणामत:, खान 1992 से अपरिचालित रही।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि आईबीएम ने ज्योतिपहाड़ी खान के खनन स्कीम का अनुमोदन हेतु निरीक्षण किया है। टीओआर का अंतिमीकरण राज्य पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण समिति, झारखण्ड के पास विचाराधीन है एवं सिरबोई खान का वन अपयोजन प्रस्ताव वन विभाग के पास लंबित है।

तथ्य यथावत है कि उपरोक्त खानों के पट्टे के नवीकरण में अत्यधिक विलम्ब हुए और वैधानिक अनापत्ति प्राप्ति में देरी के वजह से खानें अपरिचालित रही।

2.21 निजी संवेदकों द्वारा चूना पत्थर, ग्रेफाइट एवं कायनाइट के उत्पादन में कमी

कंपनी 2009-2013 के दौरान विविध अवधियों में बेंती-बागदा एवं सेमरा सलातुआ खानों से चूना पत्थर टुकड़े और महुँगाई-तुलबुला से ग्रेफाइट का उत्खनन कर रही थी। ज्योतिपहाड़ी खान से कायनाइट का खनन कार्य निजी संवेदकों के साथ-साथ विभागीय स्तर द्वारा किया जाता था। 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान खनिजों का खान-वार अनुबंधात्मक उत्पादन लक्ष्य के तुलना में वास्तविक उत्पादन **तालिका-2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2

(एमटी में आँकड़ें)

खान का नाम	खनिज का नाम	खनन की अवधि	अनुबंधित मात्रा	वास्तविक उत्पादन	कमी	कमी (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(4)x 100
बैंती-बागदा चुना पत्थर	चूना पत्थर	01.12.10 to 30.06.12	93127	50381	42746	45.90
सेमरा सलातुआ	चूना पत्थर	01.04.09 to 31.05.12	153785	77337	76448	49.71
महुँगाई-तुलबुला	ग्रेफाइट	01.05.12 to 31.12.12	10865	1518	9347	86.03
ज्योतिपहाड़ी	कायनाइट	01.05.10 to 31.07.12	16370	8161	8209	50.15

(स्रोत - झा.रा.ख.वि.नि. द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़ें)

चूना पत्थर, ग्रेफाइट और कायनाइट के उत्पादन में अनुबंधित मात्रा से 45.90 प्रतिशत से लेकर 86.03 प्रतिशत तक की कमी थी।

उपर्युक्त से यह प्रकट होता है कि संवेदकों ने अनुबंध अवधि के दौरान उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे और 2009-10 से 2012-13 के दौरान चुना पत्थर (119194 एमटी), ग्रेफाइट (9347 एमटी) एवं कायनाइट (8209 एमटी) के उत्पादन में कमी थी, जो इन खनिजों के अनुबंधित मात्रा के 45.90 प्रतिशत से 86.03 प्रतिशत के बीच था। कमियों का कारण मशीनों के विलंब एवं अपर्याप्त

उपलब्धता, संवेदकों की लापरवाही एवं कंपनी की तरफ से अनुश्रवण की कमी थे। उत्पादन में कमियों के फलस्वरुप कंपनी को सार्थक राजस्व की हानि हुई।

कंपनी ने संवेदकों के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में सतत असफलता के बावजूद उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की। कम्पनी ने उत्पादन बढ़ाने के लिए सक्षम संवेदकों की नियुक्ति की संभावना का भी खोज नहीं की थी।

सरकार ने उत्तर दिया कि कंपनी ने उत्पादन में कमी को ध्यान में रखते हुए अर्थदण्ड लगायी थी एवं उत्पादन में कमी कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों यथा स्थानीय कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, नक्सल बंद इत्यादि एवं बाजार मांग में मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण से भी थे, जो एजेंसियों के साथ-साथ कंपनी के नियंत्रण से बाहर थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी द्वारा लगाया गया अर्थदण्ड उत्पादन में हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा, कंपनी ने उपरोक्त परिस्थितियों, जिसके कारण उनके उत्पादन प्रभावित हुए थे, को ध्यान में रखते हुए खानों के उत्पादन लक्ष्यों को पहले से ही संशोधित कर दी थी। इस प्रकार, कंपनी उत्पादन में कमी के लिए संवेदकों के विरूद्ध प्रभावी कदम उठाने में असफल रही।

कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि संवेदक उत्पादन लक्ष्यों का पालन करें।

पत्थर खान

2.22 पत्थर खानों का अपरिचालन

कंपनी का पत्थर खान चन्दुला सिमलगोड़ा में 172.80 एकड़ क्षेत्र पर था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने चन्दुला सिमलगोड़ा के वन अपयोजन प्रस्ताव (स्टेज-I अनापत्ति) सम्पूर्ण वन क्षेत्र (69.93 हेक्टर) के लिए वर्तमान मूल्य का भुगतान झारखण्ड सरकार को करने की शर्त पर अनुमोदित किया (जुलाई 2010)। झारखण्ड सरकार ने कंपनी को वन भूमि के अपयोजन के लिए निवल वर्तमान मूल्य के मद में ₹ 5.61 करोड़ (दिसम्बर 2011 में संशोधित ₹ 4.38 करोड़) एवं क्षतिपूरक वनरोपन के लिए ₹ 1.25 करोड़ भुगतान करने का निर्देश दिया (अगस्त 2010)।

कंपनी ने खानों के लिए खान विकासक सह प्रचालक (एमडीओ) के चयन के लिए एक निविदा प्रकाशित किया (मई 2013)। निविदा के शर्त के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य एवं वनरोपन शुल्कों का भुगतान चयनित एजेंसी द्वारा करना था। यधपि, पूर्व बोली बैठक में बड़े संख्या में निविदाकर्ता उपस्थित हुए, परन्तु उच्च प्रारंभिक निवेश एवं वैधानिक अनापत्तियों की प्राप्ति में अनिश्चितता के कारण कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। साथ ही, कंपनी ने निवल वर्तमान मूल्य एवं वनरोपन शुल्कों का भुगतान नहीं की और वन अनापत्ति प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

चन्दुला-सिमलगोड़ा पत्थर खान वैधानिक आपत्तियों की प्राप्ति में विफलता के कारण 2000 से अपरिचालित रही।

कंपनी ने आईबीएम को खनन योजना जनवरी 2014 में प्रस्तुत की जिसका अबतक अनुमोदित किया जाना था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय अध्ययन के लिए टीओआर निर्गत किया गया (मार्च 2014) तथापि कंपनी द्वारा पर्यावरण प्रभाव आंकलन/पर्यावरण प्रबंधन योजना अबतक बनाया जाना था। इस प्रकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण अनापत्ति अभी तक प्रदान नहीं किया गया है (दिसम्बर 2014)। कंपनी ने खान के परिचालन हेतु झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति के लिए आवेदन नहीं की थी।

इस प्रकार, चन्दुला सिमलगोड़ा पत्थर खान कंपनी के वैधानिक अनापत्तियों की प्राप्ति एवं एमडीओ के नियुक्ति में असफलता के कारण 2000 से अपरिचालित रही।

सरकार ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा कि खनन योजना के अनुमोदन हेतु कार्रवाई किया गया है। एमडीओ का चयन विचाराधीन है। एमडीओ द्वारा देय प्रारंभिक पूँजी निवेश की शर्त कंपनी के निधि के अवरोध से बचने के लिए निर्धारित किया गया था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से टीओआर प्राप्त हो गया है और पर्यावरण प्रभाव आंकलन/पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी प्रक्रियाधीन है।

तथ्य यथावत है कि वैधानिक अनापत्तियों एवं एमडीओ की नियुक्ति के अभाव में खान पिछले 14 वर्षो से संचालन में नहीं थी।

ग्रेनाइट खान एवं ग्रेनाइट टाइल्स प्लांट

2.23 ग्रेनाइट खान का अल्प निष्पादन

ग्रेनाइट एक अन्तर्वेधी आग्नेय चट्टान है जो वृहद पैमाने पर भवन निर्माण एवं वास्तुशिल्प डिजाइन में उपयोग होता है। कंपनी का दो एकड़ पट्टा क्षेत्र में एक ग्रेनाइट खान है।

कम्पनी द्वारा ग्रेनाइट ब्लॉकों के उत्पादन में 95.72 प्रतिशत की कमी के कारण तुपुदाना ग्रेफाइट प्लांट अल्प निष्पादन में था।

कंपनी चेलांगी ग्रेनाइट खान से ग्रेनाइट ब्लॉक विभागीय स्तर पर उत्खनन कर रही थी। चेलांगी ग्रेनाइट खान के अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, ग्रेनाइट ब्लॉक का उत्पादन लक्ष्य प्रति वर्ष 6499 घन मीटर था। 2011-12 से 2013-14 की अवधि में 16,248 घन मीटर के ग्रेनाइट ब्लॉक के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में कंपनी ने 695 घन मीटर (4.28 प्रतिशत) उत्पादन कर सका। ग्रेनाइट ब्लॉक के उत्पादन में 15,553 घन मीटर (95.72 प्रतिशत) की कमी का कारण मानव शक्ति का अभाव था जो तुपुदाना ग्रेनाइट टाइल्स प्लांट के अल्प निष्पादन का कारण भी बना जैसा कि कंडिका 2.24 में विवेचित है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि तुपुदाना ग्रेनाइट प्लांट केवल छोटे ब्लॉकों को संभालने के लिए पर्याप्त है और छोटे ग्रेनाइट ब्लॉकों के लिए पड़ोस के क्षेत्र में कोई बाजार नहीं है। चूंकि उत्पादन प्लांट की क्षमता पर सीमित है और इसलिए कम मानव शक्ति लगाया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्लांट ग्रेनाइट ब्लॉकों के अभाव में अल्प उपयोग में रहा।

2.24 ग्रेनाइट टाइल्स प्लांट का अल्प उपयोग

बि.रा.ख.वि.नि. ने ग्रेनाइट कटिंग एवं पॉलिशिंग प्लांट (प्लांट) 1997 में स्थापित किया जिसका उत्पादन क्षमता 2500 वर्ग फीट प्रति माह था। प्लांट 2007 से 2010 तक ग्रेनाइट ब्लॉकों के अनुपलब्ध्ता के कारण असंचालित रहा। कंपनी ग्रेनाइट प्लांट को स्वयं के खान (चेलांगी) से विभागीय स्तर पर ग्रेनाइट ब्लॉकों के उत्पादन प्रारंभ होने पर पुन: आरंभ किया (मई 2011)। 2011-12 से 2013-14 के वर्षो में प्लांट के उत्पादन निष्पादन **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका - 2.3

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14
वार्षिक उत्पादन क्षमता (वर्गफीट)	30000	30000	30000
वार्षिक उत्पादन (वर्गफीट)	2392	9036	8872
वार्षिक क्षमता से उत्पादन का प्रतिशत	7.97	30.12	29.57

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़ें)

2011-12 से 2013-14 में ग्रेफाइट टाइल्स का वार्षिक उत्पादन, उत्पादन क्षमता का 7.97 प्रतिशत से 30.12 प्रतिशत था।

तालिका 2.3 से देखा जा सकता है कि ग्रेनाइट टाइल्स का वार्षिक उत्पादन 2011-12 में 2392 वर्गफीट, 2012-13 में 9036 वर्गफीट एवं 2013-14 में 8872 वर्गफीट था जो इस अवधि के दौरान वार्षिक उत्पादन क्षमता का 7.97 से 30.12 प्रतिशत था। प्लांट के अल्प उपयोग का कारण ग्रेनाइट ब्लॉक, डायमंड ब्लेड एवं कटिंग तेल की अनुपलब्धता थी।

फलस्वरुप, प्लांट 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान क्रमश: ₹ 46.49 लाख, ₹ 62.11 लाख, और ₹ 96.46 लाख की हानि वहन किया जिसमें निंरतर वृद्धि हो रही थी। हानि का कारण निष्क्रिय मानवशक्ति पर वेतन एवं मजदूरी में व्यय एवं प्लांट का उन्नयन ना होना था।

हमने अवलोकित किया कि कंपनी मई 2013 में प्लांट के उन्नयन के लिए प्रस्ताव तैयार किया, तथापि उन्नयन अभी तक किया जाना था (दिसम्बर 2014) और कंपनी व्यवहार्यता सुनिश्चित किए बिना प्लांट का परिचालन कर रही थी।

सरकार ने उत्तर दिया कि तुपुदाना प्लांट एक प्रायोगिक प्लांट था, प्रबंधन वाणिज्यिक उत्पादन के लिए सुधारात्मक उपाय शुरु करने का प्रयास करेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्लांट पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन में था। प्लांट के उन्नयन का प्रस्ताव इसके प्रारंभ के 18 माह बीतने के बाद भी अब तक अनुमोदित किया जाना था।

कंपनी को प्लांट के निष्क्रिय क्षमता के उपयोग एवं इसके वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना चाहिए।

इस तरह, नौ मौजूदा गैर कोयला खानों में से केवल पाँच खानों[28] के खनन योजनायें अनुमोदित थे, एक खान (सेमरा-सलातुआ) के लिए वन अनापत्ति प्राप्त किया गया था और किसी भी खान के लिए पर्यावरण अनापत्ति और झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति अबतक प्राप्त नहीं किया जा सका था (दिसम्बर 2014) जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में विवेचित है।

परिणामत:, आठ खाने दिसम्बर 2014 तक अपरिचालित रही हालांकि चार[29] खानों से खनन विभिन्न अवधियों के दौरान किया गया और इनको सरकार द्वारा वन एवं पर्यावरण अनापत्ति, खनन योजना एवं खनन स्कीम के अभाव में बंद कर दिया गया था। फलस्वरुप, जनवरी 2013 से इन खानों में नियुक्त मानवशक्ति (115 कर्मचारी) निष्क्रिय रहे।

कंपनी सुदना ग्रांइडिंग फैक्टरी के संचालन में विफल रहा जो सितम्बर 2010 से बंद रहा, परिणामत: फैक्टरी के अपरिचालन के कारण ₹ 87.80 लाख का निष्क्रिय व्यय हुआ। तुपुदाना ग्रेनाइट प्लांट निष्क्रिय मानवशक्ति पर वेतन एवं मजदूरी के व्यय और प्लांट के उन्नयन न होने के कारण 2011-2014 के दौरान ₹ 2.05 करोड़ का हानि वहन किया।

कंपनी को खानों के विकास एवं वैधानिक आवश्यकताओं के समयबद्ध अनुपालन हेतु प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

2.25 खनिजों के स्टॉक का अनिस्तारीकरण

वन अनापत्ति के अभाव में ₹ 23.71 लाख मूल्य के खनिजों का स्टॉक बिना निस्तारीकरण के रहा।

31 मार्च 2010 को कायनाइट (921 लाख एमटी) चूनापत्थर (3198 लाख एमटी) मैग्नेटाइट (304 लाख एमटी) और ग्रेफाइट (6917 लाख एमटी) का अविक्रीत स्टॉक था। खनिजें वन क्षेत्र में पड़े हुए थे। इन खनिजों का अनुमानित उगाही योग्य मूल्य कंपनी द्वारा 2008 में निविदा के लिए तय सुरक्षित मूल्य के आधार पर ₹ 23.71 लाख था।

हमने देखा कि इन खनिजों के निस्तारीकरण के लिए निविदा 2008 एवं 2009 में किया गया था और कार्य आदेश जारी किए गए थे। चूंकि वन विभाग, वन अनापत्ति के अभाव में वन क्षेत्र से खनिजों को उठाने की अनुमति नहीं दिया इनको निस्तारित नहीं किया जा सका। खनिज स्टॉक के अपरिशोधन के परिणामस्वरुप कार्यशील पूँजी अवरूद्ध हुई एवं उनके गुणवत्ता में ह्रास के कारण इसके कीमत में गिरावट हो रही थी। इसके अलावा, खनिजों के स्टॉक का लंबे समय तक भंडार, चोरी एवं कमी के लिए अतिसंवेदनशील थे।

सरकार ने तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा कि अपलेखन सहित इनके निस्तारीकरण के लिए संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

---

[28] बेंती-बागदा, ज्योतिपहाड़ी, सिरबोई, महुँगाई-तुलबुला, चेलांगी।

[29] बेंती-बागदा (दिसंबर 2010 से जून 2012 के दौरान परिचालित), सेमरा सलातुआ (सितम्बर 2007 से मई 2012), ज्योतिपहाड़ी (मई 2010 से जुलाई 2012) एवं महुँगाई-तुलबुला (मई 2012 से दिसंबर 2012)।

तथ्य यथावत हैं कि कंपनी वन अनापत्ति प्राप्त नहीं कर सकी एवं वन क्षेत्र में खनिजों के स्टॉक को उठाने हेतु अनुमति प्राप्ति के लिए अनुसरण नहीं किया ।

2.26 वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करना और खनिजों में कमी

बि.रा.ख.वि.नि. के निर्णय (मई 1989) के अनुसार, प्रत्येक वर्ष खानों के स्थलों पर खनिजों के स्टॉक का भौतिक रुप से सत्यापन करना चाहिये और खनिजों के निपटानीय (हैंडलिंग) हानियों के लिये स्वीकार्य सीमा/मानदंड 0.25 से 1.50 प्रतिशत तय की गयी थी। यधपि यह अवलोकित किया गया कि भौतिक सत्यापन समिति द्वारा मई 2010 में खानों के स्थलों पर खनिजों के स्टॉक को अतिंम बार सत्यापित किया गया था और चार खानों के खनिज स्टॉक में व्यापक कमियाँ पायी गयी थी जैसा कि **तालिका-2.4** में चित्रित है।

तालिका - 2.4

परियोजना का नाम	खनिजों का नाम	खाते में दर्ज स्टॉक (एमटी)	सत्यापित स्टॉक (एमटी)	कमी	
				मात्रा (एमटी) (प्रतिशत)	मूल्य ₹ लाख में
महुंगाई-तुलबुला ग्रेफाइट खान	ग्रेफाइट	4577.032	735.545	3841.487 (83.93)	13.83
रंका ग्रेफाइट खान (बंद खान)	ग्रेफाइट	21568.350	6181.086	15387.264 (71.34)	23.08
सेमरा-सलातुआ चूना पत्थर खान	चूना पत्थर	21817.776	1909.700	19908.076 (91.25)	29.86
	मेंगनेटाइट	16858.982	304.330	16554.652 (98.19)	48.01
मानासोती ग्रेफाइट खान	ग्रेफाइट	8870.233	2029.740	6840.493 (77.12)	10.33
कुल		**73692.373**	**11160.401**	**62531.972 (84.86)**	**125.11**

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़ें)

मई 2010 में हुये भौतिक सत्यापन में 0.25 से 1.50 प्रतिशत के मानदंडों के विरुद्ध 71.34 से 98.19 प्रतिशत असामान्य कमी का पता चला।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 0.25 से 1.50 प्रतिशत मानदण्डों के विरूद्ध खनिजों के स्टॉक में 71.34 से 98.19 प्रतिशत की असामान्य कमी थी। खनिजों की कुल कमी 62531.972 एमटी थी जिसका मूल्य ₹ 1.25 करोड़[30] था। कंपनी ने असामान्य कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, 2009-10 से लेखों के अंतिमीकरण के अभाव में लेखाबही में कमी का समायोजन प्रतीक्षित था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकार ने कहा कि लम्बे समय तक ढेर रखने और प्रतिकूल मौसमीय प्रभाव के कारण स्टॉक धँस जाता है। हाल के वर्षों में अंतिम

[30] कंपनी द्वारा 2008 के निविदा के लिए निर्धारित सुरक्षित मूल्य के आधार पर।

स्टॉक का सत्यापन वन विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के साथ-साथ स्टॉक पर बढे हुए झाड़ियों के कारण नहीं किया जा सका।

यधपि, तथ्य यथावत है कि कंपनी ने वर्ष 2010 के बाद ना तो भौतिक सत्यपन की थी ना ही मई 2010 में पाये गये भारी कमियों के कारणों की जाँच की थी।

नियत लगान का परिहार्य भुगतान

2.27 खान एवं खनिज (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधान के अनुसार, खनन पट्टा धारक झारखण्ड सरकार को पट्टा क्षेत्र से निकाले गए या उपभोग किए गए खनिजों पर रॉयल्टी या उस क्षेत्र से खनिजों के कम/अनुत्पादन के संबंध में नियत लगान जो भी उच्चतर था, के भुगतान का दायी था।

खानों के परिचालन के लिये वैधानिक अनापत्तियों की प्राप्ति में विफलता के कारण ₹ 99.83 लाख नियत लगान का परिहार्य भुगतान किया गया।

हमने अवलोकित किया कि 2009-10 से 2013-14 के दौरान, कंपनी के पाँच खानों[31] के संबंध में पट्टे के नवीकरण न होने के कारण खनिजों के अनुत्पादन/कम उत्पादन के कारण ₹ 99.83 लाख का नियत लगान भुगतान किया गया। इसका ₹ 77.76 लाख चंदुला-सिमलगोड़ा के पत्थर खानों से संबंधित था जो 2000 से बंद थी चूंकि इसके पास वन एवं पर्यावरण अनापत्तियाँ नहीं थी जिसके कारण वन विभाग ने खानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था। यधपि, जनवरी 2012 में पट्टे का नवीकरण की मंजुरी दिया गया है, वन एव पर्यावरण अनापत्तियों के अभाव में लीज डीड का निबंधन नहीं किया गया था।

कंपनी द्वारा वन एवं पर्यावरण अनापत्तियों की प्राप्ति में असफलता के कारण अन्य चार खानों में खनन (मई 2012 से दिसम्बर 2012 के दौरान महुँगाई-तुलबुला ग्रेफाइट खान के अलावा) नहीं किया जा सका, जिसके कारण 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹ 22.07 लाख का नियत लगान भुगतान किया गया। इस प्रकार, खानों के परिचालन हेतु वैधानिक अनापत्तियों की प्राप्ति में असफलता के कारण कंपनी द्वारा ₹ 99.83 लाख नियत लगान का परिहार्य भुगतान किया गया था।

सरकार ने उत्तर दिया कि नियत लगान का भुगतान सक्रिय (डायनमिक) पूँजीगत व्यय के रूप में किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि नियत लगान का भुगतान राजस्व प्रकृति का है।

तथ्य यथावत है कि वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में खानें असंचालित थे और नियत लगान का भुगतान बिना किसी उत्पादन के किया जा रहा था।

2.28 आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियाँ

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में लेखा आंकड़ों की परिशुद्धता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए दीर्घ एवं लघु अवधि योजना को विकासित करना, योजनाओं के सामयिक समीक्षायें, प्रत्येक उत्तरदायी क्षेत्र एवं उनके मूल्यांकन के नियंत्रण को परिभाषित करना, प्रणाली के परिकल्पना एवं प्रणाली का समीक्षा और

[31] सलहन, सिरबोई, चन्दुला सिमलगोड़ा, महुँगाई-तुलबुला और मानासोती।

उचित परिचालन तथा लेखा प्रक्रियाएं समाविष्ट होता है। तथापि, कंपनी के आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र में निम्नलिखित कमियां देखी गई:

• कंपनी ने 2009-10 के बाद परियोजना-वार लागत पत्र नहीं बनायी। लागत पत्र के अभाव में, कंपनी लागत प्रभावी रीति से विभिन्न खानों के परिचालन में उपयुक्त निर्णय लेने में असमर्थ थी।

सतर्कता और अनुश्रवण तंत्र एवं व्यापक प्रबंधन सूचना प्रणाली का अभाव था।

• खानों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्यचालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी का कोई सतर्कता एवं अनुश्रवण प्रणाली नहीं है।

• कंपनी विभिन्न सूचना/आंकड़ों के संग्रहण, समेकन एवं विश्लेषण हेतु कोई व्यापक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) नहीं बनायी थी, जिसके अभाव में प्रबंधन, कंपनी के सर्वोत्तम हित एवं उसके लाभकारिता में सुधार करने हेतु निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे।

सरकार ने कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन को कार्रवाई हेतु नोट किया गया है।

2.28.1 अनुबद्धित संख्या में निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन नहीं होना

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 285 प्रावधान करता है कि प्रत्येक कंपनी तीन महीने में कम से कम एक निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक का आयोजन करेगी और प्रत्येक वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित करनी है। कंपनी ने 2012-13 से 2013-14 के दौरान, आठ बैठकों में से पाँच निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित की और जुन 2013 के बाद कोई भी बैठक आयोजित नहीं किया। नियमित बैठकों के अभाव में, लेखापरीक्षा में यह पता नहीं हो सका कि निदेशक मंडल कंपनी के गतिविधियों का प्रभावी रुप से अनुश्रवण किये।

2012-13 से 2013-14 के दौरान आठ बैठकों के आवश्यकता के विरूद्ध निदेशक मंडल के मात्र पाँच बैठकें आयोजित की गयी थी।

सरकार ने अवलोकन को स्वीकारा और कहा कि पूर्ण निदेशक मंडल के गठन न होने, मुख्य प्रबंधकीय वैयक्तिक पद रिक्त रहने के कारण, बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

2.28.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण का एक अनिवार्य संघटक है। आंतरिक लेखापरीक्षक आंतरिक नियंत्रक की प्रभावकारिता और सुधारों की अनुशंसा की जाँच करते हैं। कंपनी का अपना आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था। कंपनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली भी अभी तक नही बनायी थी (दिसम्बर 2014)। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के अभाव में, कंपनी ने अपने निगमित कार्यालय एवं परियोजना कार्यालयों के आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु सांविधिक लेखाकारों को नियुक्त करता है। तथापि, उनके कार्य मुख्यत: लेखाओं के रोकड़ आधार पर नमुना जाँच तक ही सीमित थे। लेखापरीक्षक ने परियोजना-वार लाभप्रदता/ व्यवहार्यता तथा विभिन्न परियोजनाओं में नियुक्त मानवशक्ति के उपयोग की जाँच नहीं किया था।

कम्पनी के स्वयं का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था और आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल भी नहीं बनाया गया था।

सरकार ने कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन को कार्रवाई हेतु नोट कर लिया गया है।

कंपनी को विभिन्न आंतरिक नियंत्रण तंत्रों एवं प्रबन्ध सूचना प्रणाली को स्थापित एवं सुदढ़ करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- कंपनी ने आंवटित कोयला ब्लॉकों के विकास के लिए निर्धारित माइलस्टोन को प्राप्त नहीं कर सकी, परिणामस्वरूप नौ ब्लॉकों में खनन प्रारंभ नहीं हुआ। इनमें से, आठ कोयला ब्लॉकों को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किये गये और कंपनी द्वारा इन कोयला ब्लॉको पर किये गये ₹ 18.31 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय निरर्थक हो गया;
- कंपनी वैधानिक अनापत्तियों को प्राप्त करने मे असफल रही जिसके कारण 2012-13 के दौरान चार खनिज खानों में खनन क्रियायें बंद हो गयी, चार अन्य खनिज खानें 14 वर्षो से अधिक समय से अपरिचालित थे;
- 2013-14 के दौरान चेलांगी ग्रेनाइट खान के अलावा कोयला एवं अन्य खनिजों का कोई उत्पादन एवं विक्रय नहीं था;
- निजी संवेदकों द्वारा किये गये चूना पत्थर, ग्रेफाइट एवं कायनाइट के उत्पादन में अनुबंधित मात्रा का 45.90 प्रतिशत से लेकर 86.03 प्रतिशत का सार्थक कमी थी;
- सतर्कता और अनुश्रवण तंत्र एवं व्यापक प्रबंधन सूचना प्रणाली का अभाव था। कंपनी का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था।

अध्याय-III

अध्याय - III

3. लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों और सांविधिक निगम के लेन-देन की नमूना जाँच करने पर पाये जाने वाले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सन्निहित है।

सांविधिक निगम

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

3.1 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अल्पावधि ऊर्जा क्रय पर दीर्घ कंडिका

3.1.1 प्रस्तावना

झारखण्ड में ऊर्जा के उत्पादन, संचरण और वितरण का कार्य दिसम्बर 2013 तक झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) द्वारा किया जाता था और जेएसईबी का जनवरी 2014 में चार कंपनियों[1] में विखण्डन के बाद ऊर्जा का क्रय झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) जोकि ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में था, के द्वारा किया जा रहा था। जेएसईबी अपने पतरातु थर्मल ऊर्जा स्टेशन, पतरातु और पनबिजली स्टेशन, सिकिदिरी से ऊर्जा उत्पादन कर रही थी।

जेएसईबी अपने ऊर्जा आवश्यकता को वार्षिक राजस्व आवश्यकता के माध्यम से झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) को दाखिल करता है। इसके बाद जेएसईआरसी इसकी समीक्षा के पश्चात ऊर्जा आवश्यकता की मात्रा की संस्तुति प्रदान करती है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदित ऊर्जा आवश्यकता, जेएसईबी का अपना ऊर्जा उत्पादन तथा आवश्यकता एवं अपना ऊर्जा उत्पादन के बीच अंतर का विवरण **तालिका-3.1** में दिखाया गया है।

तालिका 3.1

(आँकड़े एमयू में)

वर्ष	जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदित ऊर्जा आवश्यकता[2]	अपना ऊर्जा उत्पादन	ऊर्जा आवश्यकता एवं अपने उत्पादन में अन्तर	अन्तर का प्रतिशत
1	2	3	4 = (2-3)	5 = {(4/2)*100}
2009-10	7290	1084	6206	85
2010-11	7592	582	7010	92
2011-12	8383	635	7748	92
2012-13	9513	765	8748	92
2013-14	11435[3]	720	10715	94

(स्रोत: जेएसईआरसी का टैरिफ आदेश तथा जेएसईबी द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़ें)

---

[1] होल्डिंग कम्पनी झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियां झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड और झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

[2] युआई बिक्री को छोड़कर।

[3] जेएसईबी द्वारा याचित टैरिफ प्रस्ताव के अनुसार जो अभी तक जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदित नहीं था।

जेएसईबी का ऊर्जा उत्पादन वर्ष 2009-10 में 1084 मिलियन युनिट (एमयू) से घट कर वर्ष 2013-14 में 720 एमयू हो गया। जेएसईआरसी द्वारा स्वीकृत ऊर्जा आवश्यकता तथा अपने उत्पादन का अन्तर जो वर्ष 2009-10 में 85 प्रतिशत था बढ़कर वर्ष 2013-14 में 94 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार, जेएसईबी अपने ऊर्जा आवश्यकता को अपने उत्पादन द्वारा पूर्ति करने में असमर्थ था और दीर्घावधि[4] ऊर्जा क्रय समझौते (पीपीए) के द्वारा ऊर्जा क्रय कर रहा था । इसके अतिरिक्त, 2009-10 से 2013-14 के दौरान जेएसईबी द्वारा दामोदार घाटी निगम (डीवीसी), पावर ट्रैडिंग निगम (पीटीसी), टाटा पावर, आधुनिक पावर एवं नेचुरल रिसोरसेज लिमिटेड (एपीएनआरएल) इत्यादि से अल्पावधि[5] आधार पर तथा अनुसूचित विनियमन (युआइ)[6] के द्वारा भी ऊर्जा क्रय किया गया।

अल्पावधि ऊर्जा के क्रय पर व्यय 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹ 129.15 करोड़ से ₹ 337.93 करोड़ के बीच था जो इस अवधि में कुल ऊर्जा क्रय का 6.69 प्रतिशत से 11.77 प्रतिशत था।

3.1.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य, क्षेत्र एवं पद्धति

लेखापरीक्षा ने मूल्यांकन किया कि क्या जेएसईबी ने अल्पावधि ऊर्जा क्रय मितव्ययता के साथ अपने वित्तीय हित को सुरक्षित रखते हुए किया। लेखापरीक्षा अप्रैल 2014 से जून 2014 के दौरान किया गया जिसमें जेएसईबी के द्वारा वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच अल्पावधि ऊर्जा क्रय को समावेश किया गया। लेखापरीक्षा ने पूर्ववर्ती जेएसईबी और जेयूवीएनएल का निगम कार्यालय के अभिलेखों की जाँच की।

लेखापरीक्षा निष्कषों को जेयूवीएनएल के प्रबंधन तथा सरकार को 3 जुलाई 2014 को जारी किये गये थे। प्रबंधन का उत्तर प्राप्त हुआ (सितम्बर 2014), यद्यपि, सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)। समापन सभा दिनांक 12 सितम्बर 2014 को आयोजित हुआ जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार और अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, जेयूवीएनएल के साथ चर्चा की गई। जेयूवीएनएल के उत्तर उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.3 राज्य में ऊर्जा क्रय की स्थिति

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान दीर्घावधि एवं अल्पावधि में ऊर्जा क्रय का विवरण को **तालिका-3.2** में दर्शाया गया है:

[4] सात वर्षो से अधिक अवधि के लिये उर्जा क्रय समझौता।

[5] एक वर्ष से कम के लिए ऊर्जा क्रय समझौता।

[6] अधिसूचित ऊर्जा से कम या अधिक निकासी को अनुसूचित विनियमन (यूआई) कहा जाता है।

तालिका - 3.2

क्र.सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
1.	दीर्धावधि विद्युत क्रय[7] (एमयू में)	7120	7710	7734	8617	9528	40709
2.	दीर्धावधि ऊर्जा क्रय का कुल मुल्य (₹ करोड़ में)	1671.22	2032.77	2508.32	2985.34	3527.59	12725.24
3.	अल्पावधि विद्युत क्रय (एमयू में)	459	1052	1184	1056	902	4653
4.	अल्पावधि विद्युत क्रय का कुल मुल्य (₹ करोड़ में)	129.15	297.83	337.93	331.22	265.91	1362.04
5.	कुल विद्युत क्रय (एमयू में) (1+3)	7579	8762	8918	9673	10430	45362
6.	क्रय का कुल मूल्य (₹ करोड़ में) (2+4)	1800.37	2330.60	2846.25	3316.56	3793.50	14087.28
7.	कुल विद्युत क्रय में अल्पावधि क्रय का प्रतिशत (3/5)*100	6.06	12.01	13.28	10.92	8.65	10.26

(स्रोत: जेएसईआरसी का टैरिफ आदेश तथा जेएसईबी द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ें)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता कि जेएसईबी ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹ 14087.28 करोड़ की 45362 एमयू ऊर्जा की खरीद की जिसमें से ₹ 12725.24 करोड़ का 40709 एमयू ऊर्जा दीर्घावधि का था तथा ₹ 1362.04 करोड़ का 4653 एमयू ऊर्जा अल्पावधि का था।

अल्पावधि के आधार पर ऊर्जा क्रय

जेएसईबी द्वारा अल्पावधि ऊर्जा क्रय में अंकेक्षण के दौरान पायी गई कमियों को आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.1.4 कम दर पर उपलब्ध ऊर्जा की कम निकासी के कारण हानि

अपने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, जेएसईबी अल्पावधि आधार पर 100 मेगा वाट (एमडब्ल्यु) ऊर्जा डीवीसी से वर्ष 2010-11 से चौबीस घंटे लगातार क्रय कर रहा था।

जेएसईबी ने ₹ 2.77 प्रति इकाई की अंतरिम दर पर डीवीसी से वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान अल्पावधि आधार पर 3467.99 एमयू ऊर्जा क्रय किया। डीवीसी से वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान अल्पावधि आधार पर आपूर्ति किये गए ऊर्जा की दर को केन्द्रीय ऊर्जा नियामक आयोग द्वारा पुन: निर्धारण किया गया (जुलाई 2013), औसत पुन: निर्धारित दर वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और

[7] यूआई बिक्री शामिल नहीं।

2013-14 के लिये क्रमश: ₹ 3.31, ₹ 3.86, ₹ 4.11 और ₹ 4.32 प्रति इकाई निकाला गया था। यद्यपि, जेएसईबी द्वारा सभी स्रोतों से क्रय किये गये ऊर्जा का औसत लागत वर्ष 2010-11 में ₹ 2.66, 2011-12 में ₹ 3.19, 2012-13 में ₹ 3.43 और वर्ष 2013-14 में ₹ 3.63 प्रति इकाई था।

हमने पाया कि इस अवधि (2010-14) के दौरान जेएसईबी ने 2174.40 एमयू महत्वपूर्ण परिमाण ऊर्जा की कम निकासी की थी, जिसके लिए निम्नतर दर वर्ष 2010-11 में ₹ 2.61, वर्ष 2011-12 में ₹ 2.44, वर्ष 2012-13 में ₹ 2.17 और वर्ष 2013-14 में ₹ 0.96 प्रति इकाई वसूल किया था, परिणामस्वरूप ऊर्जा की कम निकासी के कारण ₹ 231.24 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

जेयूवीएनएल ने 2174.40 एमयू ऊर्जा की कम निकासी को स्वीकार करते हुए कहा कि जेएसईबी/जेयूवीएनएल ने विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा क्रय किया था इसलिए ऊर्जा बिक्री से हानि को ऊर्जा के किसी एक स्रोत के संदर्भ में दिखाना उचित छवि प्रदर्शित नहीं करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जेएसईबी ने कम निकासी किये गये ऊर्जा के लिये विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा की औसत क्रय लागत की तुलना में निम्नतर दर वसूल कर पाया था। साथ ही, जेएसईबी डीवीसी से एक दिन पूर्व के शिड्यूल के आधार पर लगभग 2.40 एमयू ऊर्जा प्रतिदिन चौबीस घंटे लगातार क्रय कर रहा था, इसलिए डीवीसी से ऊर्जा नहीं लेना चाहिए था जब दूसरे स्रोतों से निम्न दर पर अधिशेष ऊर्जा उपलब्ध था।

जेयूवीएनएल को अल्पावधि में ऊर्जा क्रय करने से पूर्व अपने ऊर्जा आवश्यकता को उपयुक्त तरीके से निर्धारण करने की आवश्यकता है ताकि ऊर्जा की कम निकासी से बचा जा सके।

3.1.5 संचरण लाइन की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना व्यापार हेतु निजी ऊर्जा उत्पादक से ऊर्जा क्रय

एक निजी ऊर्जा उत्पादक मेसर्स आधुनिक पावर और नेचुरल रिसोरसेज लिमिटेड (एपीएनआरएल) ने जेएसईबी को 200 मेगावाट ऊर्जा आपुर्ति का प्रस्ताव दिया (फरवरी 2013)। प्रस्ताव के आधार पर, जेएसईबी ने अल्पावधि आधार पर ₹ 3.50 प्रति युनिट की दर से 100 मेगावाट ऊर्जा एपीएनआरएल से क्रय करने का निर्णय किया (फरवरी 2013) यह ऊर्जा आंध्र प्रदेश ऊर्जा समन्वय समिति (एपीपीसीसी) को एक ऊर्जा व्यापारिक कंपनी (मेसर्स मित्तल प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड) के माध्यम से व्यापार करना/बेचना था। यद्यपि, जेएसईबी द्वारा गठित (अगस्त 2013) समिति की सिफारिश के आधार पर यह दर मार्च 2013 के लिए ₹ 3.12 प्रति युनिट एवं अप्रैल 2013 के लिए ₹ 3.14 प्रति युनिट बाद में पुन: निर्धारित की गई।

हमने पाया कि जेएसईबी ने ऊर्जा व्यापारिक कंपनी से क्रय का प्रस्ताव (7 मार्च 2013) पाने से पहले एपीएनआरएल से 100 मेगावाट ऊर्जा क्रय करना शुरू किया था (1 मार्च 2013)। तदानुसार, जेएसईबी ने 1 मार्च 2013 से 8 अप्रैल 2013 के बीच 83.16 एमयू ऊर्जा क्रय किया जिसका मुल्य ₹ 25.96 करोड़ था। यद्यपि, एपीएनआरएल से खरीदी गई ऊर्जा दक्षिणी क्षेत्र संचरण लाइन में व्यस्तता के कारण एपीपीसीसी को बेचा नहीं जा सका।

हमने लखापरीक्षा में पाया कि:

• अल्पावधि आधार पर क्रय किया गया 83.16 एमयू ऊर्जा का व्यापार नहीं हो सका, जिसमें से जेएसईबी ने 40.08 एमयू ऊर्जा का उपयोग किया तथा शेष 43.08 एमयू ऊर्जा पीटीसी के पास बैंक किया। ऊर्जा बैंक करने के लिए जेएसईबी को केन्द्रीय ऊर्जा नियामक आयोग (अंतर्राज्यीय संचरण में ओपेन एक्सेस) विनियम, 2008 के अनुसार संचरण (इंजेक्शन और निकास) शुल्क भुगतान करना था। साथ ही, जेएसईबी को ऊर्जा बैंक करने के लिए पीटीसी को व्यापारिक मार्जिन का भी भुगतान करना था। इस प्रकार, बिना संचरण लाइन की उपलब्धता सुनिश्चित किये व्यापारिक उद्देश्य से ऊर्जा क्रय के कारण, जेएसईबी को 43.08 एमयू ऊर्जा को बैंक करने के फलस्वरुप ₹ 1.15 करोड़ का संचरण शुल्क और ₹ 0.18 करोड़ व्यापारिक मार्जिन पर परिहार्य व्यय करना पड़ा।

• एपीएनआरएल के साथ समझौते के अनुसार, एपीएनआरएल द्वारा आपूर्तिकृत ऊर्जा का विपत्रीकरण सप्ताहिक आधार पर करना था। अगर जेएसईबी द्वारा बिपत्र प्राप्त करने के सात दिन के अन्दर भुगतान किया जाता तो दो प्रतिशत छूट जेएसईबी को उपलब्ध था और नियत तिथि से 30 दिन बाद शेष बकाया राशि का भुगतान करने पर 1.25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क एपीएनआरएल को भुगतेय था।

हमने लेखापरीक्षा में पाया कि एपीएनआरएल द्वारा मार्च 2013 और अप्रैल 2013 का विपत्र नियत तिथि (मार्च के 9, 16, 24 और 31 तथा 9 अप्रैल 2013) को जमा किया था और जेएसईबी ने जुन 2013 में ₹ 10 करोड़ तदर्थ भुगतान किया और शेष राशि ₹ 15.96 करोड़ का भुगतान अक्टूबर 2013 में किया गया और इस प्रकार, देर से भुगतान के कारण जेएसईबी ₹ 51.93 लाख का छूट प्राप्त करने में असफल रहा साथ ही ₹ 1.30 करोड़ का अतिरिक्त शुल्क का परिहार्य दायित्व का सृजन किया।

• जेएसईबी ने वैकल्पिक स्रोतों से दर की तुलना किये बिना एपीएनआरएल से ऊर्जा क्रय किया। यह देखा गया कि इसी अवधि के दौरान भारतीय ऊर्जा इक्सचेंज (आईईएक्स) में ₹ 2.23 प्रति युनिट की औसत दर पर ऊर्जा उपलब्ध था। ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार ने अल्पावधि आधार पर जेएसईबी द्वारा आईईएक्स से उपलब्ध सस्ती ऊर्जा को नजरअंदाज कर उच्च दर पर ऊर्जा क्रय करने के संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त किया (अप्रैल 2013)। इस प्रकार, जेएसईबी ने सस्ती उपलब्ध ऊर्जा पर विचार किये बिना उँची दर पर एपीएनआरएल से ऊर्जा क्रय किया,

परिणामत: ₹ 7.42 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। अत: जेएसईबी अपनी वित्तीय हितों के संरक्षण में असफल रहा।

जेयूवीएनएल ने उत्तर दिया कि एपीपीसीसी को बिक्री करने के लिए एपीएनआरएल से ऊर्जा क्रय किया गया था, परंतु, संचरण लाइन की व्यस्तता के कारण ऊर्जा को बेचा नहीं जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एपीपीसीसी से बिना क्रय आदेश या इच्छा पत्र प्राप्त किये ही जेएसईबी द्वारा फरवरी 2013 में व्यापार के लिए ऊर्जा क्रय का निर्णय लिया गया था। जेएसईबी को व्यापार हेतु ऊर्जा क्रय करने से पहले संचरण लाइन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए थी।

जेयूवीएनएल को व्यापार के लिए ऊर्जा क्रय करने के पहले योजना तैयार करना चाहिए तथा संचरण प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए।

3.1.6 पीटीसी से ऊर्जा क्रय के कारण परिहार्य व्यय

ग्रीष्मकाल में निर्विघ्न ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए जेएसईबी ने 100 मेगावाट ऊर्जा अल्पावधि आधार पर एक ऊर्जा व्यापारिक कंपनी पीटीसी से क्रय करने का निर्णय किया (जुन 2012)। तदानुसार जेएसईबी ने 16 जुन से 30 जुन 2012 की अवधि में पीटीसी से 33.84 एमयू ऊर्जा ₹ 17.43 करोड़ की लागत से (₹ 5.15 प्रति युनिट की दर से) क्रय किया।

पीटीसी द्वारा क्रय किये गये 33.84 एमयू में से, जेएसईबी ने 6.24 एमयू ऊर्जा का उपयोग 16 जुन से 18 जुन 2012 के बीच किया और शेष 27.60 एमयू जो कि 19 जुन से 30 जुन 2012 के बीच क्रय किया गया, ऊर्जा की उपलब्धता और माँग पर विचार करते हुए, बैंक किया गया। जेएसईबी ने इस बैंक किये गये ऊर्जा का उपयोग केवल नवम्बर 2012 में किया। इस प्रकार, अल्पावधि आधार पर बिना तत्काल आवश्यकता के ऊर्जा की क्रय के कारण, जेएसईबी को 27.60 एमयू ऊर्जा बैंक करना पड़ा, जिसपर ऊर्जा बैंकिंग के लिए ₹ 63.49 करोड़ संचरण शुल्क (इंजेक्शन और निकास) का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

जेयूवीएनएल ने उत्तर दिया कि टीवीएनएल में ऊर्जा औटेज के कारण ऊर्जा की अत्याधिक कमी थी और जब टीवीएनएल की युनिट चालु हुआ तो प्रतिवद्धित ऊर्जा को शीतकालीन मौसम में प्राप्त करने के लिए बैंक किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जून 2012 में टीवीएनएल में औटेज नहीं था और जून 2012 में औसत ऊर्जा उत्पादन (254.99 एमयू) था जो वर्ष 2012-13 में प्रतिमाह औसत ऊर्जा उत्पादन (243.5 एमयू) से अधिक था। इसके अलावा, जेएसईबी अल्पावधि आधार पर ऊर्जा क्रय करने से पहले ऊर्जा की आवश्यकता को मुल्यांकन करने में असफल रहा।

निष्कर्ष

• जेएसईबी ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान दामोदर घाटी निगम से अल्पावधि आधार पर 3467.99 एमयू ऊर्जा क्रय किया और इसी अवधि में जेएसईबी ने 2174.40 एमयू ऊर्जा की कम निकासी की जिसपर निम्नतर दर वसूली गई जिसके फलस्वरुप ₹ 231.24 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

• जेएसईबी द्वारा संचरण प्रभार एवं व्यापार मार्जिन के रुप में ₹ 1.96 करोड़ का परिहार्य व्यय व्यापार के लिए संचरण लाइन की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना 70.68 एमयू अल्पावधि ऊर्जा क्रय करने के फलस्वरुप ऊर्जा व्यापार पर (43.08 एमयू के संचरण शुल्क के लिए लागत ₹ 1.15 करोड़ तथा व्यापारिक मार्जिन के लिए ₹ 0.18 करोड़) एवं तत्काल जरुरत नहीं रहने के कारण (27.60 एमयू जिसका मुल्य ₹ 0.63 करोड़) हुआ।

• जेएसईबी ने कम दर पर उपलब्ध ऊर्जा पर विचार किये बिना उच्च दर पर एक निजी ऊर्जा उत्पादक से 83.16 एमयू ऊर्जा क्रय किया जिसके फलस्वरुप ₹ 7.42 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

3.2 पावर फैक्टर अधिभार की उगाही में देरी के कारण हानि

टैरिफ के अनुसार पावर फैक्टर अधिभार की उगाही में अत्याधिक देरी के कारण, एक कैप्टिव पावर प्लांट उपभोक्ता से ₹ 47.16 करोड़ का राजस्व अवसूलनीय रहे।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) ने उषा मार्टिन इंडस्टीज (यूएमआई) के साथ इसके कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) और अपने गम्हरिया ग्रिड सब-स्टेशन के तुल्यकालिक प्रचालन के लिए समझौता किया (मई 2002)। समझौते के अनुसार सीपीपी में उत्पन्न बिजली यूएमआई द्वारा उपयोग किया जाना था और अधिशेष बिजली को जेएसईबी की ऊर्जा प्रणाली में प्रवाहित करना था। साथ ही, जेएसईबी की ऊर्जा प्रणाली से ऊर्जा के आहरण के लिए यूएमआई का अनुबंध मांग 21.7 एमवीए तय किया गया। चूंकि सीपीपी में उत्पन्न बिजली यूएमआई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी अत: जेएसईबी द्वारा मीटर पठन के अनुसार जेएसईबी को यूएमआई से प्राप्त बिजली एवं जेएसईबी से यूएमआई को दिया गया बिजली के अंतर के लिये मासिक विपत्र भारित किया जा रहा था।

एक विद्युत प्रणाली में पावर फैक्टर (पीएफ) भार में प्रवाहित वास्तविक ऊर्जा (कि.वा) तथा सर्किट के आभासी ऊर्जा (केवीए) के अनुपात को कहते हैं और समान उपयोगी ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए कम पीएफ का भार, अधिक पीएफ के भार से अधिक धारा का उपयोग करता है। लागू टैरिफ के अनुसार, यदि किसी माह में उपभोक्ता का औसत पीएफ 0.85 से नीचे गिर जाता है तो, 0.85 से 0.60 तक प्रत्येक 0.01 की गिरावट तक अनुबंध माँग एवं ऊर्जा प्रभार के एक प्रतिशत पीएफ

अधिभार के रुप में उगाही किया जाना था और पीएफ के 0.60 से 0.30 तक प्रत्येक 0.01 की गिरावट पर दो प्रतिशत का पीएफ अधिभार लगाना था। इसी तरह, यदि औसत पीएफ 0.85 से अधिक रहा तो उपभोक्ता को पीएफ छूट मिलना था।

टैरिफ के प्रावधान के अनुसार, उपभोक्ता को शंट कैपासिटर उचित दशा में रखना था और इसके खराब होने की स्थिति में, उपभोक्ता द्वारा एक माह के भीतर इसके दोष को सुधार लेना था। पर्याप्त रेटिंग के शंट कैपासिटर का अनुक्षरण लगातार छह माह तक नहीं होने की स्थिति में जेएसईबी द्वारा ऊर्जा आपूर्ति के विच्छेद सहित अन्य कार्रवाई की जानी थी।

अप्रैल 2002 से मार्च 2008 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक माह में यूएमआई को आपूर्तित बिजली का औसत पीएफ 0.23 से 0.69 के बीच रहा जो 0.85 के स्वीकार्य सीमा से कम था। हालांकि, यूएमआई ने इस अवधि के दौरान शंट कैपासिटर के दोष को ठीक नहीं किया। कम पीएफ के वाबजूद जेएसईबी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और टैरिफ के प्रावधानों के अनुसार पीएफ अधिभार नहीं लगाया गया।

ग्रिड और सीपीपी उपभोक्ता के परिसर के निरीक्षण के लिए जेएसईबी ने एक समिति का गठन किया (मार्च 2008) जिसने पाया कि यूएमआई द्वारा स्थापित दोषपूर्ण और निष्क्रिय शंट कैपासिटर के कारण कम पीएफ था। यूएमआई द्वारा शंट कैपासिटर के पुन: स्थापना (जुलाई 2009) के बाद सितम्बर 2009 से पीएफ बढ़कर स्वीकार्य सीमा से अधिक हो गया जो सितम्बर 2009 से जुलाई 2014 की अवधि के दौरान 0.890 से 0.986 के बीच रहा।

हमने पाया की जेएसईबी ने केवल अगस्त 2008 के पीएफ अधिभार के लिए पूरक विपत्र जारी किया (सितम्बर 2010) जो यूएमआई द्वारा इस आधार पर भुगतान नहीं किया गया कि पीएफ अधिभार के भुगतान के लिए समझौते में कोई प्रावधान नहीं था। ये कथन उचित नहीं था क्योंकि जेएसईबी टैरिफ के अनुसार यूएमआई की मासिक विपत्र में वोल्टेज छूट दे रही थी। हालांकि, विपत्र वापस ले लिया गया और राशि को बाद के विपत्रों में बकाया के रूप में दावा नहीं किया गया। तत्पश्चात, जेएसईबी ने पीएफ अधिभार उगाही करने के मामले की जाँच करने के लिए एक समिति का गठन[8] किया (जनवरी 2012)। जिसने टैरिफ के प्रावधान के अनुसार यूएमआई पर पीएफ अधिभार लागू करने की सिफारिश की।

जेएसईबी मंडल द्वारा लागु टैरिफ के अनुसार पीएफ अधिभार लगाने का फैसला किया गया (दिसम्बर 2013) और पीएफ अधिभार किस अवधि के लिए लगाया जाये इस संबंध में निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष जेएसईबी को अधिकृत किया गया। इसके बाद, जेएसईबी का चार कंपनियों में पुर्नगठन हो गया (जनवरी 2014)। झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, जेएसईबी की उत्तरवर्ती कंपनी ने अप्रैल 2002 से

[8] अभियंता प्रमुख (अध्यक्ष), वित्त नियंत्रक - 2 (सदस्य) और ईएसई/कोल ब्लॉक (सदस्य सचिव)।

सितम्बर 2014 की अवधि के लिए ₹ 47.16 करोड़ की शुद्ध राशि का पूरक विपत्र यूएमआई पर भारित किया (अक्टूबर 2014) जिसमें ₹ 52.09 करोड़ का पीएफ अधिभार की माँग की गई और ₹ 4.93 करोड़ का पीएफ छूट दिया गया जो अभी तक अवसूलनिये थे (दिसम्बर 2014)।

इस प्रकार, जेएसईबी ने वर्ष 2002 से 2008 के दौरान कम पीएफ के लिए उपभोक्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहा और अप्रैल 2002 से सितम्बर 2014 की अवधि के लिए पी.एफ अधिभार की उगाही में अत्याधिक देरी हुई। इसके फलस्वरूप, ₹ 47.16 करोड़ का राजस्व अवसूलनीय रहा।

मामला झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जनवरी 2014 में जेएसईबी के पुर्नगठन के बाद गठित होल्डिंग कंपनी)/सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014); अनुस्मारक दिनांक 2 सितम्बर, 2014 और 16 दिसम्बर, 2014 के वाबजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2014)।

3.3 प्रत्याभूति राशि के गैर-वसूली के कारण हानि

जेएसईबी के प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहने के कारण उपभोक्ता से ₹ 66.95 लाख की प्रत्याभूती राशि और उस पर ₹ 50.13 लाख के क्षतिपूर्ति प्रभार अवसूलनीय रहे।

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी), (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2005 के अनुसार, जिस व्यक्ति को बिजली आपूर्ति या अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति स्वीकृत किया गया है उसे लाइसेंसीधारी वितरक को प्रत्याभूति राशि जमा करना है। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) ने उच्च तनाव विशेष सेवा (एचटीएसएस) उपभोक्ताओं के लिए प्रति केवीए ₹ 3150 की दर से प्रत्याभूति राशि तय की।

प्रत्याभूति राशि के भुगतान की सुविधा के लिए, जेएसईबी की शीर्ष परिषद ने यह अनुमोदित किया (जुलाई 2010) कि नये एचटीएसएस उपभोक्ता के प्रत्याभूति राशि के भुगतान अधिकतम चार किश्तों में 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से क्षतिपूर्ति प्रभार के साथ भुगतान कर सकता है। इसकी पहली किस्त प्रत्याभूति राशि के 40 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए एवं उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/नकदी के द्वारा करना था और शेष राशि का भुगतान तीन किस्तों में उत्तरदिनांकित चेक के द्वारा करना था। किसी भी उत्तरदिनांकित चेक के अनादरण की स्थिति में, बिजली लाइन बिना किसी सूचना के काट दिया जाना था।

जेएसईबी द्वारा (सितंबर 2011) एचटीएसएस उपभोक्ता का भार में 5,000 केवीए से 10,500 केवीए की वृद्धि स्वीकृत की गई जिसके लिए उपभोक्ता को ₹ 1.73 करोड़ का अतिरिक्त प्रत्याभूति राशि जमा करना था। जेएसईबी अध्यक्ष ने अतिरिक्त प्रत्याभूति राशि ₹ 1.73 करोड़ का भुगतान चार किश्तों में करने का अनुमोदन किया (दिसम्बर 2011)। तदनुसार, जेएसईबी ने उपभोक्ता के साथ समझौता किया

(दिसम्बर 2011) जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा प्रत्याभूति राशि का 40 प्रतिशत प्रथम किश्त ₹ 69.30 लाख के भुगतान के बाद विद्युत संबंध सक्रिय कर दिया गया (जनवरी 2012)। उपभोक्ता द्वारा ₹ 1.04 करोड़ की शेष राशि और ₹ 3.12 लाख के क्षतिपूर्ति प्रभार के तीन उत्तरदिनांकित चेक[9] जमा किए गए।

लेखों की जाँच के बाद हमने पाया (मार्च 2014) कि दूसरे और तीसरे किश्तों के पूर्व दिनांकित चेक जो क्रमश: ₹ 36.21 लाख और ₹ 35.69 लाख के थे, बैंक द्वारा अनादर कर दिए गए थे और चौथी किश्त का उत्तरदिनांकित चेक, जो ₹ 35.17 लाख का था, उसे जेएसईबी द्वारा बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा, उपभोक्ता की बिजली लाइन समझौते के प्रावधान के अनुसार जेएसईबी द्वारा उपभोक्ता के बिजली लाइन काटी नहीं गई और उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति पर्याप्त प्रत्याभूति राशि जमा किए बिना जारी रखा गया जिससे जेएसईआरसी विनियम का उल्लंघन हुआ।

लेखापरीक्षा के बताए जाने पर जेएसईबी ने ₹ 37 लाख की राशि उपभोक्ता से वसूली की (अप्रैल 2014)। हालांकि, ₹ 66.95 लाख की शेष प्रत्याभूति राशि और उसपर ₹ 50.13 लाख[10] के क्षतिपूर्ति प्रभार की वसूली नहीं हुई (दिसम्बर 2014)।

इस प्रकार, जेएसईबी द्वारा प्रत्याभूति राशि की वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाई नहीं करने के कारण ₹ 66.95 लाख की प्रत्याभूति राशि और ₹ 50.13 लाख के क्षतिपूर्ति प्रभार अवसूलनीय रहे।

मामला झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जनवरी 2014 में जेएसईबी के पुर्नगठन के बाद गठित होल्डिंग कंपनी)/सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2014); अनुस्मारक दिनांक 2 सितम्बर 2014 और 16 दिसम्बर 2014 के वाबजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2014)।

सरकारी कंपनियां

झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

3.4 आयकर पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए अग्रिम आयकर का भुगतान न करने और आयकर विवरणी दायर करने में देरी के कारण आयकर पर ₹ 28.82 लाख का परिहार्य भुगतान।

आयकर अधिनियम, 1961, (अधिनियम) की धारा 208 के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर देय है, यदि करदाता द्वारा इस तरह के देय कर की राशि वर्ष के दौरान दस हजार रूपये या इससे अधिक है। अधिनियम की धारा 234ए में यह

[9] उत्तरदिनांकित चेक दिनांक 29.02.2012 का ₹ 36,20,925, दिनांक 31.03.2012 का ₹ 35,68,950 और दिनांक 30.04.2012 का ₹ 35,16,975

[10] ₹ 42.10 लाख (₹ 103.95 लाख x 1.5 *प्रतिशत* x 27 माह, फरवरी 2012 से अप्रैल 2014 की तिथि तक) + ₹ 8.03 लाख (₹ 66.95 लाख x 1.5 *प्रतिशत* x 8 माह मई 2014 से दिसम्बर 2014 की तिथि तक)

प्रावधान है कि यदि किसी निर्धारण वर्ष की आयकर विवरणी नियत तिथि के बाद दाखिल की जाती है तो निर्धारित आय पर कर की राशि में से भुगतान किये गये अग्रिम कर और कर कटौती/स्रोत पर संग्रहित कर की राशि घटाने के बाद शेष कर राशि पर प्रत्येक माह एक प्रतिशत की दर से सधारण ब्याज भारित होता है।

साथ ही, अधिनियम के धारा 234बी निर्दिष्ट करती है कि जहाँ किसी वित्तीय वर्ष में, एक करदाता जो धारा 208 के अधीन अग्रिम कर की अदायगी के लिये उत्तरदायी है, कर अदायगी में चुक करता है या जहाँ करदाता द्वारा भुगतान किये गये अग्रिम कर निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम है, तो करदाता निर्धारित कर के विरुद्ध कम भुगतान किये गये अग्रिम आयकर पर अप्रैल की पहली तिथि से प्रत्येक माह के लिये एक प्रतिशत के दर से साधारण ब्याज के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, अधिनियम के धारा 234सी में यह प्रवधान है कि यदि करदाता अग्रिम कर के भुगतान में चुक करता है या देय कर के अग्रिम कर भुगतान 15 जुन, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक क्रमश: 15 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत से कम है तो करदाता उस कम जमा राशि पर प्रत्येक माह एक प्रतिशत के दर से साधारण ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

हमने पाया कि कंपनी के पास अग्रिम कर के भुगतान हेतू आय निर्धारण और वार्षिक बजट की तैयारी के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। इस कारण, अधिनियम की धारा 234बी और 234सी के प्रावधानों के आवश्यकतानुसार वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान कंपनी अग्रिम कर का भुगतान नियत तिथियों पर नहीं की। साथ ही, लेखों[11] के अंतिमीकरण में देरी के कारण, कंपनी इन वर्षों की आयकर विवरणी अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत नियत तिथियों में दायर नहीं कर सकी।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 17.47 लाख आयकर आकलित किया और मार्च 2013 में आयकर विवरणी दाखिल किया। वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिये कंपनी द्वारा आकलित कर क्रमश: ₹ 47.40 लाख और ₹ 58.53 लाख पर आयकर विवरणी मार्च 2014 में दाखिल की गयी थी। वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए अग्रिम कर का भुगतान नहीं करने और आयकर विवरणी दाखिल करने में देरी के परिणामस्वरुप, कंपनी को ₹ 28.82 लाख[12] के ब्याज का भुगतान नवम्बर 2012 और मार्च 2014 में करना पड़ा।

---

[11] कम्पनी ने अपने वर्ष 2010-11 के लेखों का 17 अक्टुबर 2012 को तथा वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 का 10 जनवरी 2014 को अंतिमिकृत किया।

[12] धारा 234ए के अंतर्गत - 2010-11 के लिये ₹ 1.46 लाख, 2011-12 के लिये ₹ 6.06 लाख, 2012-13 के लिये ₹ 2.32 लाख: धारा 234बी - 2010-11 के लिये ₹ 2.08 लाख, 2011-12 के लिये ₹ 8.08 लाख, 2012-13 के लिये ₹ 4.64 लाख, धारा 234सी -2010-11 के लिये ₹ 0.52 लाख, 2011-12 के लिये ₹ 1.70 लाख, 2012-13 के लिये ₹ 1.95 लाख।

कंपनी ने कहा (सितंबर 2014) कि लेखों के अंतिमीकरण में देरी के कारण आयकर विवरणी दाखिल करने में देरी हुई तथा उन्होनें वर्ष 2013-14 से अग्रिम कर के भुगतान करने की प्रक्रिया को अपनाया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रही और ₹ 28.82 लाख की परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा अग्रिम कर का सही समय पर भुगतान नहीं करने और आयकर विवरणी नियत तिथियों पर दाखिल नहीं करने के कारण अधिनियम की धारा 234ए, 234बी और 234सी के अंतर्गत ₹ 28.82 लाख के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014); अनुस्मारक दिनांक 2 सितम्बर, 2014 और 16 दिसम्बर 2014 के वाबजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2014)।

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

3.5 सेवा कर का परिहार्य भुगतान

कंपनी द्वारा केंदू पत्ती के विक्रेता से पर्यवेक्षण शुल्क और गोदाम किराया पर लगने वाले सेवा कर की वसूली में विफल रहने के कारण ₹ 15.63 लाख की गैर-वसूली रही।

वित्त अधिनियम, 2002 में संशोधित सेवा कर अधिनियम (अधिनियम) की धारा 65(105)(जेडजेडए) के अनुसार, संग्रहण और भंडारण की सेवाओं की लागत पर सेवा कर लगाने एवं वसूल करने का प्रावधान है। इसके अलावा, 1 जून 2007 से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अचल सम्पति पर किराये को सेवा कर[13] के दायरे में लाया गया। अधिनियम के अनुसार, जो व्यक्ति सेवा शुल्क की प्राप्ति के साथ कर योग्य सेवा प्रदान करता है, वह सरकार को सेवा कर के भुगतान के लिए बाध्य होगा।

भारत सरकार ने सेवा कर स्वेच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना (वीसीईएस), 2013 को प्रारंभ किया (मई 2013) जिसके तहत अक्टूबर 2007 से दिसंबर 2012 में देय या भुगतान योग्य सभी करों को 31 दिसंबर 2013 या इससे पहले नामित प्राधिकारी के समक्ष घोषणा के बाद 30 जून 2014 तक भुगतान करना था।

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (कंपनी), जो झारखण्ड में केंदू पत्ती के संग्रहण एवं क्रय के लिए झारखण्ड सरकार की अधिकृत एजेन्सी है, केंदू पत्ती के संग्रहण के मौसम के प्रारंभ होने से पहले निविदा के द्वारा केंदू पत्ती का अग्रिम विक्रय कर देता है। ज़बतक क्रेता द्वारा केंदू पत्ती के क्रय के लिए भुगतान की

[13] अधिसूचना संख्या - 23/2007 दिनांक 22 मई 2007 के अनुसार।

प्राप्ति न कर ली जाती है तबतक केंदू पत्ती को संग्रह कर कंपनी के गोदामों या अधिकृत निजी गोदामों में भंडारित किया जाता है।

निविदा की शर्तों एवं बंधेजों के अनुसार, क्रेता के द्वारा कंपनी को केंदू पत्ती के भंडारण और सुरक्षा के लिए पर्यवेक्षण शुल्क एवं कंपनी के स्वामित्व वाले गोदामों में केंदू पत्ती के भंडारण पर लगने वाले किराया सभी कर एवं शुल्क सहित भुगतान करना था। अत: कंपनी को केंदू पत्ती के क्रेता से पर्यवेक्षण शुल्क और गोदाम किराया पर सेवा कर की वसूली कर सरकार को जमा करना था।

हमने, हालांकि, पाया कि (मार्च 2014) कंपनी ने पर्यवेक्षण शुल्क और गोदाम किराया पर सेवा कर की वसूली केंदू पत्ती के क्रेता से नहीं की और सेवा कर राशि सरकार को जमा नहीं किया। अप्रैल 2008 से दिसंबर 2012 तक की अवधि के लिए कंपनी ने पर्यवेक्षण शुल्क और गोदाम किराया पर देय सेवा कर[14] देनदारी क्रमश: ₹ 14.21 लाख और ₹ 5.55 लाख का आकलन किया। कंपनी सेवा कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी थी अत: उसने वीसीईएस के तहत ₹ 19.76 लाख का सेवा कर का भुगतान किया (30 दिसंबर 2013)। कंपनी द्वारा अपने प्रमंडलीय प्रबंधको को क्रेताओं से सेवा कर की राशि की वसूली के निर्देश जारी करने पर ₹ 4.13 लाख की राशि वसूल हो सकी (दिसंबर 2014)।

कंपनी ने कहा (दिसंबर 2014) कि पर्यवेक्षण शुल्क और गोदाम किराया पर सेवा कर की प्रयोज्यता के बारे में उन्हे वीसीईएस के प्रारंभ के समय ही पता चला।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी सेवा कर अधिनियम की आवश्यकता को यथासमय पालन करने में विफल रहा जिसके कारण केंदू पत्ती के क्रेताओं से ₹ 15.63 लाख के सेवा कर की वसूली नहीं हो सकी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014); अनुस्मारक दिनांक 2 सितम्बर, 2014 और 16 दिसम्बर 2014 के वाबजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2014)।

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड

3.6 लिफ्ट की गैर-स्थापना के कारण निष्फल व्यय

कंपनी द्वारा प्रारंभिक कार्य को पूरा न करने और कार्य स्थल को सौंपने में विफल रहने के कारण लिफ्ट की अधिष्ठापन न होने के परिणामस्वरूप ₹ 84.57 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (कंपनी) ने तीन लिफ्ट के डिजाइन, निर्माण, निरीक्षण, आपूर्ति, स्थापना और उनके एक साल के संचालन और रखरखाव के लिए

[14] शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर सहित।

एक एजेंसी[15] को क्रय आदेश जारी किया (अगस्त 2004)। एक 884 किलोग्राम क्षमता की यात्री लिफ्ट की अधिष्ठापन स्वागत भवन में और दो टन क्षमता के दो माल ढुलाई सह यात्री लिफ्ट की स्थापना तेनुघाट वाष्प चलित ऊर्जा केन्द्र के दो बायॅलर स्थलों में की जानी थी। लिफ्ट का अनुबंधित मूल्य ₹ 1.41 करोड़ का था जिसमें ₹ 1.23 करोड़ सामग्री की आपूर्ति के लिए, ₹ 1.65 लाख इसके अधिष्ठापन और चालू करने के लिए और ₹ 16.71 लाख एक साल के संचालन एवं रखरखाव के लिए था।

क्रय आदेश में सामग्री की आपूर्ति पर अनुबंधित मूल्य के 20 प्रतिशत का भुगतान उसी राशि के 18 महीने तक के मान्य अवधि की बैंक गारंटी (वीजी) के विरुद्ध करना था, 70 प्रतिशत का भुगतान सामग्री की आपूर्ति पूरा करने पर और शेष 10 प्रतिशत का भुगतान 18 महीने की गारंटी अवधि के बाद करना था। सामग्री की आपूर्ति क्रय आदेश के 52 सप्ताह के भीतर यानी अगस्त, 2005 तक करनी थी। सामग्री की आपूर्ति के 16-20 सप्ताह यानि जनवरी 2006 तक लिफ्ट का स्थापना एवं चालू करने का कार्य पूरा कर लिया जाना था।

अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2014) से, हमने पाया कि एजेंसी ने ₹ 22.80 लाख मूल्य के सामग्री की आपूर्ति जनवरी 2006 और शेष सामग्री की आपूर्ति मार्च 2007 से अप्रैल 2007 के बीच की। एजेंसी द्वारा कंपनी को अनुरोध किया गया (सितंबर 2006) कि वह प्रारंभिक कार्यों यथा उपकरण गृह का निर्माण, लिफ्ट कुओं के दीवारों पर स्टील का परत चढ़ाना और लिफ्ट के लिये ऊर्जा आपूर्ति हेतू विद्युत कार्यों को पूरा करना, जो क्रय आदेश के अनुसार उसके कार्य क्षेत्र में नहीं थे।

कंपनी ने ₹ 0.44 लाख की लागत से स्वागत भवन में 884 किलोग्राम लिफ्ट का प्रारंभिक कार्य पूरा किया (जनवरी 2008) और लिफ्ट को स्थापित किया (फरवरी 2008)। यद्यपि प्रथम बॉयलर स्थल में प्रारंभिक कार्य मार्च से सितंबर 2008 के दौरान ₹ 2.36 लाख की लागत से हुए, लिफ्ट कुओं में स्टील का परत चढ़ाने का कार्य पूरा नहीं किया गया था और लिफ्ट के स्थापना के लिए कार्यस्थल एजेंसी को नहीं सौंपा गया था। इसके अलावा, दुसरा बॉयलर स्थल में प्रांरभिक कार्य को पूरा नहीं किया गया था।

इस तरह, कंपनी द्वारा प्रारंभिक कार्य को पूरा करने और दो लिफ्ट की स्थापना के लिए कार्यस्थलों को न सौंपने के कारण लिफ्टों की स्थापना इनके आपूर्ति के सात वर्ष बाद भी नहीं हो सकी। इसके अलावा, क्रय आदेश के अनुसार विनिर्माण दोष, दोषपूर्ण कारीगरी, दोषपूर्ण सामग्री और असंतोषजनक सेवाओं के विरूद्ध आपूर्तित सामग्री की गांरटी अक्टूबर 2008 में समाप्त हो गई है। कंपनी ने सामग्री की आपूर्ति

[15] एस्सार स्काई मार्क (इंडिया) प्रा. लि., कोलकाता।

के लिए एजेंसी को ₹ 1.09 करोड़ का भुगतान किया जिसमें से ₹ 84.57 लाख दो लिफ्टों पर व्यय हुए जो अभी तक स्थापित नहीं हो पाए (दिसंबर 2014)।

सरकार ने (जुलाई 2014) लिफ्ट की गैर-स्थापना के कारणों के रूप में समरूप कार्यों के क्रियान्वयन के लिए टीटीपीएस के अधिकारियों में विशेषज्ञता का अभाव और कार्यस्थल के प्रभारी अधिकारियों के लगातार स्थानांतरण को जिम्मेदार ठहराया। इसके आगे यह भी कहा गया कि लिफ्ट की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यो की पहचान, एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से कर ली गई है और लिफ्ट की स्थापना दिसंबर 2014 तक पूरी कर ली जायेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी, प्रारंभिक कार्यों को पूरा करने और कार्यस्थल को एजेंसी को सौंपने में विफल रही जिसके कारण लिफ्टों की स्थापना इनके आपूर्ति के सात वर्ष के बाद भी नहीं हुई। सरकार ने उत्तर में कहा था कि लिफ्टों की स्थापना दिसंबर 2014 तक पूरी नहीं हो पाई थी।

इस प्रकार, लिफ्टों के क्रय पर किये गए ₹ 84.57 लाख निष्फल रहे और लिफ्टों से प्राप्त होने वाले निर्धारित लाभों को नहीं लिया जा सका

सामान्य

3.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

3.7.1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में रखे गए खातों एवं अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण के साथ प्रारम्भ की गई लेखापरीक्षा संविक्षा की प्रक्रिया के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि कार्यपालिका से इनपर उपयुक्त उत्तर ससमय प्राप्त किया जाए।

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान मंडल के पटल पर क्रमश: अगस्त 2010, अगस्त 2011, सितम्बर 2012, जुलाई 2013, एवं मार्च 2014 में प्रस्तुत किये गये थे। वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल एवं वाणिज्यिक) और वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा.क्षे.उ.) में तीन विभागों के अंतर्गत नौ सा.क्षे.उ. से संबंधित अठाइस कंडिकायें/निष्पादन लेखापरीक्षायें सम्मिलित किये गये थे जिनपर सरकार से 30 सितम्बर 2014 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं जैसा कि **तालिका-3.3** में इंगित किया गया है। विभागवार विश्लेषण ***परिशिष्ट-3.1*** में दिया गया है।

तालिका - 3.3

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा	संबंधित विभागों की संख्या	कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2008-09	5	2	5
2009-10	7	2	7
2010-11	4	3	4
2011-12	6	8	6
2012-13	6	3	6
कुल	**28**		**28**

सार्वजनिक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.7.2 वर्ष 2001-02 से 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल एवं वाणिज्यिक) और वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा.क्षे.उ.) में, 45 कंडिकाएं तथा दस निष्पादन लेखापरीक्षाएं सम्मिलित की गयी थी। इनमें से, 30 सितम्बर 2014 तक सात कंडिकाओं तथा चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा चर्चा की गयी थी। वर्ष 2001-02 से 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के तीन कंडिकाओं और दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं से संबंधित तीन उप-कंडिकाओं के संबंध में कोपू ने अनुशंसायें की थी।

कोपू की कार्यचालन नियमावली के अनुसार संबंधित विभागों को कोपू की अनुशंसाओं पर कार्रवाई टिप्पणियाँ (एटीएन) तीन माह के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि, विभागों ने कोपू की उपरोक्त अनुशंसाओं पर एटीएन उपलब्ध नहीं कराए थे।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

3.7.3 लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए तथा तत्काल निस्तारित न हुए लेखापरीक्षा अवलोकनों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्य सरकार के संबंधित विभागों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) के माध्यम से संसूचित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर इनके प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है। 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मार्च 2014 तक निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से परिलक्षित होता है कि 421 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 1425 कंडिकाएं सितम्बर 2014 के अंत तक अनिस्तारित रही। 30 सितम्बर 2014 के अंत तक विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों का विवरण ***परिशिष्ट-3.2*** में दिया गया है।

इसी प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यचालन पर प्रारूप कंडिका एवं निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव एवं प्रधान सचिव, वित्त को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा छः सप्ताह के अन्दर तथ्यों एवं आँकड़ों की

पुष्टि एवं उन पर उनकी टिप्पणियों की अपेक्षा सहित प्रेषित की जाती है। मई से अगस्त 2014 के दौरान संबंधित विभागों को अग्रसारित छः प्रारूप कंडिकाओं (एक दीर्घ प्रारूप कंडिका सहित) एवं एक निष्पादन लेखापरीक्षा में से, सरकार ने केवल निष्पादन लेखापरीक्षा और एक प्रारूप कंडिका का उत्तर दिया था (दिसंबर 2014); पाँच प्रारूप कंडिकाओं (एक दीर्घ प्रारूप कंडिका सहित) का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं जिसका विवरण ***परिशिष्ट-3.3*** में है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि (क) उन कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया विद्यमान है जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा कोपू की अनुशंसाओं पर कार्रवाई टिप्पणियाँ निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रेषित करने में विफल रहे हैं, (ख) एक समयबद्ध कार्यसूची के अनुसार हानि/बकाया अग्रिम/अधिभुगतान को वसूल करने की कार्यवाही हो और (ग) लेखापरीक्षा अवलोकनों के उत्तर देने की प्रणाली को सुदृढ़ कर दिया गया है।

मृदुला सप्रू

राँची **(मृदुला सप्रू)**
दिनांक : **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**
झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक : **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1.1

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम के संबंध में 31 मार्च 2014 को प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋण तथा मानवशक्ति को दर्शाती अद्यतन विवरणी

(कंडिका 1.7 में संदर्भित)

(कॉलम 5(क) से 6(घ) के आँकड़े ₹ लाख में)

क्र.सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समाहित करने का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2012-13 के अंत में बकाया ऋण				2013-14 के ऋण अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानवशक्ति (31.03.2014 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं संबद्ध													
1.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन एवं पर्यावरण	27.3.2002	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	246
2.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड	जल संसाधन	22.3.2002	500.00	-	-	500.00	525.00	-	-	525.00	1.05:1	199
प्रक्षेत्रवार कुल				**505.00**	**-**	**-**	**505.00**	**525.00**	**-**	**-**	**525.00**	**1.04:1**	**445**
आधारभूत संरचना													
3.	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	15.12.2004	1200.00 (200.00)	-	-	1200.00 (200.00)	-	-	-	-	-	13
4.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड	गृह	13.03.2002	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	48
5.	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	योजना एवं विकास	23.01.2003	3500.00 (3450.00)	-	-	3500.00 (3450.00)	-	-	-	-	-	10
प्रक्षेत्रवार कुल				**4900.00 (3650.00)**	**-**	**-**	**4900.00 (3650.00)**		**-**	**-**	**-**	**-**	**71**
विनिर्माण													
6.	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	23.08.2006	1000.00	-	-	1000.00	-	-	450.00	450.00	0.45:1	275*
7.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास	खान एवं भूतत्व	07.05.2002	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	342
	निगम लिमिटेड												

क्र.सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समाहित करने का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी$				2012-13 के अंत में बकाया ऋण				2013-14 के ऋण अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानवशक्ति (31.03. 2014 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
प्रक्षेत्रवार कुल				**1200.00**	**-**	**-**	**1200.00**	**-**		**450.00**	**450.00**	**0.38:1**	**617**
ऊर्जा													
8.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	26.11.1987	10500.00	-	-	10500.00	66589.87	-	-	66589.87	6.34:1	608
9.	कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड	ऊर्जा	19.09.2008	-	-	5.00	5.00	-	-	1195.75	1195.75	239.15:1	❖
10.	झारखण्ड उर्जा विकास निगम लिमिटेड	ऊर्जा	16.09.2013	840.00	-	-	840.00	-	-	-	-	-	-
11.	झारखण्ड उर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	ऊर्जा	23.10.2013	-	-	210.00+	210.00	-	-	-	-	-	-
12.	झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड	ऊर्जा	23.10.2013	-	-	210.00+	210.00	-	-	-	-	-	-
13.	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	ऊर्जा	23.10.2013	-	-	210.00+	210.00	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार कुल				**11340.00**	**-**	**635.00**	**11975.00**	**66589.87**	**-**	**1195.75**	**67785.62**	**5.67:1**	**608**
सेवायें													
14.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम	पर्यटन	22.3.2002	325.00 (25.00)	-	-	325.00 (25.00)	-		-	-	-	93
15.	झारखण्ड राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड	उत्पाद एवं निषेध	26.11.2010	500.00 (300.00)	-	-	500.00 (300.00)	-	-	-	-	-	56
16.	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	लोक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	18.06.2010	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	222
17.	झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड	कल्याण	15.03.2012	#	-	-	-	-	-	-	-	-	5
प्रक्षेत्रवार कुल				**1325.00 (325.00)**	**-**	**-**	**1325.00 (325.00)**	-	**-**	**-**	-	**-**	**376**

क्र.सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समाहित करने का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी$				2012-13 के अंत में बकाया ऋण				2013-14 के ऋण अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानवशक्ति (31.03. 2014 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
कुल (क) (प्रक्षेत्रवार कुल सभी कार्यरत सरकारी कम्पनियां) (अंश आवेदन राशि)				**19270.00 (3975.00)**		**635.00**	**19905.00 (3975.00)**	**67114.87**	**-**	**1645.75**	**68760.62**	**3.45:1**	**2117**
(ख) कार्यरत सांविधिक निगम													
ऊर्जा													
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	ऊर्जा	20.3.2001	-	-	-	-	565815.00	-	19521.57	585336.57	-	6043
प्रक्षेत्रवार कुल				**-**	**-**	**-**	**-**	**565815.00**	**-**	**19521.57**	**585336.57**	**-**	**6043**
कुल (ख) (प्रक्षेत्रवार कुल सभी कार्यरत सांविधिक निगम)				**-**	**-**	**-**	**-**	**565815.00**	**-**	**19521.57**	**585336.57**	**-**	**6043**
सकल योग (क+ख) (अंश आवेदन राशि)				**19270.00 (3975.00)**	**-**	**635.00**	**19905.00 (3975.00)**	**632929.87**	**-**	**21167.32**	**654097.19**	**32.86:1**	**8160**
(ग) अकार्यरत सरकारी कम्पनियां		शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) अकार्यरत सांविधिक निगम		शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग+घ) (अंश आवेदन राशि)				**19270.00 (3975.00)**	**-**	**635.00**	**19905.00 (3975.00)**	**632929.87**	**-**	**21167.32**	**654097.19**	**32.86:1**	**8160**

(स्रोत: सरकारी कम्पनी/सांविधिक निगम द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

कॉलम 5(क) एवं 5(घ) के कोष्ठक में आँकड़े अंश आवेदन राशि को दर्शाते है

@ सांविधिक निगम झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को (जनवरी 2014) एक होल्डिंग कम्पनी झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) और तीन सहायक कम्पनियों झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल), झारखण्ड ऊर्जा संचरन निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) और झारखण्ड बिजली वितरन निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) में पुन: संगठित कर दिया गया।

$ प्रदत्त पूँजी में अंश आवेदन राशि शामिल है।

❖ कंपनी के कार्य जेएसईबी के अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाते है।

सरकार द्वारा ₹ 1.00 लाख अभिदत्त पुँजी अभी तक अप्राप्त है।

* आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्त मानवशक्ति (239) शामिल है।

+ होल्डिंग कम्पनी द्वारा भुगतान किया गया।

परिशिष्ट-1.2

वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य अंश पूँजी, ऋण, अनुदान तथा सहाय्य, प्राप्त प्रत्याभूति, बकायों की माफी, अपलिखित ऋण तथा अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण तथा मार्च 2014 की समाप्ति पर प्रत्याभूति प्रतिबद्धता, को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 1.10 में संदर्भित)

(कॉलम 3(क) से 6(घ) के आँकड़े ₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंश पूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त सहाय्य एवं अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूति और वर्ष के अंत में प्रतिबद्धता		वर्ष के दौरान बकाये की माफी			
		अंश पूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	अपलिखित की गई पुनः अदायगी ऋण	अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण	माफ किये गये ब्याज/दण्ड ब्याज	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
(क)	**कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ**												
आधारभूत संरचना													
1.	जीआरडीए	1000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	जीडको	200.00											
प्रक्षेत्रवार कुल		**1200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कृषि													
3.	झालको	-	-	-	571.00	-	571.00	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार कुल		**-**	**-**	**-**	**571.00**	**-**	**571.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
सेवायें													
4.	जेटीडीसी	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार कुल		**25.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.	झारखण्ड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड	840.00											
प्रक्षेत्रवार कुल		**840.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल (क) प्रक्षेत्रवार सभी कार्यरत सरकारी कम्पनियां		**2065.00**	**-**	**-**	**571.00**	**-**	**571.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(ख) कार्यरत सांविधिक निगम													
ऊर्जा													
1.	जेएसईबी	-	17534.00	-	96709.00	-	96709.00	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार कुल		**-**	**17534.00**	**-**	**96709.00**	**-**	**96709.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल (ख) प्रक्षेत्रवार सभी कार्यरत सांविधिक निगम		-	**17534.00**	**-**	**96709.00**	**-**	**96709.00**	**-**	**-**	-	-	-	-
कुल योग (क+ख)		**2065.00**	**17534.00**	**-**	**97280.00**	**-**	**97280.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(स्रोत: सरकारी कम्पनी/सांविधिक निगम द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

परिशिष्ट - 1.3

अद्यतन वर्ष के लिए तैयार लेखे के अनुसार सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(कंडिका 1.14 में संदर्भित)

(कॉलम 5(क) से (11) के आँकड़े ₹ लाख में)

क्र.सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे तैयार किये गये	निवल लाभ(+)/हानि(-)				आवर्त	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचयी लाभ (+)/ हानि (-)	विनियोजित पूँजी@	विनियोजित पूँजी से प्रतिफल$	विनियोजित पूँजी से प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(क)	**कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ**													
कृषि एवं संबद्ध														
1.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2014-15	778.03	-	22.34	755.69	10024.76	26.93	5.00	2444.71	2449.71	755.69	30.85
2.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड	2009-10	2013-14	(-)133.39	-	0.73	(-)134.12	71.02	36.28	500.00	(-)1040.86	(-)15.86	(-)134.12	-
प्रक्षेत्रवार कुल				**644.64**	**-**	**23.07**	**621.57**	**10095.78**	**63.21**	**505.00**	**1403.85**	**2433.85**	**621.57**	**25.54**
आधारभूत संरचना														
3.	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2014-15	120.60	-	1.90	118.70	16.44	8.90	1000.00 (100.00)	324.28	1324.28	118.70	8.96
4.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	314.10	-	6.43	307.67	324.53	-	200.00	1879.78	2079.78	307.67	14.79
5.	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	2012-13	2013-14	138.17	-	4.00	134.17	-	-	2500.00 (2450.00)	870.90	3370.90	134.17	3.98
प्रक्षेत्रवार कुल				**572.87**	**-**	**12.33**	**560.54**	**340.97**	**8.90**	**3700.00 (2550.00)**	**3074.96**	**6774.96**	**560.54**	**8.27**

क्र.सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे तैयार किये गये	निवल लाभ(+)/हानि(-)				आवर्त	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचयी लाभ (+)/ हानि (-)	विनियोजित पूँजी@	विनियोजित पूँजी से प्रतिफल$	विनियोजित पूँजी से प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विनिर्माण														
6.	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2014-15	331.48	201.77	92.59	37.12	3574.55	-	1000.00	100.27	1100.27	238.89	21.71
7.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2013-14	1409.10	-	15.00	1394.10	5190.59	-	200.00	9824.24	10024.24	1394.10	13.91
प्रक्षेत्रवार कुल				**1740.58**	**201.77**	**107.59**	**1431.22**	**8765.14**	**-**	**1200.00**	**9924.51**	**11124.51**	**1632.99**	**14.68**
ऊर्जा														
8.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	2001-02^	2014-15	9486.70	9021.68	9281.68	(-)8816.66	22400.06	2211.00	10000.00	(-)48590.76	117611.21	205.02	0.17
9.	कर्णपूरा ऊर्जा लिमिटेड	$$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	$$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	$$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	$$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	$$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार कुल				**9486.70**	**9021.68**	**9281.68**	**(-)8816.66**	**22400.06**	**2211.00**	**10000.00**	**(-)48590.76**	**117611.21**	**205.02**	**0.17**
सेवायें														
14.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2004-05	2012-13	15.61	-	4.19	11.42	103.38	1.47	50.00	44.30	94.30	11.42	12.11
15.	झारखण्ड राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	35.54	1.36	0.89	33.29	3283.98	-	500.00 (300.00)	33.29	533.29	34.65	6.50

क्र.सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे तैयार किये गये	निवल लाभ(+)/हानि(-)				आवर्त	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचयी लाभ (+)/ हानि (-)	विनियोजित पूँजी@	विनियोजित पूँजी से प्रतिफल$	विनियोजित पूँजी से प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16.	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	$$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड	$$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार कुल				**51.15**	**1.36**	**5.08**	**44.71**	**3387.36**	**1.47**	**550.00 (300.00)**	**77.59**	**627.59**	**46.07**	**7.34**
कुल (क) क्षेत्रवार सभी कार्यरत सरकारी कम्पनियां				**12495.94**	**9224.81**	**9429.75**	**(-)6158.62**	**44989.31**	**2284.58**	**15955.00 (2850.00)**	**(-)34109.85**	**138572.12**	**3066.19**	**-**
(ख) कार्यरत सांविधिक निगम														
ऊर्जा														
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	2012-13	2014-15	(-)174828.43	78337.52	13589.68	(-)266755.63	261595.52	57250.00	-	(-)1195770.40	(-)11181.47	(-)188418.11	-
प्रक्षेत्रवार कुल				**(-)174828.43**	**78337.52**	**13589.68**	**(-)266755.63**	**261595.52**	**57250.00**	**-**	**(-)1195770.40**	**(-)11181.47**	**(-)188418.11**	**-**
कुल (ख) प्रक्षेत्रवार सभी कार्यरत सांविधिक निगम				**(-)174828.43**	**78337.52**	**13589.68**	**(-)266755.63**	**261595.52**	**57250.00**	**-**	**(-)1195770.40**	**(-)11181.47**	**(-)188418.11**	**-**
कुल योग (क+ख)				**(-)162332.49**	**87562.33**	**23019.43**	**(-)272914.25**	**306584.83**	**59534.58**	**15955.00 (2850.00)**	**(-)1229880.24**	**127390.65**	**(-)185351.92**	**-**

टिप्पणी: झारखण्ड राज्य में कोई अकार्यरत सरकारी कंपनी/सांविधिक निगम नहीं है।

लेखा टिप्पणी के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षक एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का निवल प्रभाव शामिल है, और लाभ में वृद्धि/हानि में कमी को (+) तथा लाभ में कमी/हानि में वृद्धि को (-) से दर्शाया गया है।

@ कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची - VI के आवश्यकतानुसार विनियोजित पूँजी अंशधारक निधि तथा दिर्घावधि ऋण के योग को दर्शाती है। जेएसईबी के संर्दभ में विनियोजित पूँजी, निवल अचल परिसंपत्तियों, प्रगतिशील पूँजीगत व्यय और कार्यशील पूँजी के योग को दर्शाती है क्योंकि अनुसूची - V जेएसईबी पर लागु नहीं है

$ निवेशित पूँजी से प्रतिफल लाभ एवं हानि लेखे में भारित ब्याज तथा लाभ को जोड़कर निकाली गई है।

$$ कम्पनी ने अभी तक पहला लेखा जमा नहीं किया है।

^ टी.वी.एन.एल. से वर्ष 2002-03 से 2005-06 के लेखे प्राप्त हो गये थे, जो सितम्बर 2014 तक अंतिमीकृत नहीं हुये थे, जिसे अंतिमीकृत होना है।

परिशिष्ट-1.4

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के वित्तीय परिणाम को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 1.14 में संदर्भित)

(राशि: ₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
क. सम्पत्ति			
सकल ब्लॉक	2351.60	2500.79	3345.95
घटाव: मूल्य ह्रास	1115.61	1232.97	1369.80
निवल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	1235.99	1267.82	1976.15
चालु पूँजीगत व्यय	1813.99	1752.26	1920.40
सम्पत्ति उपयोग में नहीं	2.29	2.29	2.29
निवेश	200.27	179.07	373.16
कुल चालू सम्पत्ति	4740.45	5450.15	6718.99
घाटा	6079.12	9290.15	11957.70
कुल (क)	**14072.11**	**17941.74**	**22948.69**
ख. दायित्व			
कार्यशील पूँजी हेतु उधार	218.98	274.93	305.53
पूँजीगत दायित्व पर बकाया भुगतान	4481.13	5383.28	6123.01
पूँजीगत दायित्व	210.10	205.58	182.89
राज्य सरकार से प्राप्त निधि	2958.65	2743.16	3183.19
योगदान, अनुदान और सहाय्य	1570.38	1676.22	2426.73
कुल चालू दायित्व	4632.87	7658.57	10727.34
कुल (ख)	**14072.11**	**17941.74**	**22948.69**
ग. विनियोजित पूँजी*	**3157.56**	**811.66**	**(111.80)**

*** विनियोजित पूँजी, निवल अचल परिसंपत्तियों (प्रगतिशील पूँजीगत व्यय सहित) और कार्यशील पूँजी के योग को दर्शाता है**

परिशिष्ट - 1.5

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकारी परिणाम को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 1.14 में संदर्भित)

(राशि: ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.		विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
1.	क)	राजस्व प्राप्तियाँ	2010.69	2229.05	2615.96
	ख)	राजस्व सहाय्य, अनुदान एवं अन्य आय	652.85	961.23	1377.84
	ग)	कुल	2663.54	3190.28	3993.80
2.		राजस्व व्यय (पूंजीगत अपलिखित व्यय, अमूर्त परिसम्पत्तियों रहित परंतु मूल्य ह्रास एवं ब्याज को छोड़कर)*	3036.58	3531.75	4149.90
3.		वर्ष का सकल आधिक्य (+)/घाटा (-) (ना.)	(-) 373.04	(-) 341.47	(-)156.10
4.		गत वर्ष से संबंधित समायोजन (ना.)	97.26	(-) 2252.70	(-)1520.03
5.		वर्ष का अंतिम सकल आधिक्य (+)/ घाटा (-) (3+4)	(-) 275.78	(-) 2594.17	(-)1676.13
6.		विनियोग			
	क)	ह्रास	50.99	117.37	135.90
	ख)	पूंजी/ऋण पर ब्याज	554.67	622.13	899.98
	ग)	अन्य ऋण, अग्रिम आदि पर ब्याज	158.61	122.64	116.60
	घ)	ऋण पर कुल ब्याज (ख-ग)	396.06	499.49	783.38
7.		राज्य सरकार से प्राप्त सहाय्य के लेखांकन से पहले आधिक्य (+)/घाटा(-) {5-6क-6घ-1ख(केवल अनुदान)}	(-) 1172.83	(-) 3961.03	(-)3695.41
8.		शुद्ध आधिक्य (+)/घाटा(-) (5-6क-6घ)	(-) 722.83	(-) 3211.03	(-)2595.41
9.		विनियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल** (8+6घ)	(-) 326.76	(-) 2711.54	(-)1812.03
10.		विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल का प्रतिशत***	-	-	-

नोट: * राजस्व व्यय में ह्रास और ऋण पर ब्याज शामिल नहीं हैं।

** विनियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल, शुद्ध आधिक्य/घाटा जोड़ लाभ हानि खाता पर भारित कुल ब्याज (घटाव पूंजी पर ब्याज) को दर्शाता है।

*** विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल का प्रतिशत आकलित नहीं किया गया है क्योंकि सभी वर्षो में घाटा था।

परिशिष्ट - 1.6

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया हैं, में किए गए निवेश को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 1.20 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	सा.क्षे.उ. का नाम	वर्ष जबतक लेखाओं को अंतिमीकृत किया गया है	अद्यतन अंतिमीकृत किए गए लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी*	अवधि जिस दौरान लेखें बकाया है	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में, जिसके लेखे बकाया है, किए गए निवेश			
					अंश पूँजी	ऋण	अनुदान	अन्य
कार्यरत सरकारी कम्पनी/निगम								
क. सरकारी कम्पनियाँ								
1.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड	2009-10	500.00	2010-11	-	-	-	-
				2011-12	-	-	-	-
				2012-13	-	-	542.00	
				2013-14	-	-	571.00	-
2.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम	2004-05	50.00	2005-06	25.00	-	-	-
				2006-07	-	-	-	-
				2007-08	-	-	-	-
				2008-09	-	-	-	-
				2009-10	25.00	-	-	-
				2010-11	50.00	-	-	-
				2011-12	100.00	-	-	-
				2012-13	50.00	-	-	-
				2013-14	25.00	-	-	-
3.	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	2012-13	2500.00 (2450.00)	2013-14	1000.00			
4.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	2005-06	10500.00	2006-07	-	800.00	-	-
				2007-08 to 2013-14	-	-	-	-
5.	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	-	-	2010-11	500.00	-	9400.00	
		-	-	2011-12	-	-	24396.00	
		-	-	2012-13	-	-	13500.00	-
		-	-	2013-14	-	-	-	-
6.	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2012-13	1000.00 (100.00)	2013-14	200.00	-	-	-
	कुल (क)		**14550.00 (2550.00)**		**1975.00**	**800.00**	**48409.00**	**-**
ख. सांविधिक निगम								
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	2012-13	-	2013-14	-	17534.00	96709.00	-
	कुल (ख)				**-**	**17534.00**	**96709.00**	**-**
	कुल (क)+(ख)		**14050.00 (2550.00)**		**1975.00**	**18334.00**	**145118.0**	**-**

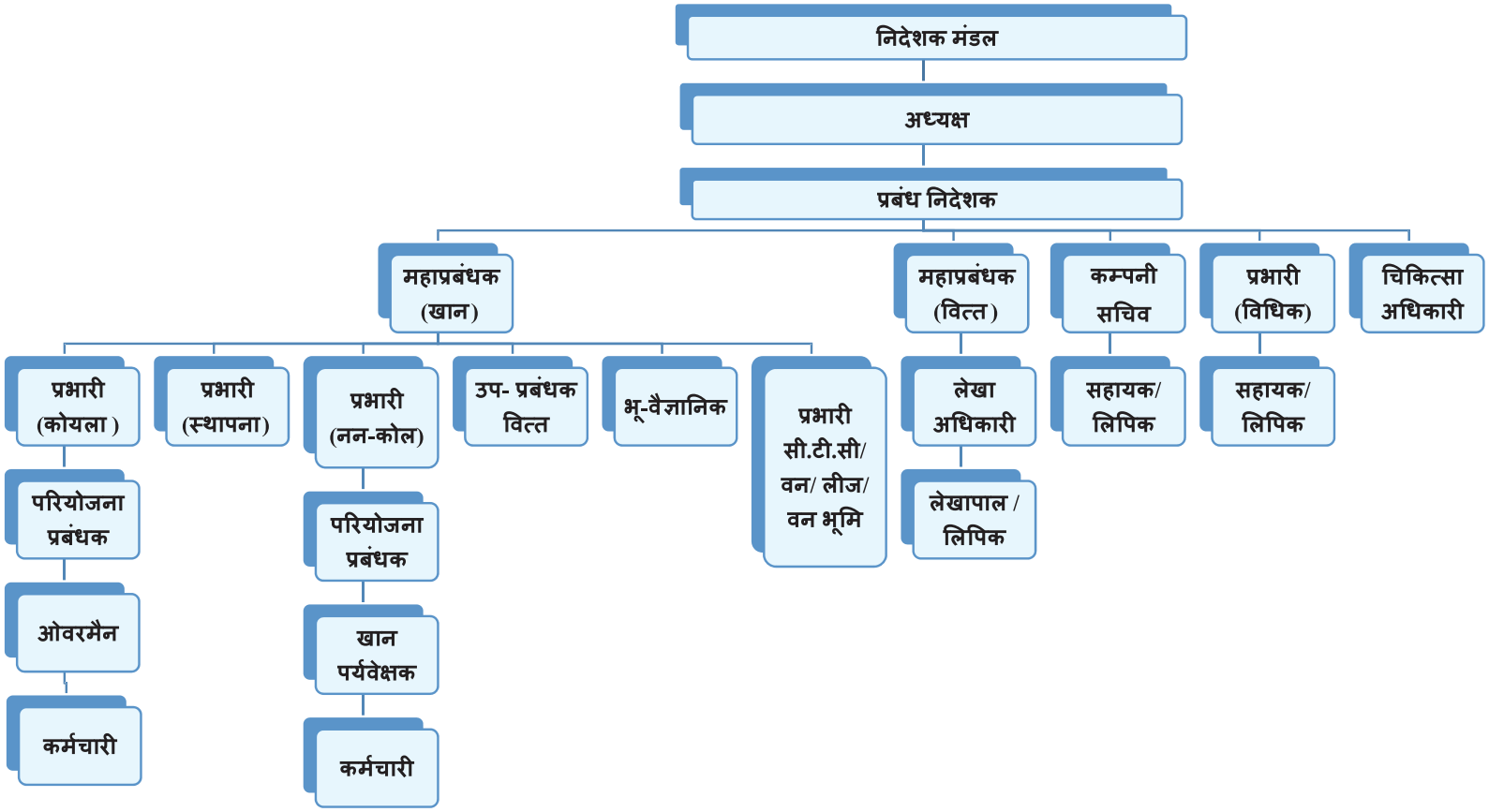
(स्रोत: सरकारी कम्पनी/सांविधिक निगम द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

* कोष्ठक में आँकड़े अंश आवेदन राशि को दर्शाते है)

परिशिष्ट - 2.1

झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का संगठनात्मक ढाँचा

(कंडिका 2.2 में संदर्भित)



परिशिष्ट - 2.2

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान कंपनी के कार्यकारी परिणाम को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 2.6 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनन्तिम					
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
क. आय						
खनिजों का विक्रय	51.27	50.08	19.00	0.69	0.07	121.11
कोयला व्यापार	52.26	45.91	61.57	93.16	62.34	315.24
अर्जित ब्याज	10.64	10.87	10.45	10.61	12.00	54.57
कुल	**114.17**	**106.86**	**91.02**	**104.46**	**74.41**	**490.92**
ख. व्यय						
कोयला व्यापार	50.09	43.92	59.08	89.55	59.97	302.61
उत्पादन (खनिज)	18.37	16.88	5.66	0.25	0.07	41.23
रॉयल्टी/नियत लगान	4.97	4.58	1.83	0.20	0.18	11.76
अन्य खर्च	11.39	13.66	13.55	12.16	12.04	62.80
कुल	**84.82**	**79.04**	**80.12**	**102.16**	**72.26**	**418.40**
ग. लाभ/हानि	**29.35**	**27.82**	**10.90**	**2.30**	**2.15**	**72.52**

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार)

परिशिष्ट - 2.3

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के माइलस्टोन के लक्ष्य के तुलना में उपलब्धि को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 2.11 में संदर्भित)

कोयला ब्लोकों का नाम ↓	माह की संख्या में माइलस्टोन →	आबंटन की तिथि ↓	जियोलोजिकल रिपोर्ट का क्रय (जीआर)	जी.आर. की तैयारी[1]	खनन योजना का अनुमोदन	वन अनापत्ति	पर्यावरण अनापत्ति	खनन पट्टा प्रदान करना	भूमि अधिग्रहण	परिचालन हेतु अनुमति	उत्पादन[2]
		→	आवंटन का 1.5 माह	आवंटन का 27 माह	जीआर का 8 माह	जीआर का 18 माह	जीआर का 18 माह	जीआर का 24 माह	जीआर का 36 माह	जीआर का 41/53 माह	जीआर का 42/54 माह
सरकारी कम्पनी व्यवस्था के तहत कोयला ब्लॉकों का आंवटित											
पतरातु (भूमिगत[3])	अनुसूचित तिथि	-	-	25.09.09	25.05.10	25.03.11	25.03.11	25.09.11	25.09.12	25.02.14	25.03.14
	उपलब्धि/माह में देरी	25.06.07	-	62 माह	54 माह	45 माह	45 माह	39 माह	26 माह	09 माह	08 माह
रबोध (खुली[4])	अनुसूचित तिथि		09.08.07	-	25.02.08	10.02.09	10.02.09	10.08.09	10.08.10	25.01.11	10.02.11
	उपलब्धि/माह में देरी	25.06.07	जून 2012 (59 माह)	-	81 माह	69 माह	69 माह	63 माह	51 माह	46 माह	45 माह
पिंडारा देवीपुर (मिश्रित[5])	अनुसूचित तिथि		-	02.11.08	02.07.09	02.05.10	02.05.10	02.11.10	02.11.11	02.04.12	02.05.12
	उपलब्धि/माह में देरी	02.08.06	-	72 माह	64 माह	54 माह	54 माह	48 माह	36 माह	31 माह	30 माह
लातेहार (खुली)	अनुसूचित तिथि		-	02.11.08	02.07.09	02.05.10	02.05.10	02.11.10	02.11.11	02.04.12	02.05.12
	उपलब्धि/माह में देरी	02.08.06	-	72 माह	64 माह	54 माह	54 माह	48 माह	36 माह	31 माह	30 माह

[1] आंशिक अन्वेषित एवं अन्नवेषित कोयला ब्लॉकों के लिए पुर्वेक्षण लाइसेंस के आवेदन के तीन माह के अवधि और विस्तृत अन्वेषण एवं जीआर की तैयारी के लिए 24 माह की अवधि को ध्यान में रखते हुए आवंटन की तिथि से जीआर बनाने हेतु माइलस्टोन 27 माह का है। पतरातु, पिंदरा- देवीपुर, राउता और बुढ़ाखाप अन्नवेषित या आंशिक अन्वेषित थे |

[2] जीआर की तिथि से खुली खान के संबंध में परिचालन एवं उत्पादन की अनुमति प्रदान करने के लिए माइलस्टोन क्रमश: 41 एवं 42 माह था और भूमिगत खान के संबंध में यह 53 एवं 54 माह था।

[3] भूमिगत परियोजना

[4] खुली परियोजना

[5] भूमिगत और खुली परियोजना

जागेश्वर एवं खास जागेश्वर (खुली)	अनुसूचित तिथि		26.05.08	-	26.01.09	02.11.09	02.11.09	26.05.10	26.05.11	26.10.11	11.11.11
	उपलब्धि/माह में देरी	11.04.08	जून 2012 (50 माह)	-	70 माह	60 माह	60 माह	54 माह	42 माह	37 माह	36 माह
सुगिया (खुली)	अनुसूचित तिथि		15.03.06	-	15.11.06	15.09.07	31.07.07	31.03.08	31.03.09	30.08.09	31.09.09
	उपलब्धि/माह में देरी	31.01.06	06.09.06 (6 माह)	-	04.09.08 (22 माह)	86 माह	02.02.09 (21 माह)	81 माह	69 माह	63 माह	62 माह
बुढ़ाखाप (खुली)	अनुसूचित तिथि		-	10.04.08	31.12.08	31.10.09	31.10.09	30.04.10	30.04.11	30.09.11	31.10.11
	उपलब्धि/माह में देरी	31.01.06	-	06.06.12 (50 माह)	71 माह	61 माह	61 माह	55 माह	43 माह	38 माह	33 माह
रउता (खुली)	अनुसूचित तिथि		-	31.03.08	31.12.08	31.10.09	31.10.09	30.04.10	30.04.11	30.09.11	31.10.11
	उपलब्धि/माह में देरी	30.01.06	-	80 माह	71 माह	61 माह	61 माह	55 माह	43 माह	38 माह	33 माह
कोल इंडिया लिमिटेड से हस्तांतरित कोयला ब्लॉक											
जगलदगा (खुली)	अनुसूचित तिथि		-	31.10.96	16.05.97	16.03.98	16.03.98	16.09.98	16.09.99	16.02.00	16.03.00
	उपलब्धि/माह में देरी	16.09.96	-	तैयार	20.10.97 (5 माह)	200 माह	28.05.08 (122 माह)	02.02.98	182 माह	177 माह	176 माह

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़े)

परिशिष्ट - 2.4

खनिज खानों के वैधानिक अनापत्तियों की स्थिति को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 2.14 में संदर्भित)

वैधानिक अनापत्तियाँ	अनुमोदन की तिथि[6]								
	बैंती बागदा	सलहन	ज्योतिपहाड़ी	सिरबोई	चंदुला-सिमलगोड़ा	महुँगाई-तुलबुला	मानासोती	चेलांगी[7]	सेमरा सलातुआ
खनन योजना	22.08.2002	-	21.03.2007	18.07.2000	-	24.08.1999	-	10.01.2011	-
खनन पट्टा का नवीकरण		-	-	-	17.03.2011 (सिमलगोड़ा) 09.01.2012 (चंदुला)	-	-	19.01.2011	-
वन अनापत्ति		-	आवश्यक नहीं चूँकि कोई वन भूमि शामिल नहीं था।	-	-	-	-	आवश्यक नहीं चूँकि कोई वन भूमि शामिल नहीं था।	10.06.1998
पर्यावरण अनापत्ति		-	-	-	-	-	-	-	-
एस.पी.सी.वी. से अनापत्ति प्रमाण पत्र		-	-	-	-	-	-	-	-

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़े)

[6] खानों के वैधानिक अनापत्तियों की प्राप्ति एवं खानों के विकास के लिये कोई माइलस्टोन निर्धारित नहीं थे।

[7] नया पट्टा 19.01.2011 को प्रदान किया गया।

परिशिष्ट - 2.5

31 मार्च 2014 को खनिज खानों के संबंध में खनन पट्टे और उनके नवीकरण को दर्शाती विवरणी

(कंडिका 2.15 में संदर्भित)

पट्टा क्षेत्र का नाम	जिला	खनिज	पट्टा क्षेत्र (एकड़ में)	पट्टा क्षेत्र के स्वीकृति/ नवीकरण की तिथि	खनिज पट्टा की अवधि (वर्ष में)	खनन पट्टा नवीकरण आवेदन हेतु दाखिल करने की तिथि	नवीकरण की तिथि (वर्ष में)	वर्तमान स्थिति
सेमरा सलातुआ	पलामू	चूना पत्थर	2578.28	03.04.1976	20	02.04.1995	20	अनवीकृत
बेंती बागदा	राँची	चूना पत्थर	334.87	05.05.1976	20	04.05.1995	20	अनवीकृत
सलहन	राँची	चूना पत्थर	257.03	05.05.1976	20	04.05.1995	20	अनवीकृत
ज्योतिपहाड़ी	पूर्वी सिंहभूम	कायनाइट	50.25	19.08.1984	20	14.08.2003	20	अनवीकृत
सिरबोई	पूर्वी सिंहभूम	कायनाइट	168.40	19.08.1984	20	14.08.2003	20	अनवीकृत
चंदुला-सिमलगोड़ा	साहेबगंज	पत्थर	172.80	17.03.2011 09.01.2012	10	-	-	स्वीकृत[8]
महुँगाई-तुलबुला	पलामू	ग्रेफाइट	552.15	14.10.1976	20	13.10.1995	20	अनवीकृत
मानासोती	पलामू	ग्रेफाइट	733.03	13.09.1979	20	21.08.1998	20	अनवीकृत
चेलांगी (नया पट्टा)	खूँटी	ग्रेनाइट	2.00	19.01.2011	20	-	-	स्वीकृत
कुल क्षेत्र			**4848.81**					

(स्रोत: कम्पनी के अभिलेखों से संकलित आँकड़े)

[8] सिमलगोड़ा (86.80 एकड़) और चंदुला (86 एकड़) के लिये पट्टा का नवीकरण क्रमश: 17.03.2011 एवं 09.01.2012 को प्रदान किया गया था।

परिशिष्ट-3.1

कंडिकायें/निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसका उत्तर अप्राप्त थे, का दर्शाती विवरणी

(कंडिका 3.7.1 में संदर्भित)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		ले.प.प्र. में कंडिकाओं की सं.	कंडिकाओं की सं. जिसका उत्तर अप्राप्त था	ले.प.प्र. में कंडिकाओं की सं.	कंडिकाओं की सं. जिसका उत्तर अप्राप्त था	ले.प.प्र. में कंडिकाओं की सं.	कंडिकाओं की सं. जिसका उत्तर अप्राप्त था	ले.प.प्र. में कंडिकाओं की सं.	कंडिकाओं की सं. जिसका उत्तर अप्राप्त था	ले.प.प्र. में कंडिकाओं की सं.	कंडिकाओं की सं. जिसका उत्तर अप्राप्त था
1.	ऊर्जा	4	4	6	6	2	2	3	3	4	4
2.	वन एवं पर्यावरण	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1
3.	गृह	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-
4.	खान एवं भूतत्व	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
5.	उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
6.	जल संसाधन, उद्योग, ऊर्जा, गृह, पर्यटन, वन एवं पर्यावरण, शहरी विकास, खान एवं भूतत्व	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	कुल	**5**	**5**	**7**	**7**	**4**	**4**	**6**	**6**	**6**	**6**

परिशिष्ट - 3.2

विभागावार लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) की विवरणी

(कंडिका 3.7.3 में संदर्भित)

क्र. सं.	विभाग का नाम	सा.क्षे.उ. की सं.	लम्बित नि.प्र. की सं.	लम्बित कंडिकाओं की सं.	जिस वर्ष से कंडिका लम्बित है
1.	ऊर्जा	2	345	1123	2005-06
2.	वन एवं पर्यावरण	1	27	103	2006-07
3.	खान एवं भूतत्व	1	4	18	2010-11
4.	पर्यटन	1	7	36	2007-08
5.	उद्योग	2	6	22	2008-09
6.	गृह	1	12	59	2006-07
7.	जल संसाधन	1	18	52	2006-07
8.	नगर विकास	1	2	12	2009-10
कुल		**10**	**421**	**1425**	

परिशिष्ट - 3.3

विभागावार प्रारूप कंडिकाओं की विवरणी जिसके उत्तर अप्राप्त थे

(कंडिका 3.7.3 में संदर्भित)

क्रम सं.	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिकाओं की सं.	निर्गत करने की अवधि
1.	ऊर्जा	3	मई से जुलाई 2014
2.	वन एवं पर्यावरण	1	जून 2014
3.	उद्योग	1	जून 2014
	कुल	**5**	